

राजव्यवस्था और शासन

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 टीके के रोलआउट को समर्थन देने के लिए संचार रणनीति जारी की

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल में भारत में कोविड-19 टीके के रोलआउट को समर्थन देने के लिए संचार रणनीति को जारी किया। इसका उद्देश्य डर को दूर करके और इसकी स्वीकार्यता को सुनिश्चित करके सटीक और पारदर्शी सूचना का प्रसार करना है।



संचार रणनीति के बारे में

- चार मुख्य क्षेत्र जोकि रणनीति के अंतर्गत हस्तक्षेप के भाग के रूप में सुलझाये जाएंगे, वे हैं
 - कोविड-19 टीके पर सूचना देना
 - टीके पर हिचक को सुलझाना
 - टीके पर उत्सुकता को बढ़ाना
 - कोविड उपयुक्त व्यवहार को सतत रूप से बनाये रखना
- रणनीति का उद्देश्य टीके के लिए किसी न पूरी की गई मांग अथवा लोगों के मध्य उत्सुकता द्वारा व्यक्त किसी संभावित निराशा को प्रबंधित और कम करना है। साथ ही यह टीके के प्रति हिचक को भी सुलझायेगी जोकि टीके की सुरक्षा, सामर्थ्य को लेकर डर की वजह से पैदा हुई हो, साथ ही किसी अन्य मिथक अथवा गलतफहमी को भी दूर करेगी।
- इसका लक्ष्य संभावित खतरों पर सूचना को उपलब्ध कराना भी है और लागू करने और रोलआउट करते समय किसी गैर निर्दिष्ट संकट को कम करना है।
- इसकी रणनीति का यह भी उद्देश्य है कि संचार में पारदर्शिता को लागू करके सभी लोगों के मध्य कोविड-19 टीके के प्रति ज्यादा आत्मविश्वास और विश्वास निर्मित करे। साथ ही यह किसी गलत सूचना और अफवाहों को भी रोके।

संचार रणनीति की प्रमुख विशेषताएं:

सामाजिक प्रभाव का प्रयोग

- इसकी रणनीति टीकाकरण की प्रक्रिया (कहां, कैसे, कौन, कब- तिथि और समय) को बताने के लिए विशेषज्ञों और आधिकारिक आवाजों से सामाजिक प्रभाव अथवा समर्थन के प्रयोग पर केंद्रित होगी।

- यह टीके की सुरक्षा और सामर्थ्य पर जोर देती है और टीकाकरण को चरणबद्ध तरीके से करने के निर्णय की व्याख्या करती है।

सामुदायिक आधारित प्लेटफार्मों को शामिल करना

- सरकार सामुदायिक लामबंद करने वालों और अग्रणी कार्यकर्ताओं को शामिल करेगी जिससे विभिन्न स्तरों पर समुदाय के साथ संलग्न हुआ जा सके। इसके लिए समुदायिक सलाहों, धार्मिक नेताओं और अन्य सामुदायिक आधारित प्लेटफार्मों का सहारा लिया जाएगा जिससे कोविड-19 टीके के प्रति विश्वास निर्मित किया जा सके और ज्यादा आत्मविश्वास पैदा किया जा सके।

राष्ट्रीय मीडिया तीव्र रिस्पांस सेल (NMRRRC)

- मंत्रालय का उद्देश्य अपने अंतर्गत एक राष्ट्रीय मीडिया तीव्र रिस्पांस सेल (NMRRRC) की स्थापना का है जिससे वास्तविक समय में प्रतियुत्तर देने के लिए मीडिया निगरानी और सामाजिक सुनवाई के द्वारा तैयारी को सुनिश्चित किया जा सके।
- यह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजीटल मीडिया की सघन निगरानी के द्वारा मीडिया और सार्वजनिक चर्चा का भी खुलासा करेगी।

टीकाकरण से होने वाले खराब प्रभाव

- टीकाकरण के बाद किसी खराब प्रभाव होने की स्थिति (AEFI) में, रणनीति लामबंद करने वालों और स्वास्थ्य कार्यबल को संकट की स्थिति के प्रबंधन के लिए समुदाय को शांत रहने के लिए कहने पर जोर देगी जबकि इस बीच में उपयुक्त निदान के लिए इंतजार किया जाएगा और स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ आक्रमक व्यवहार को रोका जाएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- स्वास्थ्य मामले

स्रोत- PIB

भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स भागीदारी (INSACOG)

खबर में क्यों है?

- भारत सरकार ने हाल में भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स भागीदारी समूह (INSACOG) की शुरुआत की है।



भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स भागीदारी (INSACOG) के बारे में

- इसकी स्थापना SARS-CoV-2 में जीनोमिक रूपों की निगरानी के लिए किया गया है जोकि नियमित तौर पर होगा। इसके लिए बहु प्रयोगशाला नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा।
- यह भागीदारी SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 VUI 202012/01) के नए रूप की स्थिति के बारे में देश में जानकारी हासिल करेगा।
- इस समूह का समन्वय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW), ICMR और CSIR के साथ बायोतकनीक विभाग द्वारा किया जाएगा।

संरचना

- इसमें 10 प्रयोगशालाएं हैं (NIBMG कोलकाता, ILS भुवनेश्वर, NIV पूणे, CCS पूणे, CCMB हैदराबाद, CDFD हैदराबाद, InSTEM बंगलुरु, NIMHANS बंगलुरु, IGIB दिल्ली और NCDC दिल्ली)।

डाटाबेस के रखरखाव के लिए नोडल इकाई

- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व के नये रूपों के सभी सैंपलों के डाटाबेस के रखरखाव के लिए नोडल इकाई का कार्य करेगा।
- आंकड़ों का विश्लेषण, व्याख्या और साझेदारी महामारी विज्ञान के रूप में सभी राज्यों के साथ जांच, संपर्क ट्रेसिंग और नियोजन रिस्पांस रणनीतियों के लिए किया जाएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

मेरा गांव, मेरा गौरव कार्यक्रम

खबर में क्यों है?

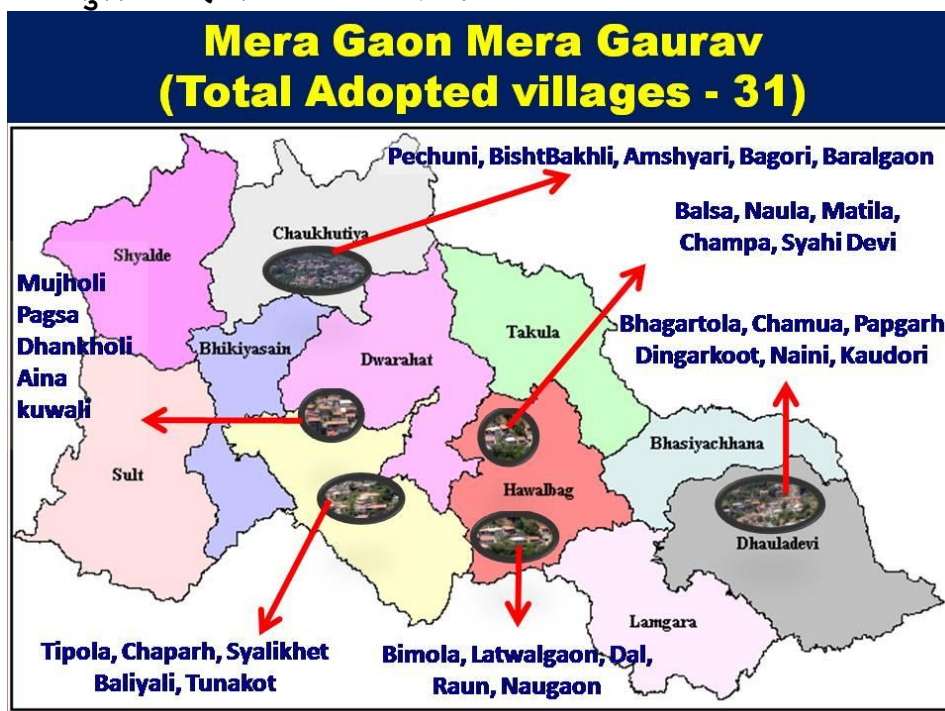
- हाल में, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने मेरा गांव, मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत इबरामपुर, वेलिंग और पार्रा गांवों में स्वच्छता अभियान को चलाया।



मेरा गांव, मेरा गौरव के बारे में

- यह भारतीय कृषीय अनुसंधान परिषद (ICAR) की राष्ट्रीय नवाचार पहल है और कई गांवों में प्रचालित है।

- यह खेत आधारित मिशन है जो किसान के दरवाजे पर ही ज्ञान का अनुवाद कर रहा है जिससे संपूर्ण रूप में उसकी खेत उन्मुख समस्याओं को सुलझाया जा सके जिससे जीवनयापन सुरक्षा को हासिल किया जा सके।



इस योजना के उद्देश्य हैं:

- गांवों को अपना कर नियमित आधार पर जरूरी सूचना, ज्ञान और सलाहों को किसानों को उपलब्ध कराना।
- किसानों के साथ वैज्ञानिकों के प्रत्यक्ष इंटरफेस को प्रोत्साहित करना जिससे प्रयोगशाला से भूमि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
- यह सुनिश्चित करना कि किसान सबसे अच्छी खेती प्रथाओं से लाभ उठाये जिसके लिए गांवों को अपना कर नियमित तौर पर जरूरी सूचना, ज्ञान और सलाहों को उपलब्ध कराया जाए।
- संगठनों और उनके कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में किसानों के मध्य जागरूकता पैदा की जाए। साथ ही खेती क्षेत्र से संबंधित सरकारी नीतियों के बारे में भी जानकारी दी जाए।
- इसने नवीनतम तकनीक के साथ किसानों को लाभ पहुँचाया है और हस्तक्षेप के रूप में नवीनतम उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया है।
- इस योजना के अंतर्गत, वैज्ञानिक अपनी सुविधा के अनुसार गांवों का चुनाव करेंगे और चुने गये गांवों के साथ संपर्क में रहेंगे और एक समयावधि के दौरान तकनीकी और अन्य संबंधित पहलुओं पर किसानों को सूचना उपलब्ध कराएंगे।
- प्रत्येक संस्थान/ विश्वविद्यालय में चार वैज्ञानिकों का एक समूह अपने कार्यस्थल से 50-100 किमी. की त्रिज्या में गांवों को गोद लेंगे।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- PIB

ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल

खबर में क्यों है?

- विदेश राज्य मंत्री ने हाल में ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और मोबाइल एप की शुरुआत की है।



ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल के बारे में

- इसका लक्ष्य पूरी दुनिया में भारतीय प्रवासी समुदाय को जोड़ना है।
- यह पोर्टल भारत के प्रवासियों के बीच में एक गत्यात्मक संचार प्लेटफार्म के रूप में कार्य करेगा।
- इस पोर्टल का निर्माण भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों के पंजीकरण को सक्षम बनाने के लिए किया गया है अर्थात अप्रवासी भारतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति और OCI।
- यह पोर्टल भारतीय सरकार को विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय से जुड़ने में मदद देगा।
- यह NRIs, OCIs और PIOs समुदाय को बढ़ावा देगा जिसके लिए वह कई नई और वर्तमान सरकारी योजनाओं से जोड़ेगा जो कि उनके हित के विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्रदान करेगा।
- यह वास्तविक समय आधार पर समुदाय के साथ संचार को सुगम बनाएगा और आपातकालीन सतर्कता और सलाहों को भी जारी करने की क्षमता प्रदान करेगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

FSSAI ने खाद्यान्नों में ट्रांस वसा स्तरों की सीमा को कम किया

खबर में क्यों है?

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हाल में तेलों और वसाओं में ट्रांस वसीय अम्लों (TFA) की मात्रा की सीमा निर्धारित कर दी।



नई सीमाएं क्या हैं?

- इसने तेलों और वसाओं में ट्रांस वसीय अम्लों (TFA) की मात्रा को 2021 तक 3% और 2022 तक 2% निर्धारित कर दिया। जबकि वर्तमान की अनुज्ञेय सीमा 5% है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और सीमा) विनियमन में संशोधन किया गया है।

पूर्व की सीमा

- पहली बार 2011 में तेलों और वसाओं में 10% की ट्रांस वसीय अम्लों की सीमा को निर्धारित करने के लिए एक नियम पारित किया गया, जिसे 2015 में और घटाकर 5% कर दिया गया।
- पुनर्निर्धारित विनियमन खाने वाले रिफाइनड तेलों, वनस्पति (आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल), मार्गेराइन, बेकरी के सामान और पकाने के अन्य माध्यम जैसे वनस्पति फैट स्प्रेड और मिश्रित फैट स्प्रेड्स पर लागू होता है।

विनियमन की आवश्यकता

- FSSAI का नियम महामारी के समय में आया है जहां गैर-संक्रामक रोगों का बोझ बढ़ गया है।
- मधुमेह के साथ हृदय रोग कोविड-19 रोगियों के लिए घातक साबित हो रहे हैं।

संबंधित सूचना

ट्रांस वसा को समाप्त करने के लिए WHO की पहल

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक समग्र योजना जिसे 'REPLACE' कहते हैं कि शुरुआत की है जिससे 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से कृत्रिम ट्रांस वसाओं का औद्योगिक उत्पादन समाप्त हो जाए।
- संयुक्त राष्ट्र निकाय ने खाद्यान्नों से ट्रांस वसाओं को समाप्त करने के लिए उद्योग के लिए चरण दर चरण दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- दिशा-निर्देश जिन्हें **REPLACE** कहा जा रहा है, में छह कार्रवाईयां हैं, जिनमें शामिल हैं-
 - a. ट्रांस वसाओं के आहार स्रोतों की समीक्षा
 - b. स्वास्थ्यकारी वसाओं से विस्थापन को प्रोत्साहन
 - c. विनियमन ढांचे की स्थापना करना
 - d. भोजन में ट्रांस वसाओं की मात्रा का आकलन और निगरानी
 - e. जागरूकता पैदा करना और विनियमन लागू करना
 - f. नीतियों और विनियमनों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करना।

भारत और ट्रांस वसा

- सरकार का लक्ष्य भारत को 2022 तक पूरी तरह से ट्रांस वसा से मुक्त करना है, जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित किये गए लक्ष्य से एक वर्ष पूर्व है।

ट्रांस वसाओं के बारे में

- ये असंतृप्त वसा के एक रूप हैं जिनका कई नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों से संबंध है।
- बड़े स्तर पर इन वसाओं का कृत्रिम रूप से उत्पादन किया जाता है लेकिन इनकी अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से भी पाई जाती है।

ट्रांस वसाओं के प्रकार

- प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस वसाएं कुछ जानवरों के पेट में पाए जाते हैं और इन जानवरों से बनाए गये खाद्यान्नों (उदाहरण के लिए दूध और मांस उत्पाद) में इन वसाओं की अल्प मात्राएं हो सकती हैं।

- कृत्रिम ट्रांस वसा का निर्माण हाइड्रोजनीकरण के समय होता है जो द्रव वनस्पति तेलों को अर्ध ठोस आंशिक हाइड्रोजनीकृत तेल में परिवर्तित कर देता है।
- क्योंकि इनका प्रयोग करना आसान है, उत्पादन करना किफायती है और लंबे समय तक ठीक रहते हैं, और खाद्यान्न को वांछित स्वाद और बनावट प्रदान करते हैं, इनका प्रयोग आज भी वृहद स्तर पर किया जा रहा है इसके बावजूद कि इनके कुप्रभाव जाने-माने हैं।

ट्रांस वसाओं के हानिकारक प्रभाव

- ट्रांस वसाएं हृदयघातों और हृदय रोग से होने वाली मौतों को बढ़ाने के जोखिम से जुड़ी हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, लगभग 5.4 लाख मौतें प्रत्येक वर्ष वैश्विक रूप से औद्योगिक उत्पादित ट्रांस वसीय अम्लों के खाने से होती हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- स्वास्थ्य

स्रोत- द हिंदू

विद्यालय बस्ता नीति, 2020

खबर में क्यों है?

- शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा जारी की गई नई विद्यालय बस्ता नीति, 2020 का अनुपालन करने के लिए विद्यालयों से कहा गया है।

परिपत्र के बारे में

- परिपत्र के अनुसार, विद्यालय के अध्यापकों को छात्रों को यह बताना होगा कि वे किसी विशेष दिन विद्यालय में कौन सी किताबें और कापियां लाएं और उन्हें अक्सर उनके बस्तों की भी जांच करनी होगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे गैर जरूरी चीजों को नहीं ला रहे हैं।



- नीति के अनुसार विद्यालय के बस्ते का वजन निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए
 - a. कक्षा 1 से 2 के लिए 1.6 किग्रा. से 2.2 किग्रा.
 - b. कक्षा 3, 4 और 5 के लिए 1.7 से 2.5 किग्रा.
 - c. कक्षा 6 और 7 के लिए 2 से 3 किग्रा.
 - d. कक्षा 8 के लिए 2.5 से 4 किग्रा.
 - e. कक्षा 9 और 10 के लिए 2.5 से 4.5 किग्रा.
 - f. कक्षा 11 और 12 के लिए 3.5 से 5 किग्रा.

- प्रत्येक तीन महीने में अध्यापक को स्कूली बस्ते के वजन को जांचने की जिम्मेदारी वहन करनी होगी। इसके लिए पूरी कक्षा के लिए दिन का चुनाव किया जाएगा और ज्यादा वजन के बस्ते के बारे में माता-पिता को सूचना देनी होगी।
- स्कूली बस्ते का वजन कम करने के लिए, विद्यालय प्रबंधन को विद्यालय में ही सभी छात्रों को पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य जल उपलब्ध कराना होगा जिससे उन्हें घरों से जल की बोतलों को लाने की आवश्यकता न रह जाए।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- शिक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

बांबे उच्च न्यायालय ने महिला श्रेणी से ट्रांस महिला को चुनाव लड़ने की इजाजत दी

खबर में क्यों है?

- बांबे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने विपरीतलिंगी को महिला श्रेणी में गांव के पंचायत चुनाव लड़ने की इजाजत दी है। उसका कहना है कि ऐसे व्यक्तियों को स्वयं द्वारा तय की गई लैंगिक पहचान को रखने का अधिकार है।

न्यायालय का दृष्टिकोण

- न्यायालय ने अपने आदेश में यह नोट किया कि केंद्र सरकार ने विपरीतलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून, 2019 को लागू किया है और एक विपरीतलिंगी व्यक्ति को अपने द्वारा तय की गई लैंगिक पहचान को अपनाने का अधिकार दिया है।

संबंधित सूचना

विपरीतलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून, 2019

- यह विपरीतलिंगी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में व्याख्यायित करता है जिसका लिंग जन्म के समय दिये गये लिंग से नहीं मिलता है। इसमें विपरीत-पुरुष और विपरीत-महिला, अंतरलिंग विभिन्नताओं के साथ व्यक्ति, गैर-द्विसंख्यिक लैंगिक व्यक्ति, और किन्नर और हिजड़ा जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति।
- अंतरलिंग विभिन्नताओं की व्याख्या यह है कि ऐसे व्यक्ति जो जन्म के समय अपनी प्राथमिक लैंगिक विशेषताओं, बाह्य गुप्तांगों, गुणसूत्रों अथवा हार्मोनों में पुरुष अथवा महिला शरीर के मानक स्तरों से अलग विभिन्नता दर्शाते हैं।
- विधेयक में एक प्रावधान है जिसके अनुसार विपरीतलिंगी व्यक्ति को अपने माता-पिता और करीबी परिवारिक सदस्यों के साथ आवास का अधिकार है।
- यह राष्ट्रीय विपरीतलिंगी व्यक्ति परिषद (NCT) की स्थापना का आह्वान करता है।



राष्ट्रीय विपरीतलिंगी व्यक्ति परिषद के बारे में

- सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने हाल में राष्ट्रीय विपरीतलिंगी व्यक्ति परिषद की स्थापना की है।
- इस परिषद की स्थापना विपरीतलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून, 2019 के अंतर्गत की गई है।
- इस परिषद में स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक मामले, शिक्षा, श्रम, ग्रामीण विकास के मंत्रालय से संयुक्त सचिव स्तर के सदस्य होंगे।
- मंत्रालयों के अतिरिक्त, परिषद में मानवाधिकार आयोगों, नीति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग से भी सदस्य होंगे।
- समुदाय से नामांकित किये गए पांच सदस्य भी परिषद के हिस्से होंगे।

परिषद के कार्य

- a. विपरीतलिंगी व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, विधानों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को तय करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देना।
- b. सभी विभागों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना।
- c. विपरीतलिंगी व्यक्तियों की शिकायतों को सुलझाना।
- d. विपरीतलिंगियों की समानता और पूर्ण भागीदारी को हासिल करने के लिए बनाये गए कार्यक्रमों और नीतियों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना।
- e. केंद्र द्वारा निर्धारित किये गए किसी अन्य कार्य को करना।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सामाजिक मामले

स्रोत- द हिंदू

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (RKA)

खबर में क्यों है?

- हाल में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (RKA) ने गौ विज्ञान पर उपलब्ध ज्ञान के बारे में अध्ययन सामग्री बनाने के लिए एक खास पहल की शुरुआत की है। वह “कामधेनु गौ-विज्ञान प्रचार-प्रसार परीक्षा” का आयोजन करेगा।



परीक्षा की प्रमुख खास बातें

- यह इस प्रकार की पहली परीक्षा है जिसका आयोजन वार्षिक तौर पर किया जाएगा।
- प्राथमिक, माध्यमिक और विद्यालय स्तरों के छात्र और सामान्य जन बिना किसी शुल्क को अदा किये हुए “कामधेनु गौ-विज्ञान प्रचार-प्रसार परीक्षा” में भाग ले सकते हैं।

महत्व

- यह युवा छात्रों और प्रत्येक अन्य नागरिक के मध्य स्वदेशी गायों के बारे में जन जागृति पैदा करने में मदद देगा।
- यह परीक्षा गायों के बारे में सभी भारतीयों के अंदर एक उत्सुकता पैदा करेगी और दूध देना बंद कर देने के बाद भी एक गाय के अंदर क्या अंजान संभावनाएं और व्यावसायिक अवसर हैं इसके बारे में उन्हें जागरूक करेगा।

संबंधित सूचना

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में

- यह एक उच्च शक्ति सम्पन्न स्थाई सर्वोच्च परामर्शदात्री निकाय है जिसके पास केंद्र सरकार को सहायता देने का शासनादेश है कि गायों की देशी नस्लों के उपयुक्त कार्यक्रमों के विकास, संरक्षण, सतत विकास और अनुवांशिक उन्नयन को कैसे किया जाए।
- यह मत्स्यन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- यह वर्तमान कानूनों, नीतियों की समीक्षा करेगा। साथ ही उन्नत उत्पादन और उत्पादकता के लिए गौ धन के अनुकूलतम आर्थिक उपयोग के लिए उपायों को देगा, जिससे डेयरी किसानों के लिए ऊंची कृषि आय हो और बेहतर जीवन स्तर हो।
- इसका लक्ष्य किसानों के दरवाजे पर उन्नत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं का संप्रेषण और अनुप्रयोग है, जिसके लिए डेयरी सहकारी समितियों, किसान उत्पादक कंपनियों और डेयरी उद्योग साथ ही अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय किया जाएगा।
- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अविभाज्य हिस्से के रूप में कार्य करेगा।

संबंधित सूचना

पशुधन जनगणना

- 2012 की पशुधन जनगणना के अनुसार, भारत में गौवंश की जनसंख्या 300 मिलियन है, जिसमें से 191 मिलियन मवेशी (गाएँ) और 108.7 मिलियन भैंसें हैं।
- मवेशी और भैंस अनुवांशिक संसाधन का निर्माण मवेशियों की 43 प्रजातियों और भैंसों की 16 प्रजातियों से हुआ है।
- गौवंश जनसंख्या में, 216 मिलियन मादा और 84 मिलियन नर हैं, पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार 5.2 मिलियन मवेशियों को छुट्टा छोड़ दिया गया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स

लंबवत और क्षैतिज आरक्षण

खबर में क्यों है?

- हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने लंबवत और क्षैतिज आरक्षणों की परस्पर क्रिया पर कानून की स्थिति को स्पष्ट किया।
- सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का निर्णय राज्य में कांस्टेबलों के पदों को भरने की चुनाव प्रक्रिया में लगाये जाने वाले आरक्षण के विभिन्न वर्गों के तरीके से उत्पन्न मामलों से संबंधित था।



लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण क्या है?

लंबवत आरक्षण

- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को लंबवत आरक्षण कहते हैं।
- यह कानून के अंतर्गत बताये गए समूहों के प्रत्येक के लिए अलग से लागू होता है।

क्षैतिज आरक्षण

- इसका आशय महिलाओं, वेटेरनों, विपरीतलिंगी समुदाय और अक्षमताओं के साथ व्यक्तियों जैसे लोगों की लाभकर्ताओं की अन्य श्रेणियों के लिए उपलब्ध समान अवसर से है। यह लंबवत श्रेणियों के आरपार जाता है।

कैसे दोनों श्रेणियों के कोटा को एक साथ लागू किया जाता है?

- क्षैतिज कोटा को प्रत्येक लंबवत श्रेणी में अलग से लागू किया जाता है ना कि एक समान रूप से।
- उदाहरण के लिए, यदि महिलाओं का 50% क्षैतिज कोटा है तो तो प्रत्येक लंबवत कोटा श्रेणी में आधे चुने हुए अभ्यर्थियों को महिला ही होना होगा- अर्थात आधे चुने गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों

को महिला होना अनिवार्य है, गैर आरक्षित वर्ग में आधे अथवा सामान्य श्रेणी में आधे को महिला होना अनिवार्य है।

- दोनों प्रकार के आरक्षणों का अंतर्ग्रथन कई प्रकार के सवाल पैदा करता है कि कैसे कोई निश्चित समूह की पहचान की जाए।
- उदाहरण के लिए, क्या अनुसूचित जाति की महिला को महिला अथवा अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाएगा?
- क्योंकि कोटा को प्रतिशत में निश्चित करते हैं, कोटा का क्या प्रतिशत प्रत्येक को दिया जाए?

सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में

- न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ निर्णय दिया, और कहा कि यदि कोई व्यक्ति लंबवत-क्षैतिज आरक्षित श्रेणी के बीच का है और उसने बिना लंबवत आरक्षण को लिये हुए अर्हता प्राप्त करने लायक अंक हासिल कर लिये हैं, तो उस व्यक्ति को बिना लंबवत आरक्षण के अर्हता हासिल करने वाला माना जाएगा, और उसे सामान्य श्रेणी में क्षैतिज कोटा से बाहर नहीं किया जा सकता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

ईश्वर का नाम प्रयोग करके वस्तुएं बेचना गैरकानूनी

खबर में क्यों है?

- बांबे उच्च न्यायालय ने हाल में उन वस्तुओं की बिक्री को रोक दिया है जिनमें टेलीविजन विज्ञापन के द्वारा चमत्कारिक अथवा अलौकिक शक्ति होने का दावा किया जाता है।

पृष्ठभूमि

- एक याचिका दायर की गई थी जिसमें टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों को रोकने के लिए निर्देश देने का निवेदन किया गया। ये विज्ञापन हनुमान चालीसा यंत्र जैसी वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहित करते हैं।



- याचिककर्ता ने 2015 में ऐसे विज्ञापनों को देखा जिसमें बाबा मंगलनाथ द्वारा तैयार किये गए हनुमान चालीसा यंत्र में विशेष, चमत्कारिक और अलौकिक गुण होने का दावा किया गया था। इस बाबा ने दावा किया कि उसने सिद्धि हासिल कर ली है और उसे भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त है।
- याचिका में यह कहा गया कि गलत प्रचार था कि यह यंत्र बाबा मंगलदास द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने सिद्धि (कुछ भी करने की क्षमता) हासिल कर ली थी।

न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन

- न्यायालय ने कहा कि किसी ईश्वर का नाम प्रयोग करना और दावा करना कि इसमें अलौकिक शक्तियां हैं महाराष्ट्र निरोधक और मानव बलि और गैरमानवीय, गलत और अघोरी प्रथाओं और काला जादू उन्मूलन कानून, 2013 के तहत गैरकानूनी और गलत है।
- न्यायालय का यह भी कहना था कि काला जादू कानून में उद्धरण किये गए उद्देश्य मुख्यतया शिक्षा के द्वारा ही हासिल किये जा सकते हैं।
- काला जादू कानून का अनुच्छेद 3, न केवल काला जादू, गलत प्रथाओं को करने के लिए निषेध करती हैं बल्कि ऐसी प्रथाओं और जादू के प्रोत्साहन और प्रचार को भी रोकता है।
- कानून का अनुच्छेद 3(2) कहता है कि इस तरह के प्रचार को बढ़ावा देना भी अपराध है।

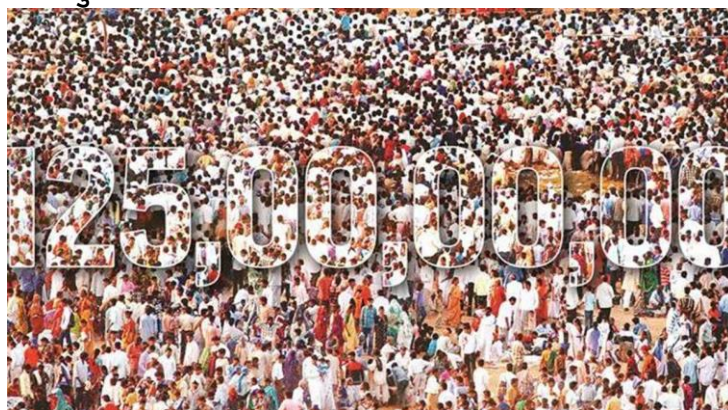
विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- राजनीतिशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

NFHS-5 परिणामों के अध्ययन पर पैनल

खबर में क्यों है?

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 से खराब परिणामों की जांच के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। साथ ही यह समूह कुपोषण, रक्तअल्पता और C- अनुच्छेद से संबंधित संसूचकों को सुधारने के लिए कार्यकार्यात्मक और नीति हस्तक्षेप की अनुशंसा भी करेगा।



- इस समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव प्रीती पटेल द्वारा की जा रही है और इसमें चिकित्सा और पोषण से विशेषज्ञ शामिल हैं।
- इसमें कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्य कार्यक्रम अधिकारी भी शामिल हैं।

संबंधित सूचना

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के बारे में

- दिसंबर 2020 में, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) 2019-20 के प्रथम चरण के आंकड़ों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।

NFHS-5 सर्वेक्षण के बारे में

- NFHS-5 ने 2014-19 के बीच के आंकड़े लिये हैं और इनकी विषयवस्तु NFHS-4 (2015-16) के ही समान है जो समय पर तुलना की अनुमति देती है और इससे एक अलग रास्ता भी दिखाती है।

- यह 30 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर नजर रखने के लिए संसूचक उपलब्ध कराती है जिसे देश 2030 तक हासिल करना चाहता है।
- लेकिन, NFHS-5 में कुछ नए विषय जैसे कि स्कूल पूर्व शिक्षा, अक्षमता, शौचालय सुविधा तक पहुँच, मृत्यु पंजीकरण, मासिक धर्म के दौरान नहाने की प्रथा और गर्भपात की विधियाँ और कारण शामिल हैं।
- 2019 में, पहली बार, NFHS-5 ने इंटरनेट का कभी भी प्रयोग करने वाले महिलाओं और पुरुषों के प्रतिशत पर विवरण मांगा है।

रिपोर्ट के मुख्य परिणाम

- पूरे देश में कई राज्य हैं जिन्होंने स्वच्छता में सुधार और ईंधन और पेयजल की बेहतर पहुँच के बावजूद बाल कुपोषण की गिरती स्थिति को रिकार्ड किया है और पीछे चले हैं।
- नवीनतम आंकड़े राज्य में महामारी के पूर्व स्वास्थ्य की स्थिति को बताते हैं।
- कई राज्यों ने या तो अल्प सुधार देखा है अथवा बाल कुपोषण मानदंडों के चार मुख्य मीट्रिक्स (5 वर्ष से कम आयुवर्ग) में सतत गिरावट देखी है।
- ये चार प्रमुख मीट्रिक्स हैं
 - a. बाल अल्पविकास
 - b. बाल निर्बलता
 - c. बाल अल्पवजन का साझा
 - d. बाल मृत्यु दर
- इन मीट्रिक्स से आंकड़े कई वैश्विक सूचकांकों में भी प्रयोग किये जाते हैं जैसे कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक।

बाल अल्पविकास

- सबसे आश्चर्यजनक गिरावट बाल अल्पविकास के क्षेत्र में है, जोकि असाध्य अल्पपोषण को दर्शाता है और बच्चों के प्रतिशत को बताता है जिनका अपनी उम्र के लिहाज से कम वजन है।
- अल्पविकास किसी अन्य कारक की अपेक्षा, बच्चों के संज्ञानात्मक और भौतिक विकास पर दीर्घावधि खराब प्रभाव डालने वाला है।
- तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बाल अल्पविकास के मामले बढ़ रहे हैं।
- बाल अल्पविकास के बढ़ते हुए मामले काफी समस्या देने वाले हैं क्योंकि सामान्य तौर पर अल्पविकास के मामले बढ़ते नहीं हैं क्योंकि सभी चीजें जो बाल विकास को प्रभावित करती हैं सुधार की ओर उन्मुख होती हैं क्योंकि स्थिर लोकतंत्र और अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ते हैं।

बाल निर्बलता

- यह तीव्र अल्पपोषण को परिलक्षित करता है और बच्चों की लंबाई के अनुसार उनके अल्प वजन को इंगित करता है।
- भारत में सदैव से ही बाल निर्बलता का ऊँचा स्तर रहा है।
- इसको कम करने की बजाय, तेलंगाना, केरल, बिहार, असम और जम्मू व कश्मीर ने इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी है जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में स्थिति जस की तस है।

बाल अल्पवजन की साझेदारी

- अल्पवजन बच्चों के समानुपात में बड़े राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरल ने लगातार वृद्धि देखी है।

बाल मृत्यु दर

- शिशु मृत्यु दर (एक वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मृत्युओं की संख्या) और 5 वर्ष के अंदर की मृत्यु दर आंकड़े सबसे ज्यादा स्थिर हैं।
- NFHS-3 (2005-06) और NFHS-4 के बीच में, मृत्यु दर घटाने में तरक्की हुई थी, लेकिन NFHS-5 और NFHS-4 लगभग पांच वर्षों की दूरी पर है लेकिन फिर भी कई राज्यों में काफी कम तरक्की हुई है।
- महाराष्ट्र में, 5 वर्ष के अंदर की मृत्यु दर NFHS-4 में मूल रूप से समान है और बिहार में पांच वर्षों में यह मात्र 3% ही कम हुई है।
- 6% से ज्यादा बाल मृत्यु दर को बाल कुपोषण से समझाया जा सकता है, जोकि एक केंद्रीय समस्या है और जिसको सुलझाने की जरूरत है।

पहली बार: इंटरनेट प्रयोग में अंतराल

- एक शहरी-ग्रामीण अंतराल साथ ही लैंगिक विभाजन भी है जोकि कई राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में इंटरनेट के प्रयोग के सापेक्ष है।
- औसत रूप से, ग्रामीण भारत में 10 महिलाओं में से 3 और शहरी भारत में 10 में से 4 ने कभी इंटरनेट का प्रयोग किया है।
- सामान्य आंकड़े: औसत रूप से 42.6% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का प्रयोग किया है जबकि इसके विपरीत पुरुषों में 62.16% ने इसका प्रयोग किया है।
- शहरी भारत में: औसत रूप से 56.81% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का प्रयोग किया है जबकि इसकी तुलना में 73.76% पुरुषों ने इंटरनेट का प्रयोग किया है।
- ग्रामीण भारत में: ग्रामीण भारत में मात्र 33.94% महिलाओं ने कभी इंटरनेट का प्रयोग किया है, इसके विपरीत 55.6% पुरुषों ने इंटरनेट का प्रयोग किया है।
- महिलाओं का प्रतिशत, जिन्होंने कभी इंटरनेट का प्रयोग किया है, ग्रामीण भारत में तेजी से गिरा है।

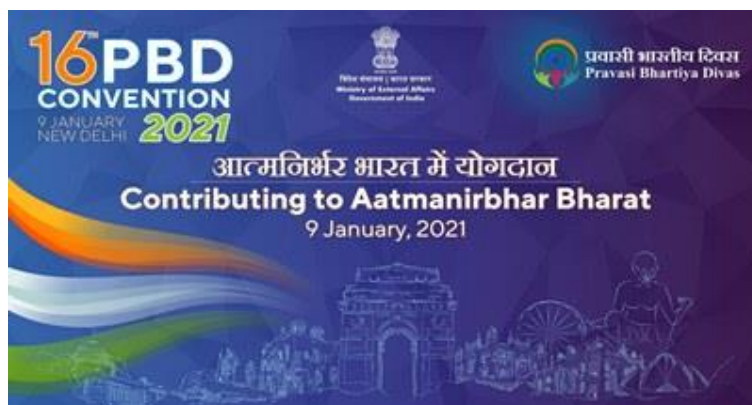
विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप (स्वास्थ्य)

स्रोत- द हिंदू

16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन

खबर में क्यों है?

- हाल में, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल रूप से 9 जनवरी 2021 को किया गया।



मुख्य अतिथि

- सूरीनाम के राष्ट्रपति, श्री चंद्रिका परसाद संतोखी मुख्य अतिथि थे।
- सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पूर्वी तट पर एक छोटा सा देश है।

थीम

- 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम “आत्मनिर्भर भारत को योगदान” थी।

प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) सम्मेलन के बारे में

- यह विदेश मामले मंत्रालय का फ्लैगशिप आयोजन है और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ जुड़ने व विचार-विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।
- इसका उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीयों को मान्यता देना है जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है।

महत्व

- इसे प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी, 1915 को ही दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे।

संबंधित सूचना

प्रवासी भारतीय सम्मान (PBSA)

- इसे प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर कुछ चुने हुए भारतीय प्रवासी सदस्यों को उनके भारत और बाहर दोनों ही जगह, विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदानों और उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है।

युवा प्रवासी भारतीय दिवस (PBD)

- इसे भी थीम “भारत और भारतीय प्रवासियों से युवा कामयाब लोगों को साथ लाना” पर वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा। और इसकी एंकरिंग युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय द्वारा की जाएगी।
- इस समारोह के विशेष अतिथि न्यूजीलैंड की समुदाय एवं स्वैच्छिक क्षेत्र की मंत्री मिस प्रियंका राधाकृष्णन है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- राजनीतिशास्त्र

स्रोत- PIB

खादी प्राकृतिक पेंट

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 12 जनवरी को एक नवाचार नए पेंट को बाजार में उतारा है जिसे खादी एवं ग्राम्य उद्योग आयोग ने विकसित किया है।
- यह अपने प्रकार का पहला है, जिसे पर्यावरण हितैषी, गैर विषाक्त पेंट माना जा रहा है जिसमें फंफूदी प्रतिरोधी और बैक्टीरिया प्रतिरोधी गुण हैं।

खादी प्राकृतिक पेंट के बारे में

- इसकी संकल्पना खादी एवं ग्राम्य उद्योग आयोग (KVIC) ने की है।

पेंट की विशेषताएं

- इस पेंट को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणीकृत किया गया है।
- खादी प्राकृतिक पेंट दो रूपों में उपलब्ध है- डिस्टेंम्पर पेंट और प्लास्टिक इम्प्रेशन पेंट।

मुख्य घटक

- गाय का गोबर इसका प्रमुख घटक है, यह पेंट किफायती और गंधरहित है और इसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणीकृत किया गया है।
- यह पेंट भारी धातुओं जैसे लेड, मरकरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम और अन्य से मुक्त है।



महत्व

- खादी प्राकृतिक पेंट का उत्पादन प्रधानमंत्री की दृष्टि किसानों की आय बढ़ाने के अनुसार है।
- यह तकनीक गाय के गोबर के उपभोग को बढ़ाएगी जोकि पर्यावरण हितैषी उत्पादों के लिए कच्चा माल है और इससे किसानों और गौशालाओं के लिए अतिरिक्त राजस्व की गारंटी भी होगी।
- इसे एक अनुमान के अनुसार रु. 30,000 (लगभग) की अतिरिक्त आय प्रति वर्ष प्रति जानवर किसानों/गौशालाओं को होगी।
- यह स्थानीय विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन होगा और तकनीक हस्तांतरण के द्वारा सतत स्थानीय रोजगार को सृजित करेगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

अंतरिक्ष शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ISRO 100 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं को अपनाएगा

खबर में क्यों है?

- अंतरिक्ष विभाग (DOS) और अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग ने हाल में घोषणा की कि ISRO पूरे देश में 100 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं को अपनाएगा जिसके द्वारा वह स्कूली छात्रों के लिए नवाचार से संबंधित STEM, अंतरिक्ष शिक्षा एवं अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा।



अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं के बारे में

- यह अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग के द्वारा एक पहल है जिसका लक्ष्य पूरे भारत में स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं (ATLs) की स्थापना करना है।

उद्देश्य

- युवा दिमागों में उत्सुकता, सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता पैदा करना; कौशल की बुनियाद डालना जैसे कि डिजाइन मानसिकता, गणनात्मक विचारशीलता, तदात्मकता वाली पढ़ाई, भौतिक गणना इत्यादि।

प्रमुख विशेषताएं

- यह एक कार्यस्थल है जहां युवा दिमाग अपने हाथों से करने के तरीके के द्वारा अपने विचारों को रच सकते हैं और नवाचार कौशलों को सीख सकते हैं।
- युवा बच्चों को STEM(विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग एवं गणित) की संकल्पनाओं को समझने के लिए टूलों और औजारों के साथ कार्य करने का मौका हासिल होगा।
- इसमें 'अपने आप करें' वाली शैक्षिक और सीखने वाली किटें शामिल होंगी। साथ ही विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ओपेन सोर्स माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड्स, सेंसर और 3डी प्रिंटर एवं कम्प्यूटर पर यंत्र होंगे।

वित्तीय सहायता

- अटल नवाचार मिशन प्रत्येक स्कूल को रु. 20 लाख का अनुदान प्रदान करेगा जिसमें एक बार स्थापना करने के लिए रु. 10 लाख की लागत और प्रत्येक ATL को 5 वर्षों के अधिकतम अवधि के लिए रु. 10 लाख के प्रचालन खर्च शामिल होंगे।

आर्हता

- सरकार, स्थानीय निकायों अथवा निजी न्यासों/समितियों द्वारा प्रबंधित स्कूल (न्यूनतम कक्षा 6-9) अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं (ATLs) की स्थापना करेंगे।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

सेना के लिए व्यभिचार का कानून रहना चाहिए: सरकार

खबर में क्यों है?

- हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय (MoD) द्वारा दायर की गई एक याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें 2018 की संविधान खंडपीठ वाले निर्णय जिसमें व्यभिचार को गैर

आपराधिक घोषित कर दिया गया था, के दायरे से सैन्य बलों के कर्मचारियों को बाहर रखने को कहा गया था।

ADULTERY CAN TAKE YOU TO COURT, NOT TO JAIL

What's struck down: Section 497 of Indian Penal code that said: "Whoever has sexual intercourse with a person who is... the wife of another man, without the consent... of that man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, is guilty of the offence of adultery"

The problem: It treated woman as victim of the offence and as 'property' of her husband. It was not an offence if a man had sexual intercourse with a woman after getting her husband's consent

After the judgment: Adultery can be a ground for divorce but it's no more a criminal offence attracting up to 5 years' jail term

Govt's problem: Centre in its affidavit before the apex court had said that it would be against the sanctity of marriage to dilute the offence of adultery

Keep in mind: Though adultery per se is no longer a crime, if any aggrieved spouse commits suicide because of partner's adultery, it could be treated as an abetment to suicide—a crime



“ Making adultery a crime is retrograde and would mean punishing unhappy people... any law which dents individual dignity and equity of women in a civilised society invites the wrath of the Constitution **”**

—CJI Dipak Misra

Ostensibly, society has **two sets of standards of morality** for judging sexual behaviour. One set for its female members and another for males... A society which perceives women as pure and an embodiment of virtue has no qualms of subjecting them to virulent attack: to rape, honour killings, sex-determination and infanticide

—Justice D Y Chandrachud

भारत में व्यभिचार कानून के बारे में

- भारतीय दंड संहिता **अनुच्छेद 497** एक अनुच्छेद था जो व्यभिचार से संबंधित है।
- इस कानून के अंतर्गत, एक महिला को व्यभिचार के अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।
- केवल एक आदमी जिसने किसी अन्य की पत्नी के साथ स्वेच्छा से यौन संबंध बनाए हो, हालांकि उस व्यक्ति की बिना इजाजत के, वह भारत में इस अपराध के दंडित किया जा सकता है।
- यदि कोई व्यभिचार का जीवन बिता रहा है तो उसका जीवनसाथी तलाक मांग सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए कारण

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को गैर संवैधानिक बताया क्योंकि यह कानून पति को मालिक के रूप में देखता है।
- व्यभिचार का अपराध महिला को जंगम संपत्ति की तरह मानता है, जिससे उनके सम्मान को ठेस लगती है।
- न्यायालय ने संवैधानिक प्रावधानों की कसौटी पर अनुच्छेद 497 का परीक्षण किया जोकि समानता के अधिकार से संबंधित है और निरंकुशता और भेदभाव के खिलाफ गारंटी देता है।

नये प्रावधान

- व्यभिचार अपने व्यभिचारी जीवनसाथी के साथ तलाक चाहने के लिए पीड़ित साथी के लिए एक आधार रह सकता है।

- यदि किसी एक साथी ने आत्महत्या की है क्योंकि उसका जीवनसाथी व्यभिचारी स्वभाव का है, तो दोषी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आपराधिक अपराध की कार्यवाही हो सकती है।

छूट चाहने के लिए सरकार द्वारा दिये गए कारण:

- सैन्य कर्मियों के दिमाग में हमेशा गलत कार्य में लिप्त परिवार के लिए एक चिंता रहेगी जोकि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने परिवारों से दूर कार्य कर रहे हैं।
- थल, नौ और वायु सेना के कर्मी एक अलग वर्ग हैं क्योंकि वे विशेष विधानों, सेना, नौसेना और वायुसेना कानूनों के द्वारा प्रशासित होते हैं।
- व्यभिचार सहन करने योग्य कार्य नहीं है और यह तीनों कानूनों के अंतर्गत अनुशासन का उल्लंघन है।
- तीनों कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 33 के द्वारा संरक्षित किया गया है, जिसने सरकार को सैन्य बलों के कर्मियों के मूलभूत अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार दिया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सामाजिक मामले

स्रोत- द हिंदू

SAATHEE पोर्टल

खबर में क्यों है?

- ऊर्जा सामर्थ्य ब्यूरो (BEE) ने हाल में 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों (NECA) के दौरान SAATHEE पोर्टल और एयर कम्प्रेशर्स और अल्ट्रा हाई डेफीनिशन (UHD) टीवी के लिए स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग कार्यक्रम की शुरुआत की।

SATHEE पोर्टल के बारे में

- SAATHEE का अर्थ है स्टेटवाइज एक्शंस ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफीसिएंसी।
- यह राज्य स्तरीय गतिविधियों के लिए राज्य नामांकित एजेंसी के लिए एक पोर्टल है।
- यह राज्य स्तर पर विभिन्न ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के क्रियान्वयन की प्रगति की वास्तविक समय निगरानी को सुगम बनाएगा।

एयर कम्प्रेशर्स एंड अल्ट्रा हाई डेफीनिशन (UHD) टीवी के लिए स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग कार्यक्रम के बारे में

- इसे स्वैच्छिक आधार पर शुरू किया गया है और ऊर्जा उपभोग मानक 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होंगे।
- यह पहल 2030 तक UHD टीवी के लिए 79.75 अरब इकाई और एयर कम्प्रेशर्स के लिए 8.41 अरब इकाई बिजली की बचत करेगी।

संबंधित सूचना

स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग कार्यक्रम के बारे में

- इसे ऊर्जा सामर्थ्य ब्यूरो द्वारा 2006 में शुरू किया गया था।

उद्देश्य

- उपभोक्ता को ऊर्जा बचत के बारे में जानकारीपूर्ण चुनाव करने का अधिकार देना और इस तरह से प्रासंगिक बाजार में बेचे गए उत्पाद की किफायती संभावना के बारे में बताना।

लक्ष्य

- यह योजना उच्च ऊर्जा एंड प्रयोग उपकरणों और यंत्रों पर ऊर्जा प्रदर्शन लेबलों को प्रदर्शित करने को लक्षित करती है और न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानकों को निर्धारित करती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान

खबर में क्यों है?

- कोरोना वायरस को 16 जनवरी को लोगों के मध्य उतारने की तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों कोविड 10 स्थिति और देश में टीकाकरण रोलआउट के बारे में चर्चा की है।



नोट: स्वास्थ्य राज्य का विषय है।

- भारतीय औषधि नियंत्रक द्वारा दो टीकों इंडिया-एस्ट्रा-जेनेका- ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड जिसे भारत में कोविशील्ड भी कहा जाता है, और जिसे सीरम संस्थान द्वारा निर्मित किया जा रहा है एवं बायोटेक की कोवैक्सीन के सीमित आपातकालीन स्वीकृति दिये जाने के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के मध्य यह पहली बैठक थी।
- ये दोनों स्वीकृत टीके दुनिया की किसी भी अन्य की अपेक्षा ज्यादा किफायती टीके हैं और देश की जरूरतों के अनुसार ही विकसित की जा रही हैं। पहले चरण में 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कर्मियों के टीकाकरण की लागत को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। टीकाकरण को अंतः मांसपेशी मार्ग द्वारा किया जाएगा।

महत्वपूर्ण अंतःदृष्टि

टीका बनने में इतना ज्यादा समय क्यों लगा?

- ऐसा इसलिए है क्योंकि टीके को बनाने में सामान्यतया ज्यादा अनुसंधान और परीक्षण होते हैं। प्रयोगशाला में सफलता के बावजूद, सभी टीकों को विभिन्न प्रकार के लोगों पर परीक्षण किये जाने की जरूरत होती है जिससे उसकी सुरक्षा और सामर्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। अभी तक दो टीकों-

भारत-एस्ट्रा-जेनेका-ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवाक्सिन को सबसे ज्यादा मुफीद माना गया है- जिसके परिणाम अगले कुछ महीनों में प्राप्त होने की आशा है।

टीकों को कौन स्वीकृति देता है?

- **DGCI** (भारतीय औषधि नियंत्रक), **ICMR** (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) और **MoHFW** यह निर्धारित करने में भूमिका निभाएंगे कि कौन सा टीका भारत में बिकेगा। यह विनिर्माणकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गये दस्तावेजों पर आधारित होगा। वे अपने निर्णय को सार्वजनिक कर भी सकते हैं और नहीं भी।

टीकाकरण में किसको प्राथमिकता मिलेगी?

- स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन कर्मी, वृद्ध नागरिक और वे जिन्हें असाध्य रोग हैं, को प्राथमिकता दी जाएगी। यह अभ्यास 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए किया जाएगा।

क्या सभी भारतीयों के लिए टीका होगा?

- देश में 1.32 अरब लोगों के साथ और यह देखते हुए कि विश्व की सभी अग्रणी टीकों के लिए दो खुराकों की जरूरत है, पूरी जनसंख्या को टीका लगाने के लिए महीनों लग जाएंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (**MoHFW**) ने इंगित किया है कि उसे आशा है कि अगले वर्ष जुलाई तक 250 मिलियन लोगों का टीकाकरण हो जाएगा।

क्या एक रोगी को यह प्रमाणपत्र अथवा दस्तावेज दिया जाएगा कि उसका टीकाकरण किया गया है?

- यह योजनाएं हैं कि कोविड 10 टीकाकरण पर डिजिटल तरीके से निगाह रखी जाएगी जिससे नकलीपन को रोका जाए और लोगों को दूसरी खुराक के बारे में याद दिलाया जाए। लाभकर्ता की प्रक्रिया की सूची को तैयार करने की तैयारी जोर-शोर से चल रही है।

कौन टीकाकरण करेगा, सरकार अथवा निजी अस्पताल?

- सरकार ने भारतीय सीरम संस्थान से कोविशील्ड खरीदने की योजना की घोषणा की है। अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं है कि क्या सरकार टीके पर अपना एकाधिकार रखेगी।

क्या टीकाकरण मुफ्त में है?

- पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन कर्मियों के लिए टीकाकरण की लागत को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

आगे के चरणों का निर्णय अभी लिया जाना बाकी है

क्या सभी के लिए टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा?

- अंतोगत्वा सभी के लिए टीका उपलब्ध होगा, लेकिन अभी तक सरकार ने इस बारे में किसी योजना की घोषणा नहीं की है कि कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य होगा। लेकिन, कंपनियां, आवास समितियां अथवा यात्रा प्रचालक इसे अनिवार्य कर सकते हैं।

टीकाकरण अभियान कैसे किया जाएगा?

- यह देखते हुए कि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, देश चुनाव करवाने के अनुभव का सहारा लेकर टीका अभियान चलाएगा।
- गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग से भी निवेदन किया है वे लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची के आंकड़ों को साझा करें जिससे प्राथमिकता समूहों के लोगों की पहचान की जा सके।
- केंद्र सरकार ने राज्यों के मध्य वितरण रणनीति का निर्णय ले लिया है जो भौगोलिक प्राथमिकताकरण अथवा उन क्षेत्रों में जहां संक्रमण के मामले काफी ज्यादा हैं, पर आधारित है। इसका अर्थ है महाराष्ट्र और केरल अन्य राज्यों के ऊपर रखे जाएंगे।

विषय: सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- सामाजिक मुद्दे (स्वास्थ्य)

स्रोत- RSTV, इंडिया टूडे एवं द इंडियन एक्सप्रेस

कोविड-19 टीकाकरण: 2 दिनों में 447 ने दुष्प्रभावों की रिपोर्ट की

खबरों में क्यों है?

- हाल में, भारत ने कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने की कोशिश में दुनिया के सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य कार्यक्रम के पहले चरण में 30 मिलियन फ्रंटलाइन कर्मियों को टीका लगाने का है।

टीकाकरण की खास बातें

- कोविड-19 टीकाकरण छह राज्यों में शुरू किया गया है- अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर और तमिलनाडु।
- कोविड-19 टीकाकरण के दौरान, गंभीर **AEFI (टीकाकरण के बाद दुष्प्रभावों की घटनाएं)** के लक्षण फ्रंटलाइन कर्मियों के मध्य रिपोर्ट किये गये जिनका टीकाकरण दिल्ली में किया गया था।
- टीकाकरण अभियान के पहले दिन **तेलंगाना** ने गंभीर घटनाओं के 11 मामले और पश्चिम बंगाल ने समान दिन इस तरह के 14 मामलों को रिपोर्ट किया।
- अब तक जितने लोगों का टीकाकरण किया गया है, 447 लोगों ने दर्द, हल्की सूजन, हल्का बुखार अथवा जी मिचलाने जैसी प्रतिक्रियाओं की रिपोर्ट की है, जिनमें से सिर्फ तीन लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी है।

टीकाकरण के बाद दुष्प्रभाव घटनाएं क्या हैं (AEFI)?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार कोई अनहोनी चिकित्सकीय घटना जोकि टीकाकरण के बाद होती है और इसका संबंध जरूरी नहीं कि टीके के प्रयोग की वजह से ही हो, को **टीकाकरण के बाद दुष्प्रभाव घटनाएं** कहते हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सामाजिक मुद्दे

स्रोत- द हिंदू

व्हाट्सएप की नई निजता नीति

खबरों में क्यों है?

- व्हाट्सएप ने हाल में अपनी निजता नीति को अपडेट किया है, और प्रयोगकर्ताओं के पास 8 फरवरी तक का वक्त नए नियमों और स्थितियों को स्वीकार करने का है।



WhatsApp Protects and Secures Your Personal Messages



WhatsApp cannot see your personal messages or hear your calls and neither can Facebook.



WhatsApp does not keep logs of who everyone is messaging or calling.



WhatsApp cannot see your shared location and neither can Facebook.



WhatsApp does not share your contacts with Facebook.



WhatsApp groups remain private.



You can set your messages to disappear.



You can download your data.

व्हाट्सएप की नई निजता नीति की खास बातें?

- नई नीति कहती है कि प्रयोगकर्ता का डाटा किस तरह से प्रभावित होता है जब प्लेटफॉर्म पर व्यवसाय के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, और यह फेसबुक के साथ एकीकरण पर ज्यादा विवरण उपलब्ध कराता है। फेसबुक व्हाट्सएप की पितृ कंपनी है।

क्या व्हाट्सएप फेसबुक के साथ आपके संदेशों को साझा करेगा?

- नहीं। निजता नीति उस तरह से परिवर्तित नहीं होती है जिस तरह से व्हाट्सएप व्यक्तिगत चैट को लेता है।
- इस अपडेट से फेसबुक के साथ व्हाट्सएप की डाटा साझा करने की प्रथा परिवर्तित नहीं होगी और इस पर प्रभाव नहीं डालती है कि लोग अपने मित्रों अथवा परिवार के साथ कैसे निजी रूप से बातचीत करते हैं।

व्हाट्सएप कौन सा डाटा फेसबुक के साथ साझा करेगा?

- यह तथ्य है कि फेसबुक के साथ डाटा का विनियम अभी भी चल रहा है।
- जबकि प्रयोगकर्ता यूरोपीय संघ में फेसबुक के साथ डाटा साझा करने से बाहर निकल सकते हैं, बाकी दुनिया को इस तरह का चुनाव का अधिकार नहीं है।
- व्हाट्सएप निम्नलिखित सूचना को फेसबुक और अपनी अन्य कंपनियों के साथ साझा करता है:
 - खाता पंजीकरण सूचना (फोन नंबर)
 - लेनदेन डाटा (भारत में व्हाट्सएप के पास अब पेमेंट्स हैं)
 - सेवा से संबंधित सूचना
 - यह सूचना की दूसरों के साथ आप कैसे बातचीत करते हैं (बिजीनेस सहित)

e. मोबाइल डिवाइस सूचना और IP एड्रेस।

बिजीनेस के साथ डाटा साझा करने पर नीति क्या कहती है?

- नई नीति इस बात की व्याख्या करती है कि कैसे बिजीनेस डाटा हासिल करते हैं जब एक प्रयोगकर्ता उनके साथ बातचीत करता है प्लेटफॉर्म पर: व्हाट्सएप पर बिजीनेस के साथ साझा की गई विषयवस्तु उस बिजीनेस में कई व्यक्तियों को दिखाई देगी।

क्या व्हाट्सएप सुरक्षित और निजी है?

- व्हाट्सएप के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर सभी चैट एंड-टू-एंड इंक्रीप्टेड हैं। कंपनी के अनुसार, भेजने वाले और पाने वाले के अतिरिक्त कोई भी आपके निजी संदेशों को पढ़ नहीं सकता है और ना ही आपकी कॉल के सुन सकता है।

क्या व्हाट्सएप मेरे साझा स्थान को देख सकता है ?

- नहीं, व्हाट्सएप आपके साझा स्थान को नहीं देख सकता है, केवल जिसके साथ आपने साझा किया है वही इसे देख सकता है। चैट में साझा किये गये स्थान भी एंड-टू-एंड इंक्रीप्टेड हैं।

संबंधित सूचना

निजता और भारत का संदर्भ

- **पुट्टास्वामी निर्णय** का कहना है कि निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अंतर्गत** मूलभूत संवैधानिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का विचार है **(रामजेठमलानी बनाम भारतीय संघ)** कि “यह महत्वपूर्ण है कि मानवों को स्वतंत्रता के स्थान उपलब्ध कराए जाएं जोकि सार्वजनिक जांचों से मुक्त हों जब तक कि वे गैरकानूनी तरीकों से कार्य नहीं कर रहे हैं।”
- निजता बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाये रखने को सुनिश्चित करती है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब हमें निगरानी में रखा जाता है तो हम राज्य की कार्यवाही के डर से अपने की कोशिश शुरू करेंगे।

भारत में निजता से संबंधित कौन सी चिंताएं हैं?

- यदि निजता न हो तो ऐसा लगेगा कि आपके नाम से लगातार वारंट कटा हुआ है।
- यदि आपको महसूस होता है कि आप लगातार निगरानी में हैं तो आप कभी भी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाएंगे जो आपके मूलभूत अधिकार हैं।
- डाटा तक गैर विनियमित पहुँच से विरोध को कुचला जा सकता है और सेंसरशिप लग सकती है।
- पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता इत्यादि, को एक अदृश्य निगरानी के कारागार में डाला जा सकता है।
- वे लोग जो ऐसी जीवनशैली जी रहे हैं जिसे समाज के कुछ तबकों द्वारा वर्जित कर्म माना जाता है तो उन्हें **समलैंगिक** के रूप में कलंकित अथवा लक्षित किया जा सकता है।
- निजी विवरण जैसे यात्रा विवरण, खरीददारी का इतिहास, वित्तीय विवरण इत्यादि का प्रयोग ऑनलाइन ग्रेनुलर प्रोफाइल बनाने में किया जाता है जिनका प्रयोग किसी समय विशेष रूप से बनाई गई नकली समाचारों को फैलाने में किया जा सकता है।

- इसने नकली समाचार की घातकता को बढ़ा दिया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

भारत को किस तरह की कृषि-खाद्य नीति की आवश्यकता है?

खबर में क्यों है?

- हाल में, ICRIER में कृषि के लिए इंसोसिस चेयर प्रोफेसर और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ पैनल के सदस्य अशोक गुलाटी ने धरना दे रहे किसानों के साथ तीन विवादित कृषि कानूनों की चर्चा की।
- उनके अनुसार, भारत को लघु अवधि और दीर्घावधि चुनौतियों दोनों को ही सुलझाने के लिए एक अनुकूलतम कृषि खाद्य नीति के निर्माण की जरूरत है।

इस तरह की नीति में कम से कम चार कसौटियां होनी चाहिए

ये चार कसौटियां हैं:

- ✓ इसे अपनी बड़ी जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन, खाना और फाइबर उत्पन्न करना होगा।
 - इस बारे में, सबसे उपयुक्त कदम कृषि में अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना और इसका प्रयोगशालाओं से खेतों और सिंचाई सुविधाओं में प्रसार करना।
 - ऐसा विश्वास किया जाता है कि विकासशील देशों को कृषि अनुसंधान एवं विकास और विस्तार में अपने कृषि सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1 प्रतिशत निवेश करना चाहिए जबकि भारत इसका आधा निवेश करता है।
- ✓ इसे ऐसे करना चाहिए कि यह न केवल पर्यावरण का संरक्षण करे- मृदा, जल, वायु और जैवविविधता- बल्कि वैश्विक प्रतियोगिता के साथ उच्च उत्पादन को भी हासिल करे।
 - इसको करने के लिए उच्च सब्सिडी वाली निवेश मूल्य नीति (बिजली, जल, खादें) और धान, गेहूँ और गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य/FRP को बदलकर जल, मृदा और वायु गुणवत्ता को बचाने से संबंधित ज्यादा आय समर्थन नीतियों को अपनाना चाहिए।
- ✓ इसे खेत से थाली तक बाधारहित खाद्य गतिशीलता को सक्षम बनाना चाहिए, जिसमें विपणन लागतों को निम्न रखने, आपूर्ति कड़ियों में खाद्य हानियों को बचाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित और ताजा खाद्य उपलब्ध कराने की जरूरत है।
 - यह क्षेत्र दशकों से सुधार के लिए चिल्ला रहा है, विशेष रूप से कृषि विपणन में सामर्थ्य लाने और लेनदेन लागतों को कम करने के बारे में।
- ✓ इसे उपभोक्ता का हितैषी होना चाहिए और उन्हें वहनीय मूल्यों पर सुरक्षित और पोषणीय भोजन प्राप्त होना चाहिए।
 - खाद्य का सार्वजनिक वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा, जोकि चावल और गेहूँ पर निर्भर है, और वह भी खरीदने, भंडार करने और वितरित करने की लागतों के ऊपर 90 प्रतिशत सब्सिडी के साथ गुलाटी के अनुसार, ज्यादा मदद नहीं कर रहा है।

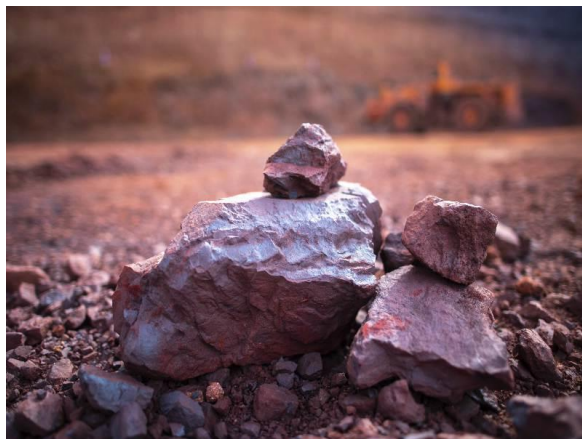
विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सरकारी नीति

स्रोत- द हिंदू

लौह अयस्क नीति 2021

खबर में क्यों है?

- रेलवे मंत्रालय ने नई “लौह अयस्क नीति 2021” जारी की है जिसमें लौह एवं इस्पात उद्योग को मदद देने के लिए लौह अयस्क के परिवहन और रैकों के आवंटन की नीति दी गई है। नई नीति 10 फरवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगी।



लौह अयस्क नीति 2021 के बारे में

- इस नीति का लक्ष्य ग्राहकों की वर्तमान की जरूरतों के हिसाब से मिलान करना है और उन्हें आश्वस्त करना है कि भारतीय रेलवे पूरी तरह से लौह अयस्क ग्राहकों के परिवहन की संपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- यह नीति घरेलू और वैश्विक स्तर पर प्रतियोगी चुनौतियों का सामना करने के लिए इस्पात उद्योग को संपूर्ण लॉजिस्टिक समर्थन उपलब्ध कराएगी।
- नई नीति प्रावधान रैक आवंटन प्रणाली मॉड्यूल में रेलवे सूचना प्रणालीयों (CRIS) के लिए केंद्र द्वारा अद्यतन किये जाएंगे।

नई नीति की महत्वपूर्ण खास बातें हैं:



- CBT/गैर- CBT ग्राहकों में ग्राहक की प्रोफाइल पर आधारित वर्तमान श्रेणीकरण को अब से समाप्त किया जा रहा है।
- पुराने और नये संयंत्र को समान रूप से देखा जाएगा जहां तक रैकों के आवंटन/लदान का संबंध है।

- लौह अयस्क की गति की प्राथमिकता का श्रेणीकरण को अब रेलवे अवसंरचना की उपलब्धता पर आधारित कर दिया गया है जिसे लदान/उतरान और विभिन्न प्रकार की साइडिंग्स के बीच में गति की प्रकृति ग्राहक के लिए विकसित किया गया था जिसका उद्देश्य रेल द्वारा अधिकतम लौह अयस्क गति को देखना था।
- ग्राहक की प्राथमिकता पसंद प्रणाली (रेक आवंटन योजना) द्वारा स्वतः उत्पन्न की जाएगी जोकि ग्राहक की प्रोफाइल पर आधारित होगी (विनिर्माणकर्ता का नाम, भेजने वाले का नाम, पाने वाले का नाम, साइडिंग/PFT नाम और कोड) जिसे संबंधित क्षेत्र द्वारा प्रणाली में डाला जाएगा।
- घरेलू विनिर्माण गतिविधि के लिए लौह अयस्क परियात की गति को सबसे उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

संबंधित सूचना

माल समानता नीति (FEP), 1952 के बारे में

- भारत की सरकार ने इसे 1952 में पूरे देश में उद्योगों की समान वृद्धि को सुगम बनाने के लिए अपनाया था।
- इसका अर्थ है भारत में कहीं भी एक फैक्ट्री को स्थापित किया जा सकता है, और केंद्र सरकार खनिजों के परिवहन को सब्सिडी प्रदान करेगी।
- इस नीति का लक्ष्य लंबी दूरी के माल परिवहन को सब्सिडी प्रदान करके समान औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना था।
- यह नीति केवल कुछ वस्तुओं पर ही लागू होती थी जैसे कि लोहा, इस्पात, सीमेंट और अन्य वस्तुओं जो औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए जरूरी मानी जाती है।
- इस नीति में कपास जैसे कच्चे माल नहीं शामिल थे।
- नीति को लागू करने के पीछे दृष्टि और तर्क पूरे देश में समान औद्योगिक वृद्धि को सुगम बनाना था।

अवगुण

- इसने आधिक्य संसाधन वाले राज्य जैसे बिहार, ओडिशा को औद्योगिक विकास से वंचित कर दिया और अंतोगत्वा इसे 1993 में समाप्त कर दिया गया, जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ।

नोट:

- लौह अयस्क रेलवे के परियात का दूसरी सबसे महत्वपूर्ण धारा है। यह इस्पात के लिए भी सही है और कोयला पहले स्थान पर है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सरकारी नीति

स्रोत- द हिंदू

मध्य प्रदेश में 'जल उत्सव'

खबर में क्यों है?

- मध्य प्रदेश के अन्नूपुर जिले के दामहेदी गांव ने हाल में अपने परिवारों में नल जल के कनेक्शनों का स्वागत करने के लिए 'जल उत्सव' मनाया।



जल जीवन मिशन के बारे में

- यह केंद्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित कर रहा है।
- जल जीवन मिशन का गठन उस समय किया गया जब इसमें चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) का विलय और पुनर्संरचना कर दी गई। यह मिशन प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यकारी परिवार नल कनेक्शन (FHTC) उपलब्ध कराएगा अर्थात, 2024 तक हर घर नल से जल (HGNSJ)।

उद्देश्य

- यह 2024 तक सभी ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को नल जल आपूर्ति (हर घर जल) उपलब्ध कराएगा।
- यह 2024 तक कार्यकारी परिवार नल कनेक्शनों (FHTC) के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति दिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की आपूर्ति करने की संकल्पना करता है।
- बजट 2020 में जल जीवन मिशन को रु. 3.6 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था।

ज्यादा जोर वाले क्षेत्र

- मिशन का जोर स्थानीय स्तर पर जल के एकीकृत मांग एवं आपूर्ति पक्ष का प्रबंधन करने पर है।
- वर्षाजल संचय, भूमिगत जल पुनर्भरण और पुनर्प्रयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे जरूरी तत्वों के रूप में स्रोत सततता उपायों के लिए स्थानीय अवसंरचना का सृजन करना। ये कार्य अन्य सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ संमिलन में किये जाएंगे।
- जल जीवन मिशन विभिन्न जल संरक्षण प्रयासों जैसे बिंदु पुनर्भरण, छोटे सिंचाई टैंकों की सफाई, कृषि के लिए गंदे जल का प्रयोग और स्रोत सततता पर आधारित होने जा रहा है।
- यह मिशन जल पर सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और मिशन के प्रमुख घटकों के रूप में सघन सूचना, शिक्षा और संचार शामिल हैं।
- भारतीय संविधान के 73वें संशोधन ने पेयजल के विषय को 11वीं अनुसूची में डाल दिया है।

वित्तीयन का तरीका

वित्तीय साझेदारी होगी

- a. केंद्र और राज्य के बीच में 90:10
 - b. हिमालियाई और उत्तर-पूर्व के राज्य के मध्य, 50:50
 - c. अन्य राज्यों के लिए और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए 100%।
- जल जीवन मिशन पूरे देश में सतत जल आपूर्ति प्रबंधन के अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए अन्य केंद्रीय और राज्य सरकारी योजनाओं में शामिल होगी।

संस्थागत प्रबंध:

1. केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM)
2. राज्य स्तर पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM)
3. जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM)
4. ग्राम्य स्तर पर ग्राम जल स्वच्छता समिति (VWSC)

ग्राम कार्य योजना (VAP):

- प्रत्येक ग्राम एक ग्राम कार्य योजना (VAP) तैयार करेगा जिसके तीन घटक होंगे:
 - i. जल स्रोत एवं उसका रखरखाव
 - ii. जल आपूर्ति
 - iii. गंदा जल (घरेलू अपशिष्ट जल) प्रबंधन।

मिशन की जरूरत और महत्व:

- भारत की जनसंख्या कुल विश्व की जनसंख्या की 16% है, लेकिन उसके पास केवल 4% ताजाजल संसाधन हैं।
- पीने योग्य जल उपलब्ध को लेकर सबसे बड़ी चुनौतियां भूमिगत स्तर का घटना, अतिदोहन और जल गुणवत्ता का क्षरण, मौसम परिवर्तन इत्यादि हैं।
- यह देश में जल संरक्षण की तुरंत जरूरत है क्योंकि भूमिगत स्तर की मात्रा तेजी से घट रही है।
- जल जीवन मिशन स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग और आपूर्ति प्रबंधन पर जोर देगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- PIB

बजट सत्र के दौरान प्रश्न प्रहर फिर से शुरू होगा

खबर में क्यों है?

- प्रश्न प्रहर जिसे मानसून सत्र के दौरान सरकार ने स्थगित कर दिया था, फिर से एक बार चालू किया जाएगा जब संसद की जनवरी 29, 2021 को बजट सत्र के लिए बैठक शुरू होगी।



पृष्ठभूमि

- मानसून सत्र 2020 के दौरान, लोकसभा और राज्यसभा के सचिवों ने अधिसूचित किया था कि संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रश्न प्रहर नहीं होगा, जिसे सितंबर 14- अक्टूबर 1 के बीच में कोविड-19 को देखते हुए संक्षिप्त कर दिया है, और दोनों सदनों में शून्य प्रहर सीमित होगा।

प्रश्न प्रहर क्या है, और इसका महत्व क्या है?

- प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्न प्रहर के लिए आवंटित होता है। लेकिन, 2014 में प्रश्न प्रहर को राज्यसभा में 11 बजे दिन से 12 बजे दोपहर तक कर दिया गया था।
- इसका उल्लेख संसद की प्रक्रिया के नियमों में किया गया है।
- इस समय के दौरान, सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री सामान्यतया उत्तर देते हैं।

पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार

तारांकित प्रश्न

- इसे तारक चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है।
- इसके लिए मौखिक प्रश्न की जरूरत होती है, और इसलिए संपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।
- इन प्रश्नों की सूची हरे रंग में प्रकाशित होती है।

2. गैर तारांकित प्रश्न

- इसके लिए एक लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, और इसलिए, संपूरक प्रश्न नहीं हो सकते हैं।
- इन प्रश्नों की सूची सफेद रंग में प्रकाशित होती है।

छोटी नोटिस वाले प्रश्न

- सार्वजनिक महत्व के और जरूरी मामलों को इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत विचार किया जाता है।
- इन्हें दस दिनों से कम की नोटिस देकर पूछा जा सकता है।
- इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है।
- इन प्रश्नों की सूची का प्रकाशन हल्के गुलाबी रंग में किया जाता है।
- मंत्रियों के अतिरिक्त, प्रश्नों को व्यक्तिगत सदस्यों से भी पूछा जा सकता है।

निजी सदस्यों से प्रश्न

- ये प्रश्न प्रक्रिया के नियमों और लोकसभा में कार्यवाही के संचालन के नियम 40 के अंतर्गत उल्लेखित किये गये हैं।
- कोई भी प्रश्न निजी सदस्य को संबोधित किया जा सकता है यदि प्रश्न की विषयवस्तु किसी विधेयक, प्रस्ताव से संबंधित हो, जिसके लिए वह सदस्य जिम्मेदार है।
- इन प्रश्नों की सूची पीले रंग में प्रकाशित की जाती है।

कितनी जल्दी प्रश्न प्रहर होते हैं?

- दोनों सदनों में प्रश्न प्रहर सत्र के सभी दिनों में होता है। लेकिन दो दिन ऐसे हैं जब इसका अपवाद होता है।
- उस दिन प्रश्न प्रहर नहीं होता है जब राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों से संसद सदस्यों को संबोधित करते हैं।
- राष्ट्रपति का भाषण नई लोकसभा की शुरुआत में होता है और नये संसद वर्ष के पहले दिन पर।
- जिस दिन वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है, उस दिन भी प्रश्न प्रहर नहीं होता है।

शून्य प्रहर के बारे में

- यह एक भारतीय संसदीय नवाचार है लेकिन इसका उल्लेख संसदीय नियमों की किताब में नहीं किया गया है।
- इसके अंतर्गत, संसद के सदस्य बिना पूर्व नोटिस के मामलों को उठा सकते हैं।
- शून्य प्रहर प्रश्न प्रहर के तुरंत बाद शुरू होता है और दिन का एजेंडा लेने तक चलता रहता है (अर्थात्, सदन की नियमित कार्यवाही तक)।
- अन्य शब्दों में, प्रश्न प्रहर और एजेंडा के बीच में समय अंतराल को शून्य प्रहर कहते हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- राजनीतिशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

विनियामक अनुपालन पोर्टल

खबर में क्यों है?

- हाल में, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है, ने विनियामक अनुपालन पोर्टल की शुरुआत की है।



विनियामक अनुपालन पोर्टल के बारे में

उद्देश्य

- पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों, उद्योगों और सरकार के मध्य एक सेतु का कार्य करना है जिससे बोझवाले अनुपालनों को न्यूनतम किया जा सके।
- यह सभी केंद्रीय और राज्य स्तर अनुपालनों के लिए अपनी तरह के पहले केंद्रीय ऑनलाइन कोष के रूप में भी कार्य करेगा।
- सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग और राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र अपने अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत कानूनों/विनियमन/नियमों की जांच करेंगे और सभी प्रक्रियाओं को तार्किक और सरलीकृत करने के लिए एक कार्य योजना का क्रियान्वयन करेंगे। साथ ही वे बोझ वाले अनुपालनों को हटायेंगे, कानूनों को गैर अपराधी बनायेंगे और पुराने पड़ गये कानूनों को समाप्त करेंगे।
- विनियामक अनुपालन पोर्टल वास्तविक आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को हासिल करने में मदद देगा और उद्योग के लिए व्यवसाय को सुगम बनाने में सहायता करेगा और नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनायेगा।
- इस विभाग का निर्देशन कैबिनेट सचिव द्वारा किया जा रहा है जो नागरिकों और व्यवसायों के लिए विनियामक अनुपालन बोझ को न्यूनतम करने के अभ्यास में समन्वय करने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है।

महत्व

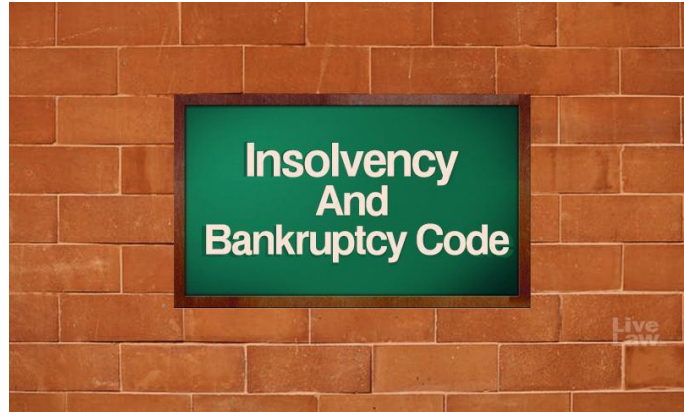
- यह प्रत्येक मंत्रालय/विभाग और राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्टों को कस्टमाइज करेगा। यह निगरानी और मूल्यांकन के लिए सृजित किया गया है।
- यह भारत की विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली व्यवसाय करने की सुगमता रिपोर्ट में रैंक सुधारने में मदद देगा, जो 2014 के 142वें स्थान से सुधरकर 2019 में 63वीं हो चुकी है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- राजनीतिशास्त्र + अर्थशास्त्र, स्रोत- PIB

दीवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) का अनुच्छेद 32A

खबर में क्यों है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में दीवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) संशोधन कानून 2020 की वैधता को सही ठहराया।



निर्णय की खास बातें

- सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि दीवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के अंतर्गत कार्पोरेट ऋणी के लिए सफलतापूर्वक निविदा किसी भी जांच एजेंसी द्वारा की गई जांच से परे होगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने IBC के अनुच्छेद 32A की वैधता को सही ठहराया है और यह कहा कि यह IBC के लिए महत्वपूर्ण है कि वह निविदाकर्ता को आकर्षित करे जोकि कार्पोरेट दीवाला सुलझाने की प्रक्रिया (CIRP) के समय पर समाप्ति को सुनिश्चित करने लिए कार्पोरेट ऋणी के लिए न्यायोचित और सही मूल्य का प्रस्ताव देगा।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि यह संरक्षण कार्पोरेट ऋणी की संपत्तियों को दिया जाए, जोकि संभावित निविदाकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण होगा और उन्हें कंपनी के लिए एक उचित निविदा के आकलन और रखे जाने में मदद देगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि यह भी कहा कि यह बचाव केवल उसी समय लागू होगा जब एक स्वीकृत निपटारा योजना होगी और कार्पोरेट ऋणी के प्रबंधन नियंत्रण में परिवर्तन होगा।

IBC के अनुच्छेद 32A के बारे में

- सफल निविदाकर्ता को संरक्षण और एक कार्पोरेट ऋणी की संपत्तियों को दीवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के अनुच्छेद 32A के अंतर्गत नियमों से उपलब्ध करवाया गया है। यह सफलतापूर्वक निपटारे का विषय है कि आवेदक अपराध करने में शामिल नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय क्यों अनुच्छेद 32A को महत्वपूर्ण ठहरा रहा है?

- जबसे दीवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 से प्रभावी हुई है, कई बड़े मामलों की निपटारा योजना में देरी कर दी गई है क्योंकि उनकी अपनी एजेंसियों और विनियामकों ने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
- विशेषज्ञों का कहना है कि यह अन्य निविदाकर्ताओं को आत्मविश्वास प्रदान करेगा जिससे वे आसानी से आगे बढ़ेंगे जबकि वे इस तरह की विवादित कंपनियों और उनकी संपत्तियों की निविदा डाल रहे होंगे।

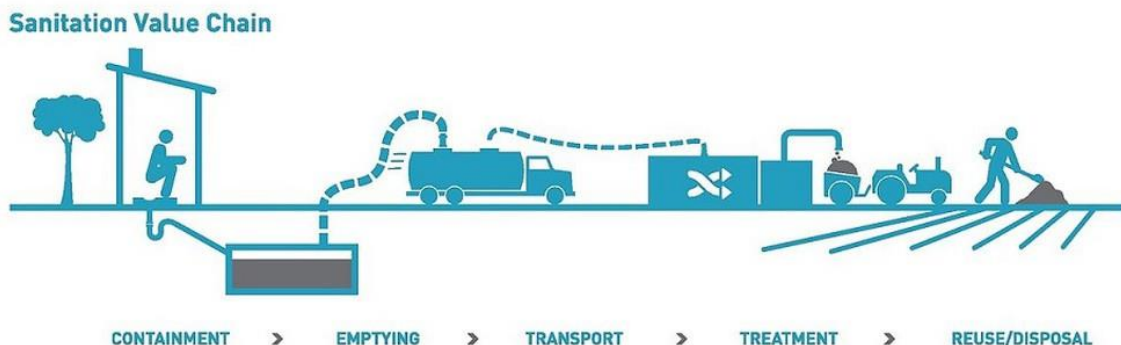
विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- राजनीतिशास्त्र अर्थशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

शहरी क्षेत्रों में मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM)

खबर में क्यों है?

- नीति आयोग ने हाल में शहरी क्षेत्र में मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) पर एक किताब जारी की है।



FSSM के बारे में

- इसे संयुक्त रूप से नेशनल फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट (NFSSM) गठबंधन ने विकसित किया है।
- इस किताब में 27 मामलों के अध्ययनों को जो दस राज्यों से हैं, को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही विभिन्न सेवा और व्यवसाय मॉडलों को भी दिया गया है जिन्हें मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) पहलों को क्रियान्वित करते समय भारतीय शहरों द्वारा अपनाया गया है।
- यह किताब FSSM की बेहतर प्रथाओं पर सही समय पर एक कोष प्रदान करती है जिन्हें पूरे देश में उपयुक्त रूप से अनुकूलित एवं दोहराया गया है।
- यह रिपोर्ट उल्लेख करती है कि लगभग 60% शहरी परिवार स्थल पर स्वच्छता प्रणालियों पर निर्भर करते हैं, जिसे इन प्रणालियों के कन्टेनमेंट संरचनाओं में एकत्रित अपशिष्ट एकत्रित करने के लिए एक समर्पित योजना की जरूरत है।

राष्ट्रीय शहरी मल कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) के बारे में

- शहरी विकास मंत्रालय ने मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) पर राष्ट्रीय नीति की शुरुआत की है जिससे भारत में FSSM का राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन सुगम बनाया जा सके जोकि स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है।
- नीति का मुख्य जोर शहरों और शहरी स्थानीय निकायों में मल सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना करने पर है और शहरी भारत में सीवेज प्रणाली की पुनर्संरचना को सुलझाने में है।
- FSSM राष्ट्रीय स्तर पर नीति में कमी का भी ध्यान रखता है जिससे शहरी स्वच्छता में अंतरालों को सुलझाया जा सके और मल कीचड़ और सेप्टेज के निपटान के लिए स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य बनाता है।

संबंधित सूचना

स्वच्छ भारत मिशन के बारे में

- केंद्र ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण को अपनी मंजूरी दे दी है।
- दूसरे चरण का क्रियान्वयन 2020-21 और 2024-25 के बीच में एक मिशन मोड पर किया जाएगा।

- दूसरा चरण खुले में शौच से मुक्त प्लस (ODF Plus) पर जोर देगा, जिसमें शामिल हैं ODF सततता और ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM)।
- ODF प्लस कार्यक्रम MNNREGA में सम्मिलित हो जाएगा विशेष रूप से गंदेजल प्रबंधन के लिए, और नये शुरू किये गये जल जीवन मिशन का संपूरक होगा।
- यह कार्यक्रम यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पीछे न रह जाए और प्रत्येक व्यक्ति शौचालय का प्रयोग करे।

वित्तीयन साझेदारी

- केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीयन साझेदारी अनुक्रम उत्तर-पूर्वी राज्यों और हिमालियाई राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र के लिए 90:10 होगा; अन्य राज्यों के लिए 60:40 होगा; अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए 100:0 होगा, यह सभी घटकों के लिए होगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- PIB

पराक्रम दिवस

खबर में क्यों है?

- भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाषचंद्र बोस के जन्मदिन को 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है।



पराक्रम दिवस के बारे में

- इस दिन का उद्देश्य देश के लोगों को प्रेरणा देना है, विशेष रूप से युवावर्ग को, विषम परिस्थितियों का साहस के साथ सामना करना जैसा कि नेताजी ने किया था और उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना को भरना।
- 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित करने संबंधी गजेट अधिसूचना को प्रकाशित कर दिया गया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- DD न्यूज

MCA पैनल ने 'छोटे सीमित उत्तरदायित्व साझीदारी (LLPs)' के सृजन का सुझाव दिया

खबर में क्यों है?

- कंपनी कानून समिति (CLC) जिसका गठन 2019 में कार्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा किया गया था, ने हाल में सीमित उत्तरदायित्व साझीदारी की एक एक नई श्रेणी जिसे छोटी सीमित उत्तरदायित्व साझीदारी कहते हैं का सुझाव दिया है। इस पर कम अनुपालन शुल्क और दंड लगेंगे।

कंपनी कानून समिति (CLC) के बारे में

- 11 सदस्यीय समिति, जिसकी अध्यक्षता MCA के सचिव राजेश वर्मा द्वारा की जा रही है, में उदय कोटक, शार्दूल श्राफ और अजय बहल शामिल हैं।
- इसका गठन LLP कानून, 2008 में कुछ शमनीय अपराधों को गैर अपराध की श्रेणी में डालने का सुझाव देने के लिए किया गया था। साथ ही यह व्यवसाय करने की सुगमता को प्रोत्साहित करता है।

अनुशंसाओं की खास बातें

- सीमित उत्तरदायित्व साझीदारी (LLP) कानून के छोटे और तकनीकी उल्लंघनों को गैर अपराध की श्रेणी में रखना और LLPs को ज्यादा उधारी लोचनीयता प्रदान करना।
- उन्होंने 'छोटी LLPs' की नई संकल्पना को प्रस्तावित किया है। इनकी व्याख्या रु. 20 लाख के रूप में योगदान और रु. 40 लाख बिक्री अथवा किसी विशेष ऊंची शुरुआत जिसका नियम बनाया जाए, के रूप में की गई है।
- ऐसी छोटी LLPs को कम शुल्क का भुगतान करना होगा और दीवालिया होने पर कम दंड दिया जाएगा। इससे छोटे व्यवसायों पर अनुपालन लागत कम हो जाएगी।
- पैनल ने यह भी प्रस्तावित किया कि LLPs को गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs) जारी करने की अनुमति दी जाए। ये ऐसी संस्थाओं को दिया जाए जिसे RBI अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा विनियमित किया जाता है।
- इस समय, LLPs को उधार लेने की अनुमति है लेकिन वे ऋण प्रतिभूतियां नहीं जारी कर सकते हैं।
- पैनल ने यह सुझाव भी दिया कि LLPs के लिए लेखांकन एवं लेखा परीक्षा मानकों को निश्चित करने का एक प्रावधान किया जाए। इसे कानून में शामिल किया जाए।
- इसके पीछे विचार व्यवसाय वाहन के इस वर्ग में शासन में सुधार करना है।

सीमित उत्तरदायित्व साझीदारियों के बारे में

- यह एक वैकल्पिक कार्पोरेट व्यवसाय का रूप है जोकि एक कंपनी के सीमित उत्तरदायित्व का लाभ देती है और साथ ही साझीदारी का लोच भी प्रदान करता है।
- LLP साझीदारों के परिवर्तनों के बावजूद भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। यह अपने नाम से संविदा और होल्डिंग संपत्ति में प्रवेश करने में सक्षम है।
- LLP के अलग कानूनी संस्था है, जो अपने संपत्तियों के पूरे दायरे के लिए जिम्मेदार है, लेकिन साझीदार का उत्तरदायित्व LLP में उनके पूर्व स्वीकृत तक ही सीमित है।
- यह बिना विस्तृत कानूनी और प्रक्रियात्मक जरूरतों को लगाये हुए लोच प्रदान करती है।
- यह पेशेवर/तकनीकी विशेषज्ञता और पहल को नवाचार और सामर्थ्य तरीके से जोखिम लेने की वित्तीय क्षमता के साथ संयुक्त करके सक्षम बनाती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन + अर्थशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य टीके की हिचक और को-विन बग से कोविड-19 टीकाकरण अभियान में खलल

खबर में क्यों है?

- को-विन प्लेटफॉर्म गड़बड़ी और स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य टीके को लेकर हिचक के परिणामस्वरूप देश में कोविड टीकाकरण में असामान्य रूप से कम लोग आ रहे हैं जबसे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।



टीके पर हिचक के बारे में

- इसका अर्थ है टीकाकरण सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद टीके को स्वीकृत करने में देरी अथवा टीका लेने से मना करना।
- टीके को लेकर हिचक जटिल और संदर्भ विशेष है जो समय, स्थान एवं टीके के अनुसार बदलता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया है कि टीके को लेकर हिचक वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े 10 खतरों में से एक है जिसकी वजह से:
 - व्यक्ति अथवा समूह कारक (पूर्व टीकाकरण के साथ अनुभव, स्वास्थ्य प्रणाली और देने वाले का विश्वास)
 - प्रासंगिक प्रभाव (संचार और मीडिया, धर्म/संस्कृति/लिंग/सामाजिक)
 - कोई टीके से संबंधित मामला (जोखिम, लाभ, देने का तरीका)।

कोविड-19 टीके के प्रति हिचक प्राथमिक रूप से निम्न वजह से है-

- टीका कंपनियों की मंशा जिसके तहत वे सामान्य से ज्यादा तेजी से टीका उत्पादित करते हैं।
- गलत चिंताएं जैसे भारत में प्रयोग की जाने वाली दो टीकों के क्लिनिकल परीक्षण की कमी।

कोविड-19 टीका इन्टेलीजेंस नेटवर्क (Co-WIN) प्लेटफॉर्म के बारे में

- यह प्रयोग में आसान मोबाइल एप है जिससे टीके के आंकड़े रिकॉर्ड किये जाते हैं। यह विभिन्न माइयूल्स के साथ लाभकर्ता प्रबंधन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।
- प्लेटफॉर्म का प्रयोग टीके के आंकड़े को रिकॉर्ड करने में किया जाता है और यह स्वास्थ्य कर्मियों के डाटाबेस को भी तैयार करेगा।
- इस एप में प्रशासक, पंजीकरण, टीकाकरण, लाभकर्ता स्वीकृति और रिपोर्टों के लिए अलग माइयूल्स होगा।
- स्वास्थ्य कर्मियों का डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया में, जोकि सभी राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में अपनी उन्नत अवस्था में है। कोविन प्लेटफॉर्म पर डाटा को अपलोड किया जा रहा है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सामाजिक मामले

स्रोत- द हिंदू

श्रमशक्ति डिजीटल डाटा सॉल्यूशन

खबर में क्यों है?

- हाल में, आदिवासी मामलों के मंत्रालय और गोवा सरकार ने संयुक्त रूप से प्रवासी मजदूरों और आदिवासी प्रवास प्रकोष्ठ के लिए श्रमशक्ति डिजीटल डाटा सॉल्यूशन की शुरुआत की है।

श्रमशक्ति डिजीटल डाटा सॉल्यूशन के बारे में

- यह प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के आसान निर्माण के लिए प्रभावी रूप से मदद करेगा।
- यह गोवा को विभिन्न राज्यों से लगभग 4 लाख प्रवासियों को प्रोत्साहित और समर्थन देने में भी मदद करेगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सामाजिक मुद्दे

स्रोत- द हिंदू

राष्ट्रीय मतदाता दिवस (NVD)

खबर में क्यों है?

- भारतीय चुनाव आयोग 25 जनवरी, 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है।
- इस वर्ष की थीम है: “अपने मतदाता को सशक्त, जागरूक और सुरक्षित और सूचना से लैस करना”।



राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में

- यह 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका समारोह पूरे देश में मनाया जाता है जिसका उद्देश्य भारतीय चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को मनाना है अर्थात 25 जनवरी, 1950।
- NVD** मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य नामांकन को प्रोत्साहित, सुगम और अधिकतम करना विशेष रूप से नये मतदाताओं के लिए।

संबंधित सूचना

ECI का वेब रेडियो: हैलो मतदाता

- यह ऑनलाइन डिजीटल रेडियो सेवा मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को सुनाएगी।
- इसपर भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट की एक लिंक के द्वारा पहुँचा जा सकता है।
- रेडियो हैलो मतदाता की कार्यक्रम की शैली की संकल्पना लोकप्रिय एफएम रेडियो सेवाओं के सुमेलन के रूप में की गई है।
- यह पूरे देश से हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में गीतों, नाटकों, चर्चाओं, खेलकूद, चुनावों पर कहानियों इत्यादि के द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं पर सूचना और शिक्षा उपलब्ध करवाएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- PIB

असमानता वायरस

खबर में क्यों है?

- हाल में एक ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार, जिसका शीर्षक “असमानता वायरस” है, ने पाया है कि कोविड महामारी ने भारत और पूरी दुनिया में वर्तमान असमानताओं को और भी बढ़ा दिया है।

रिपोर्ट की प्रमुख खास बातें



- रिपोर्ट की खास बात यह है कि जैसे महामारी ने अर्थव्यवस्था पर लगाम लगाई है, जिससे लाखों भारतीय नौकरियों से बाहर हो गए हैं, भारत के सबसे धनी अरबपतियों ने अपनी संपत्ति में 35 प्रतिशत की वृद्धि की है।
- रिपोर्ट का कहना है कि भारतीय अरबपतियों के धन में लॉकडाउन के दौरान 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2009 से 90 प्रतिशत की वृद्धि के साथ \$422.9 अरब की वृद्धि हुई है जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद भारत छठवें स्थान पर पहुँच गया है।
- भारत के सर्वोच्च 100 अरबपतियों की संपत्ति में लॉकडाउन के दौरान रु. 12.97 ट्रिलियन की वृद्धि हुई है जोकि सबसे ज्यादा 138 मिलियन गरीब भारतीयों में से प्रत्येक को रु. 94,045 का चेक देने के लिए पर्याप्त है।
- रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल 2020 में प्रत्येक घंटे 170,000 लोगों ने अपनी नौकरियों से हाथ धोया।
- ऑक्सफैम की गणना के अनुसार, महामारी के दौरान भारत के सर्वोच्च 11 अरबपतियों की संपत्ति में वृद्धि से 10 वर्षों तक NREGS की योजना चलाई जा सकती है अथवा 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्रालय चलाया जा सकता है।
- महामारी से स्वास्थ्य और शिक्षा असमानताओं में भी वृद्धि हुई।

महामारी ने कैसे सभी प्रकार की असमानताओं में वृद्धि की?

क्षेत्रीय असमानताएं

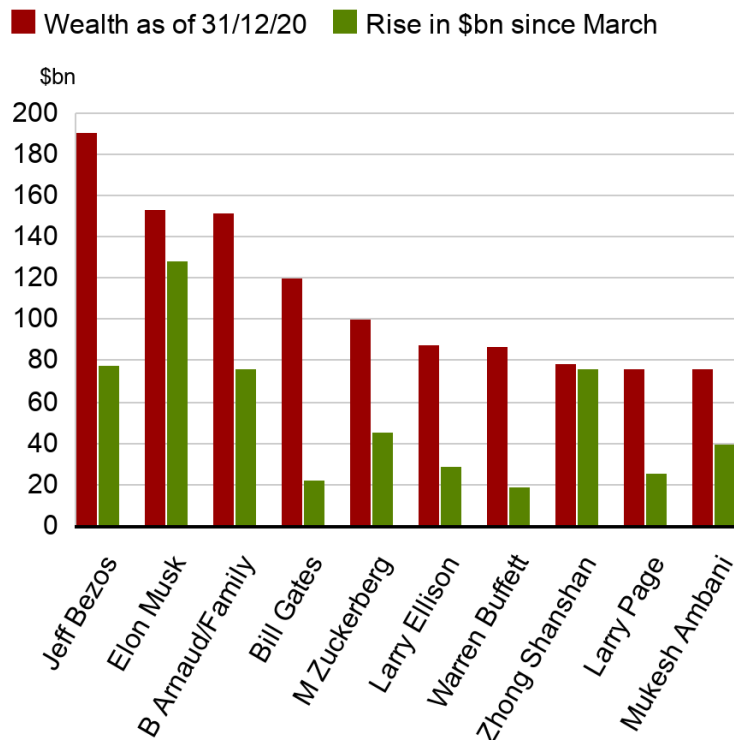
- भारत की बड़ी अनौपचारिक श्रमशक्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई क्योंकि इसने 122 मिलियन नौकरियों में से 75% नौकरियां खोईं।

- 40-50 मिलियन मौसमी प्रवासी मजदूर जो सामान्य रूप से निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों इत्यादि में कार्यरत थे, विशेष रूप से प्रभावित हुए।

शैक्षिक असमानताएं

March of the billionaires

How their wealth rose from March to December 2020



Source: Oxfam/The Inequality Virus

BBC

- पूरे पिछले वर्ष जब शिक्षा ऑनलाइन हो गई, भारत ने डिजिटल विभाजन के रूप में असमानता को देखा।
- सबसे ज्यादा गरीबों में से केवल 3 प्रतिशत जो भारतीय परिवारों का 20 प्रतिशत हैं, के पास कंप्यूटर है, और केवल 9 प्रतिशत के पास ही इंटरनेट है।

स्वास्थ्य सेवाएं

- ऑक्सफैम ने पाया है कि क्योंकि भारत सामाजार्थिक अथवा सामाजिक श्रेणियों के अनुसार केस डाटा को रिपोर्ट नहीं करता है, विभिन्न समुदायों के मध्य में रोग के वितरण को समझ पाना मुश्किल है।
- गरीब समुदायों के मध्य में रोग का फैलाव काफी ज्यादा था, जोकि अक्सर सिकुड़े इलाकों में रहते हैं जहां स्वच्छता की स्थिति खराब है। वे समान सुविधाएं जैसे शौचालयों और जल बिंदुओं का प्रयोग करते हैं।
- इस संबंध में, यह पाया गया कि सबसे ज्यादा गरीब 6 प्रतिशत जो 20 प्रतिशत परिवार हैं, के पास सुधरे हुई स्वच्छता वाली गैर साझीदारी वाले स्रोत हैं। इसकी तुलना में भारत में 20 प्रतिशत परिवार है जिनके पास 93 प्रतिशत इस तरह की सुविधाएं हैं।

लैंगिक असमानताएं

- महिलाओं के मध्य बेरोजगारी की दर कोविड के पूर्व के 15 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई।
- महिलाओं के मध्य बेरोजगारी में यह वृद्धि से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8 प्रतिशत अथवा \$218 अरब का नुकसान हो सकता है।
- सामाजिक अध्ययन न्यास संस्थान द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, वे महिलाएं जिनकी नौकरियां बची रहीं, इनमें से लगभग 83% के वेतन में कटौती की गई।
- आय और नौकरियां खोने के अतिरिक्त, सबसे ज्यादा गरीब महिलाओं को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी हानि उठानी पड़ी क्योंकि नियमित स्वास्थ्य सेवाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में बाधा पैदा हुई।
- महामारी की वजह से महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले बढ़े।
- 30 नवंबर, 2020 तक, पिछले 12 महीनों की अपेक्षा घरेलू हिंसा के मामलों में 60% की वृद्धि हुई।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सामाजिक विषय

स्रोत- द हिंदू

कानून आयोग को "वैधानिक निकाय" घोषित किए जाने की जनयाचिका पर उच्चतम न्यायालय का केंद्र सरकार को नोटिस

खबरों में क्यों है?

- उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें केंद्र को भारत के विधि आयोग को "वैधानिक निकाय" घोषित करने और एक महीने के भीतर एक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है ।



भारत के विधि आयोग के बारे में

- यह भारत सरकार के एक आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है।
- प्रथम विधि आयोग की स्थापना ब्रिटिश राज के दौरान 1834 में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा की गई थी और स्वतंत्र होने के बाद इसे पहली बार 1955 में स्थापित किया गया था।

कार्यकाल

- इसका कार्यकाल तीन वर्षों का होता है।

रचना

- 22वां विधि आयोग आधिकारिक राजपत्र में अपने आदेश के प्रकाशन से तीन वर्षों के लिए गठित किया जाएगा।
- इसमें निम्न सदस्य शामिल होंगे:
 - एक पूर्णकालिक अध्यक्ष
 - चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित)
 - पदेन सदस्य के रूप में कानूनी मामलों के विभाग का सचिव
 - पदेन सदस्य के रूप में विधायी विभाग का सचिव
 - पांच से कम अंशकालिक सदस्य

कार्य

- यह अप्रचलित कानूनों की पहचान करता है।
- ऐसे कानून जो अब प्रासंगिक नहीं हैं, मौजूदा वातावरण के साथ मेल नहीं खाते हैं और जिन कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है।
- यह कानून के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए उपयुक्त उपाय सुझाता है।
- यह गरीबों को कानूनी प्रक्रिया से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।
- इसी तरह, यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कानूनों की जांच करता है।
- हालांकि, आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। सरकार या संबंधित विभाग इन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

संदर्भ की शर्तें

- केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ अथवा अपनी स्वप्रेरणा (suo-motu) से विधि आयोग कानून में शोध करेगा और उसमें सुधार करने और नए कानून बनाने के लिए भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा।
- यह प्रक्रियाओं में देरी, मामलों के त्वरित निपटान, मुकदमेबाजी की लागत में कमी आदि में न्याय वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करेगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II-राजनीति

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

विरल रोगों पर 31 मार्च तक नीति अंतिम करें

खबर में क्यों है?

- हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को 31 मार्च तक 2020 के विरल रोगों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अंतिम करने का निर्देश दिया है। साथ ही उच्च लागत वाले विरल रोगों के उपचार के लिए कानून के अंतर्गत संकल्पित दान के लिए धन जमा करने के प्रचालनात्मक प्रावधानों को भी बनाने का निर्देश दिया है।

विरल रोग क्या हैं?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विरल रोग वे हैं जिनसे अक्सर जीवन भर के लिए अशक्तता रोग हो जाते हैं। ये रोग प्रति 1,000 की जनसंख्या में 1 अथवा इससे भी कम लोगों को होते हैं।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, यह 2,500 लोगों में से एक अथवा इससे भी कम लोगों को होता है।

संबंधित सूचना

विरल रोग 2020 पर राष्ट्रीय नीति प्रारूप

- प्रारूप नीति एक एकीकृत निरोधात्मक रणनीति पर आधारित विरल रोग की घटनाओं को कम करने के उपाय सुझाती है।
- यह विरल रोग के रोगियों को वहनीय स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को सुगम बनाती है जो एक बार के उपचार के लिए उत्तरदायी है।
- प्रारूप नीति का मुख्य जोर विशेषज्ञों द्वारा विरल रोगों के सभी तीनों समूहों के लिए प्राथमिकता के रूप में विरल रोग के निरोध पर है।

नीति के उद्देश्य के लिए, शब्दावली विरल रोग को तीन समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया है:

- रोग जो एक बार के उपचारात्मक उपचार के प्रति उत्तरदायी हैं।
- वे रोग जिनकी दीर्घावधि/जीवन भर के उपचार की जरूरत है और जिनका उपचार की लागत सापेक्षिक रूप से कम है। इनका साहित्य में दस्तावेजीकरण किया गया है और जिनके लिए वार्षिक अथवा ज्यादा बार निगरानी की जरूरत है।
- वे रोग जिनके लिए निश्चित उपचार उपलब्ध है लेकिन चुनौती यह है कि लाभ के लिए एक अनुकूलतम रोगी चुनाव करने की जरूरत है। इसकी लागत काफी ज्यादा और दीर्घावधि थेरेपी की जरूरत होती है।

वित्तीय समर्थन

- राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छतरी योजना के अंतर्गत प्रत्येक रोगी को अधिकतम रु. 15 लाख उपलब्ध कराए जा सकते हैं, और लाभकर्ताओं को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक सीमित नहीं किया जाएगा।
- इसका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नियमों के अनुसार जनसंख्या के 40% तक विस्तार किया जाएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- स्वास्थ्य मामले

स्रोत- द हिंदू

डोपिंग

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय युवा मामले एवं खेलकूद मंत्री ने हाल में, एंटी डोपिंग के क्षेत्र में रासायनिक परीक्षण में प्रयोग के वास्ते एक खास **संदर्भ सामग्री** को जारी किया है।

संदर्भ सामग्री के बारे में

- इसे राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) एवं राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल्स शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPER), गुवाहाटी द्वारा संश्लेषित किया गया है।
- इस संदर्भ सामग्री (RM) की पहचान **NDTL** द्वारा वैश्विक रूप से उपलब्ध सबसे विरल में से एक संदर्भ सामग्री के रूप में की गई है।
- इसका प्रयोग सभी विश्व की एंटी डोपिंग एजेंसी (**WADA**) द्वारा प्रमाणित प्रयोगशालाओं द्वारा एंटी डोपिंग उपायों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
- इस संदर्भ सामग्री की उपलब्धता से एंटी डोपिंग प्रयोगशालाओं को अपनी परीक्षण क्षमता को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

- यह खेलकूद में स्वस्थ परंपरा के प्रोत्साहन के बड़े कारण में मदद देगा।

राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) के बारे में

- यह युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जो दिल्ली में स्थित है।
- यह देश में एकमात्र प्रयोगशाला है जो मानव खेलकूद डोप परीक्षण के लिए जिम्मेदार है।

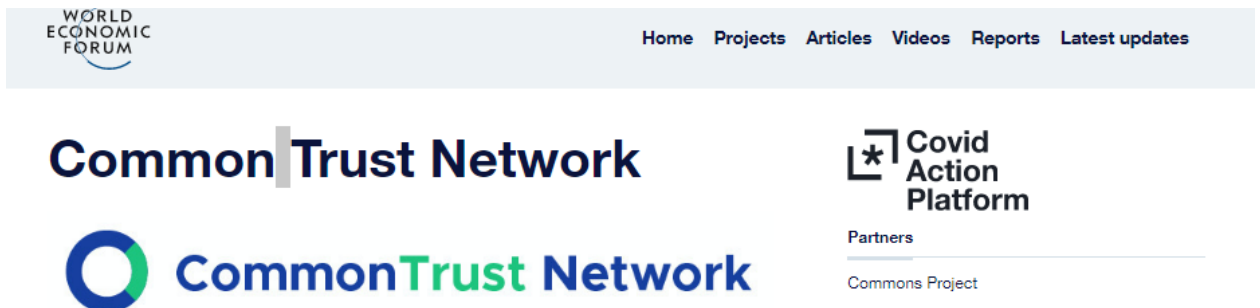
विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- स्वास्थ्य मामले

स्रोत- द हिंदू

समान न्यास नेटवर्क

खबर में क्यों है?

- हाल में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा विश्व स्वास्थ्य मंच के समान न्यास नेटवर्क के लिए अंतरसीमा गत्यात्मकता की बहाली पर एक समारोह को संबोधित किया।



समान न्यास नेटवर्क के बारे में

- जब पूरे विश्व में देश कोविड-19 महामारी से पार पाने के लिए प्रयासरत हैं और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, वे सभी अपनी सीमाओं को खोलने की चुनौती का भी सामना कर रहे हैं। साथ ही अपनी जनसंख्याओं के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए यात्रा और वाणिज्य को शुरू करने का भी प्रयास कर रहे हैं।
- जब ये देश सीमाओं की रोक, क्वारंटीन और लॉकडाउन पर छूट देने के बारे में सोच रहे हैं, तब सरकारों और उद्योग को व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानने के लिए एक ज्यादा विश्वसनीय मॉडल की जरूरत है।

समान न्यास नेटवर्क की डिजाइन इसलिए की गई है-

- (1) लोगों को उनकी स्वास्थ्य सूचना के साथ डिजिटल पहुँच तक समर्थ बनाना।
- (2) व्यक्तियों के लिए आसान बनाना जिससे वे प्रत्येक गंतव्य की जरूरतों के बारे में समझ सकें और उनका अनुपालन कर सकें।
- (3) यह सुनिश्चित करने में सहायता करें कि केवल विश्वसनीय प्रयोगशाला परिणामों और टीकाकरण रिकॉर्ड जोकि विश्वसनीय स्रोतों से हों, को ही प्रस्तुत किया जाए।

समान न्यास रजिस्ट्री

- समान न्यास नेटवर्क को विश्वसनीय प्रयोगशाला और टीकाकरण आंकड़ा स्रोतों, प्रयोगशाला परिणामों और टीकाकरण रिकॉर्डों के लिए मानक प्रारूपों, और उन परिणामों और रिकॉर्डों को डिजिटल तरीके से पहुँच वाला बनाने के लिए मानक उपकरणों की वैश्विक रजिस्ट्री द्वारा सक्षम बनाया जाता है।

- एक समान वैश्विक रजिस्ट्री सरकारों और अन्य गंतव्यों के लिए समान न्यास नेटवर्क को सक्षम बनाती है जिससे वे समान प्रारूप में स्वास्थ्य जांच प्रवेश नियमों को प्रकाशित कर सकें। यह यात्रियों और पर्यटन उद्योग के लिए प्रत्येक गंतव्य स्थान की जरूरतों को समझने और उनका अनुपालन करने को आसान बना देगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- स्वास्थ्य मामले

स्रोत- PIB

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

H-1B कार्य वीजा

खबर में क्यों है?

- हाल में, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन ने एक बार फिर से H-1B वीजा नियमों को संशोधित किया जिसके लिए नियम परिवर्तित किये गए कि योग्य उम्मीदवारों के चुनाव के लिए ऊंचे वेतन और कौशल को प्राथमिकता दी जाएगी।



क्या हैं H-1B कार्य वीजा?

- 1952 में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना आरंभ किया, तो उसने गुणवत्ता वाले कर्मचारियों को लेने की जरूरत महसूस की।
- कर्मचारियों को लेने की जरूरत की वजह से H-1B वीजा कार्य प्रणाली को लागू करने का रास्ता प्रशस्त हुआ।
- बाद में कार्य वीजा प्रणाली को H-1B, L1, O1 और E1 वीजा में उपविभाजित कर दिया गया, यह पात्रता की जरूरत पर निर्भर करता है।
- H-1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को विशेष कार्यों में कार्य करने के लिए रखने की इजाजत देता है। ये कार्य सैद्धांतिक अथवा तकनीकी विशेषज्ञता के होते हैं।

नए वेतन आधारित H-1B वीजा शासन

- नया वेतन आधारित कार्य वीजा शासन उन कर्मचारियों के आवेदनों के वीजा के चुनाव में अब प्राथमिकता देगा जहां रोजगार के क्षेत्र में चल रहे स्तरों से प्रस्तावित वेतन बराबर अथवा ज्यादा होते हैं।
- प्रस्तावित वेतन वह वेतन है जोकि नियोक्ता अपने लाभकर्ता को भुगतान करना चाहता है।
- यह कार्य नियमित 65,000 वीजा और 20,000 उन्नत डिग्री एक्जेम्प्शन वीजा के लिए किया जाएगा।
- यह आदेश वह कौशल जो विभिन्न कर्मचारी देश में ला रहा है, को भी संज्ञान में लेगा यह इस बात की जांच करेगा कि क्या यह कौशल अमेरिकी कर्मचारियों के मध्य समान लागत में उपलब्ध है।
- यह दोनों ही H-1B नियमित कैप और H-1B उन्नत डिग्री एक्जेम्प्शन के लिए क्रियान्वित किया जाएगा, लेकिन यह दो के बीच में चुनाव का क्रम नहीं परिवर्तित करेगा, जैसा कि H-1B पंजीकरण अंतिम नियम द्वारा स्थापित है।

- यह नियोक्ताओं को ऊंचे वेतन और/अथवा ऊंचे कौशल स्थितियों की पिटीशन देने के लिए प्रोत्साहित करेगा और कार्मिक जरूरतों को हासिल करने के ज्यादा निश्चित पथ के व्यवसायों को स्थापित करेगा जिससे व्यवसाय वैश्विक तौर पर प्रतियोगी हो सके।

H-1B चुनाव के लिए लॉटरी प्रणाली क्या है?

- वर्तमान में, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशासन 85,000 H-1B कार्य परमिटों को जारी करता है।
- इनमें से, 65,000 लोग विशेषज्ञता वाले व्यवसायों से हैं, जबकि बाकी विदेशी कर्मचारियों के लिए आरक्षित है जिन्होंने अमेरिका में ही परास्नातक अथवा ऊंची विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल की है।
- क्योंकि प्रत्येक वर्ष H-1B वीजा के लिए दायर किये गए आवेदन विशेषज्ञता वाले व्यवसायों में 65,000 की सीमा से ज्यादा होते हैं और ऊंची शिक्षा श्रेणी के 20,000 से भी ज्यादा होते हैं, संयुक्त राज्य नागरिकता और प्रवासी सेवाएं पात्र आवेदकों के लिए एक यादृच्छिक लॉटरी प्रणाली का प्रयोग करती है जिससे 65,000 रिक्तियां भर जाएं और फिर अगले 20,000 स्थान भरे जाते हैं।
- यह लॉटरी प्रणाली पूरी तरह से यादृच्छिक थी और वेतनमानों, कौशल अथवा नियोक्ताओं की जरूरतों जैसी जरूरतों को नहीं देखती थी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संबंध

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस (व्याख्यायित)

भारत संयुक्त राष्ट्र की हाई टेबुल पर

खबर में क्यों है?

- हाल में, भारत के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में चीन और पाकिस्तान दोनों के बारे में अप्रत्यक्ष संदर्भ दिया कि वे “अच्छे” और “खराब” आतंकवादियों के बीच में गलत अंतर बता रहे हैं। यह 2021-2022 के लिए UNSC का पहला सत्र था।



संबंधित सूचना

- भारत 2021-2022 के लिए एशिया-प्रशांत श्रेणी से गैर स्थाई सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में चुना गया है। यह आठवीं बार है कि भारत UNSC के लिए चुना गया है।

पहले के चुनाव

- भारत ने पहले अपनी सात बार सेवाएं दी हैं: 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12।

- भारत को सभी सदस्य देशों के साथ वैश्विक शांति, सुरक्षा, लचीलेपन और समानता को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है और इसकी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने की जिम्मेदारी है।
- इस शक्तियों में शामिल हैं शांति मिशन की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के द्वारा सैन्य कार्रवाईयों को प्राधिकृत करना।

बाध्यकारी प्रस्तावों को जारी करने की शक्ति

- यह एकमात्र संयुक्त राष्ट्र का निकाय है जिसे सदस्य देशों को बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार हासिल है।
- सुरक्षा परिषद में पंद्रह सदस्य होते हैं जिनमें पांच सदस्य स्थाई निकाय और दस गैर स्थाई सदस्य होते हैं।
- रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन इस निकाय के पांच स्थाई सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं।
- ये स्थाई सदस्य किसी भी सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं, जिसमें नये सदस्य देशों के प्रवेश अथवा महासचिव के लिए उम्मीदवार भी शामिल हैं।
- सुरक्षा परिषद में 10 गैर स्थाई सदस्य भी होते हैं, जिन्हें दो वर्षों के कार्यकाल के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है।
- इस निकाय की अध्यक्षता इसके सदस्यों के बीच में मासिक आधार पर बदलती रहती है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग

- संयुक्त राष्ट्र सचिवालय
- संयुक्त राष्ट्र आमसभा
- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद
- संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संगठन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

डोनाल्ड ट्रंप दो बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति

खबर में क्यों है?

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका सदन द्वारा पुनरुत्थान को भड़काने के एकल इल्जाम में महाभियोग का सामना करना पड़ा। यह उनके समर्थकों द्वारा भड़काये गये दंगे में उनकी भूमिका के लिए किया गया जिसमें पांच लोगों की मृत्यु हुई और कैपिटॉल को तहस-नहस कर दिया गया। इससे उनकी कार्यावधि पूरे होने के एक सप्ताह पहले ही उनकी विरासत पर न मिटने वाला दाग लग गया।



ऐतिहासिक वोट

- संयुक्त राज्य प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी इतिहास में दो बार महाभियोग का सामना करने वाला पहला राष्ट्रपति बना दिया। सदन ने औपचारिक रूप से कार्यकारी अमेरिकी राष्ट्रपति को पुनरुत्थान के लिए उकसाने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के साथ, पुलिस भी कैपिटॉल की सुरक्षा कर रही थी, यह मतदान उस कांड के एक हफ्ते के बाद हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के रूप में हिंसक भीड़ ने कैपिटॉल की घेराबंदी कर दी थी।
- यह 13 महीने में दूसरी बार है कि उन्होंने महाभियोग का सामना किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग से यह सुनिश्चित हो गया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यह प्रस्ताव बिना किसी विरोध के 232 वोटों से पारित हुआ।
- अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी 2021 को कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- पहले डोनाल्ड ट्रंप इसलिए महाभियोग चला था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन की जांच करने के एवज में यूक्रेन को मदद की पेशकश की है। जो बाइडेन पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं जो 2020 में व्हाइट हाउस के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे। ट्रंप के कार्य को संविधान का गंभीर उल्लंघन माना गया था।

अमेरिका में महाभियोग कैसे कार्य करता है?

- अमेरिकी संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति पर पद से राजद्रोह, रिश्वतखोरी अथवा अन्य ऊंचे अपराधों और गलत आचरण के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। यह हटाना दो अलग भागों में होता है: महाभियोग जिसे प्रतिनिधि सभा में चलाया जाता है और सीनेट में ट्रायल।
- किसी राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, उपस्थित दो-तिहाई सीनेटरों को अभियोग साबित करने के लिए जरूर मत देना होता है।
- महाभियोग का ट्रायल आपराधिक मुकदमों की तरह से होता है, जिसमें एक न्यायाधीश (अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश), एक अभियोजन (ट्रायल का प्रबंधन करने के नियुक्त सदन के सदस्य), एक सामना करने वाला (महाभियोग का सामना करने वाला राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का वकील), और एक ज्यूरी (सीनेट) होते हैं। साक्ष्यों को सुनने के बाद और एक निजी सत्र में चर्चा करने के बाद, सीनेट दोषी करार देती है या फिर आरोपमुक्त कर देती है।

राष्ट्रपति को कितनी जल्दी दोषी ठहराया जा सकता है?

- यह निर्भर करता है। सदन को महाभियोग का दोषी साबित करने के लिए सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। यह महाभियोग प्रस्ताव और महाभियोग के अनुच्छेदों को पारित करवा सकती है बिना जांच के अथवा सदन की न्यायपालिक समिति के मतदान के बिना ही।

किन अन्य अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ?

- राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन- 1868 में
- रिचर्ड निक्सन 1973 और 1974 में औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया के विषय थे।
- राष्ट्रपति बिल क्लिंटन- 1998 में

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संबंध

स्रोत- RSTV, द हिंदू

जो बाइडेन अपने कार्यकारी आदेशों में पेरिस मौसम समझौते और ईरान नाभिकीय समझौते पर ट्रंप के आदेश को बदलेंगे

खबरों में क्यों है?

- जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अपने कार्यालय के पहले दिन कार्यकारी आदेशों की ऋखला पर हस्ताक्षर करेंगे जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस मौसम समझौते और ईरान नाभिकीय समझौते पर फिर से वापस आएगा।

पृष्ठभूमि

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने औपचारिक रूप से 4 नवंबर 2020 को पेरिस मौसम समझौता को छोड़ दिया था; यह कार्य तीन वर्ष के बाद हुआ था जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे समाप्त करने की अपनी मंशा जाहिर की थी। इस समझौते को उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा की प्रमुख उपलब्धि माना गया था।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस समझौते क्यों छोड़ा?

- 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के अभियान के दौरान, उन्होंने पेरिस मौसम समझौते के अमेरिका हितों के लिए "गलत" बताया था, और चुने जाने पर समझौते से बाहर आने का वादा किया था।
- इसलिए जून 2017 में, राष्ट्रपति बनने के महीनों बाद, ट्रंप ने अपनी सरकार के समझौते को छोड़ने के फैसले की घोषणा की थी।
- लेकिन, अमेरिका तुरंत पेरिस समझौते से बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के नियम कहते हैं कि कोई भी देश समझौते के प्रभावी होने के तीन सालों के बाद ही बाहर आ सकता है अर्थात् नवंबर 4, 2019।
- अमेरिकी ने औपचारिक तौर पर इसी दिन संधि से बाहर आने के लिए आवेदन किया था, और वह 4 नवंबर, 2020 को स्वतः इससे बाहर आ गया, जोकि एक वर्ष की जरूरी लंबी अवधि का अंत था।

ईरान नाभिकीय समझौता

पृष्ठभूमि

- ईरान पूरी तरह से JCPOA (कार्यवाही की संयुक्त समग्र योजना) नाभिकीय समझौते से हट गया है। यह घोषणा उस समय की गई जब अमेरिकी सेनाओं ने जनरल कासेम सोलेमानी की हत्या कर दी।

ईरान नाभिकीय समझौते के बारे में

- ईरान नाभिकीय समझौते (अथवा कार्यवाही के लिए संयुक्त समग्र योजना (JCPOA)) पर हस्ताक्षर ईरान और पी5, प्लस जर्मनी और यूरोपीय संघ द्वारा 2015 में किये गये थे।
- पी5 UNSC के पांच स्थाई सदस्य हैं (संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम)।
- इस समझौते का उद्देश्य ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम पर लगाम लगाना था।

समझौते के अंतर्गत:

- ईरान का अधिकांश प्रसंस्कृत यूरेनियम देश के बाहर भेजा जा चुका है।
- एक भारी जल सुविधा को गैर प्रचालित कर दिया गया था
- प्रचालनात्मक नाभिकीय सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय देखरेख के आधीन लाया गया
- बदले में, समझौते में ईरान पर से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना शामिल था।

संयुक्त राज्य अमेरिका समझौते से बाहर क्यों आया?

- ट्रंप और समझौते के विरोधियों का कहना है कि यह एकतरफा है क्योंकि यह ईरान की अरबों डॉलर तक पहुँच को बनाता है लेकिन अमेरिका द्वारा माने गये हामास एवं हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी समूहों को ईरानी समर्थन के बारे में बात नहीं करती है।
- वे कहते हैं कि यह ईरान द्वारा विकसित की जा रही बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी रोक नहीं लगाती है और यह समझौता 2030 तक समाप्त हो जाएगा।
- उसका कहना है कि ईरान ने पूर्व में नाभिकीय कार्यक्रम के बारे में झूठ बोला है।

विषय- सामान्य अध्ययन II- अंतरराष्ट्रीय संबंध

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

जो बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली

खबर में क्यों है?

- जो बाइडेन ने 20 जनवरी 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल लिया। अपने पहले भाषण में जो बाइडेन ने वादा किया कि वे सभी अमेरिकियों के लिए राष्ट्रपति हैं।
- उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पहली महिला, पहली अफ्रीकी अमेरिकी बन गई हैं, दक्षिण एशियाई मूल की यह पद ग्रहण करने वाली प्रथम व्यक्ति हैं।



- उन्होंने संघीय इमारतों में मास्क पहनने की जरूरत को राष्ट्रीय शासनदेश के रूप में लागू कर दिया है और कांग्रेस को एकतरफा अप्रवासन विधेयक भेजा है जोकि देश में गैरकानूनी रूप से रह रहे लाखों अप्रवासियों को नागरिकता का आठ वर्ष का रास्ता प्रशस्त कर देगा।
- बाइडेन ने कई कार्यकारी आदेश जारी किये हैं, जिसमें महामारी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, मौसम परिवर्तन और नस्ली अन्याय की बात है।
- भारत के प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई दी है।
- भारत उनके साथ भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कार्य करने की आशा करता है और द्विपक्षीय संबंधों को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने के लिए आशान्वित है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

स्रोत- द हिंदू

अमेरिकी राष्ट्रपति की सजा माफ करने और कम करने की शक्ति

खबर में क्यों है?

- अमेरिकी के निवर्तमान राष्ट्रपति ने अमेरिकी संविधान के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए 143 लोगों की सजाओं को माफ अथवा कम कर दिया है, जिसमें उनके एक समय के मुख्य रणनीतिकार स्टीव बेनॉन भी शामिल हैं।



अमेरिकी राष्ट्रपति की माफ करने की शक्तियां

- अमेरिकी राष्ट्रपति संघीय अपराधों से संबंधित सजाओं को माफ करने अथवा कम करने का संवैधानिक अधिकार हासिल है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति की माफ करने की शक्ति बिना सीमा के दी गई है और कांग्रेस द्वारा सीमित नहीं की जा सकती है। माफ करना एक वृहद कार्यकारी शक्ति है जोकि स्वेच्छा पर निर्भर करती है जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति अपनी माफ करने की शक्ति के लिए जवाबदेह नहीं हैं और इसे जारी करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- इसका अर्थ है अधिकारियों के महाभियोग के मामलों में राष्ट्रपति माफी नहीं दे सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति की माफ करने की शक्ति की सीमाएं

- संविधान का अनुच्छेद II, अनुच्छेद 2 कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के मामलों को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड स्थगन और माफ करने की शक्ति होगी।

- राष्ट्रपति की माफ करने की शक्ति राज्य के अपराधों पर लागू नहीं होती है, जिसका अर्थ है कि वे लोग जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा माफ किया जा चुका है, उनपर फिर से व्यक्तिगत राज्य कानूनों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है।

नोट:

- अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा संख्या में माफी देने वाले राष्ट्रपति फ्रैंकलीन डी. रूजवेल्ट थे (3,796)। वे देश के नेता द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान थे और सबसे लंबे वक्त 12 साल तक व्हाइट हाउस पर काबिज रहे।

आगे पढ़ाई: पार्डेनिंग पावर ऑफ द इंडियन प्रेसीडेंट

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- राजनीतिशास्त्र + अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

चीन ने अरुणाचल प्रदेश में नये गांव को सही ठहराया

खबर में क्यों है?

- हाल में, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे “वास्तविक नियंत्रण रेखा” पर निर्माण के बारे में अवगत हैं।
- ऐसा उसने एक रिपोर्ट के बाद कहा जिसमें गांव के उपग्रह चित्र दिखाये गये थे, जिसका निर्माण नवंबर 2019 और नवंबर 2020 के बीच में हुआ। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा के कुछ किमी. पर स्थित है, जिसके बाद भारत के अनुसार अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को अलग करने वाली सीमा है। यह अरुणाचल में ऊपरी सुबानसिरी जिले में त्सारी चु नदी के किनारे पर स्थित है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय अधिकारियों का कहना था कि यह क्षेत्र 1959 से ही चीन के नियंत्रण में है।



- पूरे क्षेत्र में लगभग दो दर्जन के आसपास स्थल हैं (पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई में) जहां सीमा को लेकर भारत और चीन में असहमति है।
- भारतीय अधिकारियों का कहना था कि इस क्षेत्र में पूर्व में चीन एक स्थाई सैन्य बैरक का निर्माण किया था।
- विश्लेषकों के अनुसार गांव का निर्माण क्षेत्र पर चीन के दावे को मजबूत करने के लिए है। यह हाल के दिनों में चीन द्वारा किये जा रहे वृहद प्रयासों के अनुसार भी है जिसके द्वारा चीन विवादित सीमा क्षेत्रों में नागरिक बस्तियां बसा रहा है, जिसे इसने भूटान के साथ भी किया है।

चीन का जवाब

- चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पार गांव का निर्माण निंदा के परे है क्योंकि उसने कभी भी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता ही नहीं दी।
- चीन की वैकासिक और निर्माण गतिविधियां उसके सीमाक्षेत्र के अंदर सामान्य बात हैं।
- यह निंदा के परे है क्योंकि यह उनके सीमाक्षेत्र में है।

चीन का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

- यह निर्माण ऐसा लगता है कि गरीबी उन्मूलन गांवों के निर्माण के कार्यक्रम का हिस्सा है।
- पहल के अंतर्गत, जिसे 2015 में तिब्बत आर्थिक कार्य सम्मेलन के बाद शुरू किया गया था, लगभग 600 गांवों का निर्माण किया गया है, जिसमें से लगभग 100 सीमा क्षेत्रों में हैं।
- जहां सरकार उन्हें गरीबी उन्मूलन गांव का नाम देती है, सीमा क्षेत्रों में कुछ गांव काफी दूरस्थ स्थानों पर हैं जहां आर्थिक गतिविधियां न्यूनतम हैं। इसलिए, इनका उद्देश्य रणनीतिक लगता है।
- लोगों को तिब्बत के कुछ भागों से नये गांवों में बसा दिया गया है, जिसमें चारवाहों के परिवार शामिल हैं, जो नये निर्मित घरों में रहेंगे।
- पिछले वर्ष निर्मित एक अन्य गांव, जिसे पांगडा कहते हैं, को ऐसे क्षेत्र में बसाया गया जिसे भूटान अपना क्षेत्र बतलाता है, यह एक अन्य विवादित क्षेत्र है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संबंध

स्रोत- द हिंदू

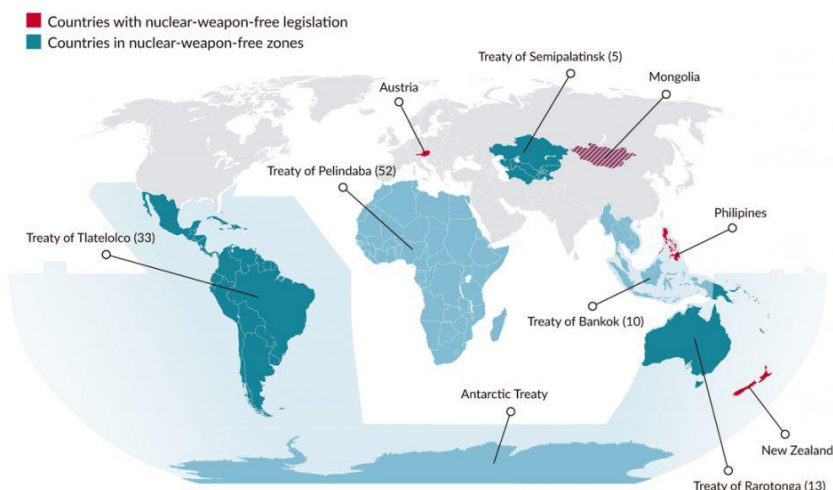
नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि

खबर में क्यों है?

- हाल में, नाभिकीय हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली संधि 'नाभिकीय हथियार निषेध संधि' लागू हो गई।

नाभिकीय हथियारों पर निषेध संधि के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र आमसभा ने 2017 में नाभिकीय हथियार निषेध संधि को स्वीकृति प्रदान कर दी थी।
- इस संधि में किसी भी प्रकार की नाभिकीय हथियार गतिविधियों में भागीदारी पर निषेध के समग्र नियम शामिल हैं।
- इसमें विकास, परीक्षण, उत्पादन, पाने, रखने, जखीरा तैयार करने, प्रयोग अथवा नाभिकीय हथियारों के प्रयोग की चेतावनी देने से रोकने का दायित्व भी शामिल है।



संधि की खास विशेषताएं

- इस संधि में राष्ट्रीय सीमाक्षेत्र में नाभिकीय हथियारों की तैनाती और निषेध वाली गतिविधियों को करने में किसी देश को सहायता देने का प्रावधान भी शामिल है।
- देशों का यह भी दायित्व होगा कि वे इस संधि के अंतर्गत देश के लिए प्रतिबंधित किसी गतिविधि को रोके और उनको दबायें जिसे उनके अधिकारक्षेत्र अथवा नियंत्रण वाले क्षेत्र में किसी व्यक्ति अथवा क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है।
- यह संधि भागीदारी देशों का यह भी दायित्व तय करती है कि वे नाभिकीय हथियारों के प्रयोग अथवा परीक्षण द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराएं।
- देशों को अपने अधिकारक्षेत्र अथवा नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्रों में आवश्यक एवं उपयुक्त पर्यावरणीय उपचार उपायों को करें जिससे नाभिकीय हथियारों के परीक्षण एवं प्रयोग से संबंधित गतिविधियों की वजह से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
- गैर-नाभिकीय हथियार वाले देश के लिए जरूरी है कि वे कम से कम किसी भविष्य के अतिरिक्त समझौते के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ एक समय सुरक्षा समझौता करें।

भारत का नाभिकीय हथियार निषेध संधि पर मत

- भारत का कहना है कि वह नाभिकीय हथियार निषेध संधि को समर्थन नहीं देता है।
- भारत का विश्वास है कि इस संधि से पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कानून का न तो विकास होता है और ना ही इसमें इसका कोई योगदान है। साथ ही यह किसी नये मानक अथवा कानून को भी नहीं बनाता है।
- भारत निशस्त्रीकरण पर सम्मेलन में समग्र नाभिकीय हथियार संधि के लिए बातचीत की शुरुआत का पक्षधर है।

नाभिकीय निशस्त्रीकरण पर वैश्विक प्रयास

- परमाणु हथियार अप्रसार संधि (NPT), समग्र नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) और नई START संधि (संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी गणराज्य के मध्य) नाभिकीय निशस्त्रीकरण की ओर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वैश्विक प्रयासों में से कुछ हैं।

नोटः

- भारत ने नाभिकीय हथियार अप्रसार संधि और समग्र नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II-अंतरराष्ट्रीय संगठन
स्रोत- द हिंदू

UNSC को प्रभावी होने के लिए समावेशी सुधार जरूरी

खबर में क्यों है?

- हाल में भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के जटिल मामलों को सुलझाने में ज्यादा से ज्यादा अपने को अक्षम पा रही है क्योंकि इसके पास उन लोगों का समावेश नहीं है जिन्हें इस वैश्विक निकाय के शक्तिशाली अंग के सदस्य बनने की जरूरत है।
- भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तुरंत सुधार और विश्व निकाय के 15 सदस्यीय सर्वोच्च अंग के सुधरे हुए रूप के लिए दवाब बना रहा है।



संयुक्त राष्ट्र सुधारों की जरूरत

- 1993 से, संयुक्त राष्ट्र आमसभा ने परिषद में सुधार पर गर्म चर्चाएं की हैं लेकिन किसी समझौते पर नहीं पहुँच सकी है।

ये कारक हैं:

असमानता

- 1945 में अपने जन्म के ही समय से सुरक्षा परिषद की सदस्यता में काफी कम परिवर्तन हुआ है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की संख्या लगभग चार गुनी हो गई है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप और ब्राजील, भारत, जर्मनी और जापान वाले जी-4 समूह से एक भी स्थाई सदस्य नहीं शामिल है।

अलगावपन

- स्थाई और गैर-स्थायी सीटों के बीच में अंतर बहुत ही असमान और अक्षम सुरक्षा परिषद को उत्पन्न करता है।
- पांच स्थाई सदस्य (P-5)- ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन- के पास स्थाई सीटें हैं और वीटो का विशेषाधिकार भी है जबकि गैर-स्थायी सदस्यों का दर्जा निचला है।
- अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सुरक्षा परिषद का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। यह सोमालिया, बोस्निया और रवांडा में अपने कार्यों में असफल रहा है।

रुकी हुई अंतरसरकारी बातचीत (IGN)

- अंतरसरकारी बातचीत ढांचा (IGN) संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक समूह है जोकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को देखता है, लेकिन इसने 2009 से कोई प्रगति नहीं की है जब इसकी स्थापना की गई थी।

जी-4 समूह

- जी-4 समूह ने भी तुरंत सुधार का आह्वान किया है जिससे अंतरसरकारी बातचीत में आमसभा की प्रक्रिया के नियमों में पारदर्शिता और अनुप्रयोग बनाए रखा जाए।

इजुल्विनी आम सहमति और सितें घोषणा

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए समान अफ्रीकी स्थिति को इजुल्विनी आम सहमति और सितें घोषणा के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, दोनों ही अफ्रीकी देशों को कम से कम दो स्थाई और 5 से 2 गैर स्थाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीटें देने का आह्वान करते हैं।
- इजुल्विनी आम सहमति और सितें घोषणा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर समान अफ्रीकी स्थिति को बताते हैं, को 2005 में अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन द्वारा स्थापित किये गए संयुक्त राष्ट्र सुधार पर समिति द्वारा विकसित किया गया है।

संबंधित सूचना

जी-4 समूह के बारे में

- यह चार देशों का एक समूह है जिसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। इसका प्राथमिक लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्य सीट हासिल करना है।

काँफी क्लब

- यह एक आंदोलन है, जिसे आम सहमति पर एक होना कहते हैं।
- इसे 1990 के दशक के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सीटों के संभावित विस्तार के विरोध में विकसित किया गया था।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संगठन

स्रोत- द हिंदू

केर्न ने कर मामले में विदेश में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने की धमकी दी

खबर में क्यों है?

- हाल में, यूनाइटेड किंगडम आधारित केर्न इनर्जी मेजर ने भारतीय सरकार को सुनिश्चित किया है कि वह विश्व की अलग-अलग राजधानियों में बैंक खातों सहित संपत्तियों को उसी समय फ्रीज करेगा यदि भारत \$1.2 अरब के एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण फैसले की भुगतान की मात्रा की चर्चा करने में असमर्थ रहता है।
- यह पूर्व प्रभावी करारोपण मामले में भारत के खिलाफ हानियों के दौरान हुआ है।

पृष्ठभूमि

- हेग में स्थाई मध्यस्थता न्यायालय के तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण जिसने यह निर्णय 21 दिसंबर, 2020 को दिया है, ने केर्न के पक्ष में आम सहमति से और भारत के खिलाफ यह निर्णय दिया है कि लगाया गया कर द्विपक्षीय निवेश समझौते के खिलाफ है।
- इसने यह भी निर्णय दिया कि केर्न को \$1.2 अरब हानियों के लिए दिये जाएं क्योंकि कर प्राधिकरण ने निर्णय दिया था बल के द्वारा कंपनी के शेयरों को बेचा जाए और डेविडेंड भुगतानों और साथ ही कर पुनर्वापसी को फ्रीज किया जाए, जिससे विवादित कर राशि को वापस लिया जा सके।



विचार के अंतर्गत संपत्तियां

- पहले से ही विचार के अंतर्गत संपत्तियों को दूतावास बैंक खाते, गैर कूटनीतिक परिसरों, एयर इंडिया जहाजों और कई स्थानों जिनमें यूनाईटेड किंगडम, हालैंड, फ्रांस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, के कई स्थान में राज्य स्वामित्व वाले समुद्री जहाजों में शामिल किया जा सकता है।
- यह कदम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) जहाज को जब्त करने जैसे कदम के समान ही होगा जिसे मलेशिया में इस महीने के पूर्व में जब्त किया गया है। इसका कारण आयरिश कंपनी के खिलाफ एक विवाद था, अथवा एक वेनेजुएलियाई जहाज की जब्ती जिसे 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी कोनोको फिलिप्स के पक्ष में न्यायालय ने निर्णय दिया था।
- केन ने यूनाईटेड किंगडम-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि, UNCIRTAL मध्यस्थता नियमों और न्यूयार्क संधि के अनुच्छेदों का भी उदाहरण दिया जिसपर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं।

संबंधित सूचना

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के बारे में

- इसकी स्थापना 1899 में द नीदरलैंड्स के हेग में प्रथम अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन में की गई थी।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता को सुगम बनाना है।

PCA की संरचना

- इसमें एक प्रशासनिक परिषद और एक अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो शामिल हैं।
- न्यायालय की प्रकृति स्थाई नहीं है, बल्कि यह एक न्यायालय है जिसमें मध्यस्थता के स्थाई पैनल में से चुना गया है।
- प्रत्येक सदस्य चार व्यक्तियों को नामांकित करने का अधिकारी है जिनकी अंतरराष्ट्रीय कानून में सक्षमता है और जिनकी नैतिक ख्याति ऊंची है और वे एक मध्यस्थ के कर्तव्य को स्वीकार कर सकते हैं।
- कुल 225 मध्यस्थ हैं, जिन्हें छह वर्षों के काल के लिए नियुक्त किया जाता है।
- प्रशासनिक परिषद में द हेग से मान्यता प्राप्त संविदा वाले पक्ष के कूटनीतिक प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- नीदरलैंड के विदेश मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संगठन+अंतरराष्ट्रीय संबंध

स्रोत- द हिंदू

अमेरिका-तालिबान समझौता

खबरों में क्यों है?

- बिडेन प्रशासन ने हाल ही में कहा है कि वह अमेरिकी-तालिबान समझौते की समीक्षा करेगी और यह देखेगी कि तालिबान अपने वायदे को कितना निभाया है।



पृष्ठभूमि

- इस समझौते पर फरवरी 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसका उद्देश्य "अफगानिस्तान में शांति लाना" है।
- इस समझौते का उद्देश्य अमेरिका और नाटो को अपने सैनिकों को वापस बुलाने में सक्षम बनाना था, जोकि तालिबान की लंबे समय से मांग थी।

समझौते के बारे में जानकारी

- चार पन्नों के इस समझौते पर अफगानिस्तान शांति के लिए अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि **ज़ाल्मे खलीलज़ाद** और तालिबान के राजनीतिक प्रमुख **मुल्ला अब्दुल गनी बरादर** के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
- समझौते में कहा गया है कि अंतर-अफगान वार्ता एवं विचार-विमर्श उद्देश्य में एक स्थायी और व्यापक युद्ध-विराम पर बात होगी।
- अंतर-अफगान वार्ता प्रतिभागी संयुक्त कार्यान्वयन तंत्र सहित एक स्थायी और व्यापक युद्ध विराम की तारीख और उसके प्रारूप पर चर्चा करेंगे।

अमेरिका-तालिबान समझौते का महत्व

- इस समझौते के महत्वपूर्ण तत्वों में अमेरिकी सैनिकों की वापसी शामिल है और समझौते के हस्ताक्षर के 14 महीने के भीतर नाटो या गठबंधन सेना की कम किया जाएगा।
- तालिबान द्वारा मुख्य आतंकवाद-रोधी प्रतिबद्धता यह है कि वह अल-कायदा सहित अपने किसी भी सदस्य, व्यक्तियों या समूहों को संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान की मिट्टी का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

- इसमें अन्य तत्वों में तालिबान नेताओं पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाना, दोनों ओर से बंदियों को रिहा किया जाना और युद्ध पर विराम लगाया जाना शामिल है।
- यह संयुक्त घोषणा अफगानिस्तान सरकार के लिए एक प्रतीकात्मक प्रतिबद्धता है कि अमेरिका उसे नहीं छोड़ रहा है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II-अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

अमेरिकी-फिलिस्तीन संबंध पुनःबहाल होने पर, रूस ने पश्चिमी एशिया वार्ता का रुख किया

खबरों में क्यों है?

- रूस ने हाल ही में पश्चिम एशिया शांति सम्मेलन के लिए एक फिलिस्तीनी प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि इसे वसंत या गर्मियों में मंत्री स्तर पर आयोजित किया जा सकता है। अमेरिका ने कहा कि वह जो बाइडेन के नेतृत्व में फिलिस्तीन के साथ संबंधों को पुनःबहाल करेगा।

साझेदार

- इसमें लगभग 10 साझेदार इजराइल, फिलिस्तीन, पश्चिम एशिया राजनयिक चौकड़ी के चार सदस्य (रूस, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ) और चार अरब राज्य - बहरीन, मिस्र, जॉर्डन और यूएई शामिल होंगे।

संबंधित जानकारी

पश्चिम एशिया शांति योजना

- पश्चिम एशिया शांति योजना का अनावरण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने किया था जिसका उद्देश्य इजरायल द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा करना था जिसमें "अविभाजित राजधानी" के रूप में यरूशलेम तक फैला हुआ राज्य और भावी फिलिस्तीन राज्य पर एक कड़ा सुरक्षा नियंत्रण शामिल है।

क्या है योजना?

- ट्रम्प की योजना संघर्ष के अधिकांश विवादास्पद मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करना है जैसे कि इजराइल की सीमा, फिलिस्तीनी शरणार्थियों की स्थिति, पश्चिमी किनारे पर यहूदी बस्तियां, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच भूमि की अदला-बदली, यरूशलेम के साथ इजराइल की सुरक्षा से जुड़ी चिंता।
- फिलिस्तीनी शरणार्थी, जिन्हें 1948 के अरब-इजरायल युद्ध के दौरान अपने घरों से बाहर निकाला गया था, जिससे ऐतिहासिक फिलिस्तीन में इजरायल राज्य बना, उन्हें वापस जाने की अनुमति नहीं होगी।
- वे भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य में जा सकते हैं, मेजबान देशों की नागरिकता ले सकते हैं या अन्य क्षेत्रीय देशों में बस सकते हैं।

ओस्लो समझौता

- ओस्लो समझौते के अनुसार, वेस्ट बैक तीन क्षेत्रों में विभाजित था, और उनमें से केवल एक ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सीधे नियंत्रण में है।
- योजना में वेस्ट बैक यहूदी बस्तियों के इजरायल के आक्रमण हेतु कुछ भूमि अदला-बदली का प्रस्ताव है।
- यह गाजा को बढ़ाने और एक सुरंग के माध्यम से वेस्ट बैक के साथ पट्टी को जोड़ने का प्रयास करता है।
- गाजा के करीब इजरायल के दक्षिण-पूर्व में अरब शहर, भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य का हिस्सा बन सकते हैं।

फिलिस्तीन के लिए इस समझौते के मायने

- फिलिस्तीन की स्थिति 1967 की सीमा पर आधारित एक स्वतंत्र, संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य का गठन करके दुनिया की अधिकांश शक्तियों द्वारा समर्थित है।
- इसका अर्थ है वेस्ट बैक और पूर्वी यरुशलम के साथ गाजा पट्टी जो ओल्ड सिटी सहित अपनी राजधानी है जिसमें हरम उमेश-शरीफ शामिल हैं, जिसे टेम्पल माउंट के रूप में भी जाना जाता है, जो मुस्लिमों और यहूदियों दोनों के लिए एक पवित्र स्थल है।
- फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी के अधिकार जैसे मुद्दों को अंतिम बातचीत में सुलझाया जाएगा।
- लेकिन अमेरिका ने फिलिस्तीनी दावों को एकमुश्त प्रभावी रूप से खारिज कर दिया है और उनसे और अधिक समझौते करने को कहा है।
- वह इजरायल को यरुशलम और लगभग 30% वेस्ट बैक देना चाहता है और उसने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के वापसी के अधिकार को खारिज किया है।
- फिलिस्तीनियों को आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जेल में बंद इजराइल द्वारा मारे गए या मारे गए फिलिस्तीनी परिवारों का समर्थन करना बंद करना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कब्जे पर सवाल उठाने से बचना चाहिए।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- द हिंदू

रूस ने START संधि का विस्तार करने की अनुमति दी

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में रूस के विधि निर्माताओं ने पांच साल की अवधि के लिए नई START संधि के विस्तार को मंजूरी दी है।

नई START संधि के बारे में

- यह सामरिक आक्रामक हथियारों को कम और सीमित करने के उपायों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच एक संधि शर्त है।
- यह **5 फरवरी 2011** को प्रभाव में आयी थी।



- नई START ने 1991 **START I संधि** की जगह ली है, जो दिसंबर 2009 को समाप्त हो गई, और 2002 की रणनीतिक आक्रामक कटौती संधि (SORT) का स्थान लिया था, जिसे नई START नीति प्रभाव में आने से स्थगित किया गया था।
- यह 1991 के START फ्रेमवर्क (शीत युद्ध के अंत में) का अनुवर्ती है, जो दोनों पक्षों को 1,600 रणनीतिक डिलीवरी वाहनों और 6,000 वॉरहेड तक सीमित करता है ।

संधि की शर्तों

- कई रणनीतिक परमाणु मिसाइल लांचर आधे से कम हो जाएंगे।
- SORT तंत्र की जगह एक नया निरीक्षण और सत्यापन शासन स्थापित किया जाएगा।
- तैनात रणनीतिक परमाणु वारहेड की संख्या 1,550 तक सीमित है।
- तैनात और गैर-तैनात अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) लांचर, पनडुब्बी-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल (एसएलबीएम) लांचर, और परमाणु आयुध से युक्त भारी बमवर्षक की संख्या 800 तक सीमित होगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- द हिंदू

कार्य की संयुक्त समग्र योजना

खबर में क्यों है?

- हाल में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकेन ने प्रशासन की स्थिति की पुष्टि की कि यदि ईरान बेकार पड़े संयुक्त समग्र कार्ययोजना (JCPOA अथवा ईरान समझौते) की शर्तों का अनुपालन करने के लिए तैयार है, तो संयुक्त राज्य एक बार फिर से इसमें शामिल हो जाएगा।
- ट्रंप प्रशासन 2018 में इससे बाहर आ गया था।

संयुक्त समग्र कार्ययोजना के बारे में

- ईरान नाभिकीय समझौते पर 2015 में (अथवा संयुक्त समग्र कार्ययोजना (JCPOA)) ईरान और पी5, प्लस जर्मनी और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किये थे।
- पी5, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्य हैं (संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम)।
- इस समझौते का लक्ष्य ईरान के नाभिकीय कार्यक्रम को रोकना था।

समझौते के अंतर्गत:

- ईरान का अधिकांश प्रसंस्कृत यूरेनियम देश के बाहर भेज दिया गया और इसकी एक भारी जल सुविधा प्रचालन की अवस्था में नहीं है।
- इसके बदले में प्रचालन की अवस्था वाली नाभिकीय सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय जांच के दायरे में लाया गया, इस समझौते में ईरान पर से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने की बात कही गई थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों समझौते से हटा?

- ट्रंप और समझौते के विरोधियों का कहना है कि यह एकपक्षीय है क्योंकि यह ईरान की अरबों डॉलर की पहुँच बनाता है लेकिन हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों जिन्हें अमेरिका आतंकवादी मानता है, के मामले को नहीं देखता है।
- उनका कहना है कि यह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल विकास पर रोक नहीं लगाता है और यह समझौता 2030 तक के लिए ही है।
- उनका कहना है कि ईरान ने पूर्व में अपने नाभिकीय कार्यक्रम के बारे में झूठ बोला था।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संबंध

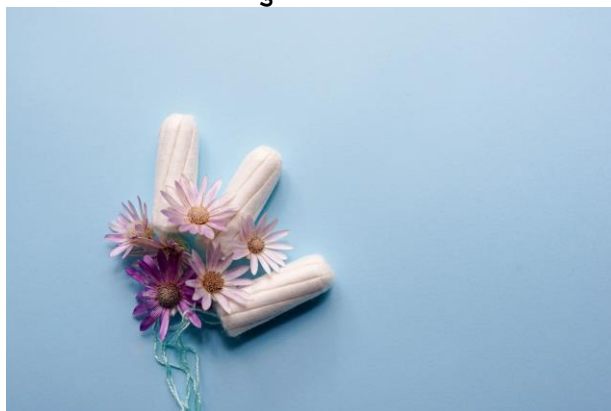
स्रोत- द हिंदू

आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे

टैम्पन कर

खबर में क्यों है?

- हाल में, यूनाईटेड किंगडम ने 2021 की शुरुआत टैम्पन कर की समाप्ति के साथ की।



पृष्ठभूमि

- 31 दिसंबर तक, यूनाईटेड किंगडम यूरोपीय संघ का हिस्सा था, जहां मासिक धर्म उत्पाद जैसे सैनेटरी नैपकिन और टैम्पन को गैर-जरूरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और सदस्य देशों को इन पर 5 प्रतिशत कर लगाने की आवश्यकता होती है।
- अब यूनाईटेड किंगडम 27 देशों के ब्लॉक से अलग हो चुका है और इसके दिशा-निर्देशों से नहीं बंधा हुआ है जिसके अंतर्गत 1973 से सैनेटरी उत्पादों पर पांच विभिन्न VAT दरें लगती हैं।
- 2015 में, कंजर्वेटिव पार्टी सरकार ने एक टैम्पन कर कोष की स्थापना की थी जिसने मासिक धर्म के उत्पादों पर VAT से उत्पन्न कोषों को कमजोर महिलाओं और लड़कियों को सहायता देने वाली परियोजनाओं के लिए आवंटित किया था।

टैम्पन कर के बारे में

- यह महिलाओं के सैनेटरी उत्पादों पर 5 प्रतिशत मूल्य वर्धित कर (VAT) है।

इस प्रकार के कर समाप्त करने वाले देश

- यूनाईटेड किंगडम अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने पहले से ही यह कर समाप्त कर दिया है, जिनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल हैं।
- यह यूनाईटेड किंगडम सरकार के वृहद प्रयास का हिस्सा है जिसे 'एंड पीरियड पावर्टी' कहते हैं।
- स्कॉटलैंड जो यूनाईटेड किंगडम का हिस्सा है, ने नवंबर 2020 में दुनिया का पहला देश बन कर इतिहास रच दिया जब उसने जरूरतमंद लोगों के लिए मासिक धर्म उत्पादों को मुफ्त कर दिया।

टैम्पन कर की समाप्ति का महत्व

- ब्रिटिश सरकार का आकलन है कि टैम्पन कर के हटाने के कदम से एक औसत महिला को अपने जीवनकाल में लगभग 40 पाउंड बचाएगी।
- टैम्पन करों के हटाने से गैरबराबरी कर बोझ भी हट गया है और इससे मासिक धर्म स्वच्छता उत्पाद निम्न आय वर्ग वाले उपभोक्ताओं के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सामाजिक मामले और स्वास्थ्य

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

फेसलेस कर योजना

खबर में क्यों है?

- हाल में केंद्र सरकार ने आयकर आकलन में ज्यादा पारदर्शिता, सामर्थ्य, और जवाबदेही तय करने के लिए फेसलेस आकलन योजना की शुरुआत की है।

पृष्ठभूमि

- 2019 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने फेसलेस ई-आकलन योजना की शुरुआत का प्रस्ताव रखा था।
- इस योजना का उद्देश्य करदाता और आयकर विभाग के बीच में मानव इंटरफेस को समाप्त करना है।
- यह योजना प्रक्रिया तय करती है जिससे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फेसलेस आकलन को किया जा सके।
- 13 अगस्त 2020 से, 2019 की ई-आकलन योजना संशोधित हो गई है और अब इसका नाम फेसलेस आकलन योजना है।

फेसलेस कर योजना के बारे में

- फेसलेस आकलन योजना केवल जांच आकलन और सर्वश्रेष्ठ न्याय आकलन पर ही लागू होती है।

उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य जहां तक संभव हो भौतिक मेलमिलाप को समाप्त करना है, और इसलिए, करदाताओं को यह अवसर मिल सकता है कि वे व्यक्तिगत तौर पर व्यवसाय से संबंधित जटिलताओं को बताएं। साथ ही आयकर रिटर्न को भरते समय उन्होंने कौन सी विभिन्न स्थितियां ली हैं, इसके बारे में भी बताएं।
- यह योजना उपयुक्त मामलों की अनुमति देती है जहां एक निश्चित सुनवाई जरूरी है, जिससे, प्रोटोकाल का पालन करने के बाद, एक सुनवाई का अवसर दिया जाता है।

फेसलेस आकलन के अंतर्गत, आयकर कानून, 1961 के अंतर्गत सभी प्रावधान लागू किये जाते समय निम्न को लागू किये जाते हैं-

- आकलन करने वाले अधिकारी और आकलन किये वाले व्यक्ति के बीच में इंटरफेस को समाप्त करना जो कि प्रक्रियाओं के दौरान होगा। यह उस दायरे तक होगा जोकि तकनीकी रूप से संभव है;
 - अर्थव्यवस्थाओं के परिमाण और कार्यात्मक विशेषज्ञता के द्वारा संसाधनों के उपयोग को अनुकूलतम करना; और
 - उचित अधिकार क्षेत्र के साथ करीबी मूल्य के टीम आधारित निर्धारण को लागू करना
- लेकिन, कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन) विधेयक, 2020 के अनुसार, फेसलेस आकलन अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आयकर कानून, 1961 के अन्य प्रावधानों को लायेगा।

नोट:

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) फेसलेस आकलन जैसे कि क्षेत्र, व्यक्ति, व्यक्तियों का वर्ग, आय, आय के वर्ग, मामले, मामलों के वर्ग के दायरे का निर्णय करता है, जिनपर यह फेसलेस आकलन लागू होता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

सागरमाला सीप्लेन सेवाएं (SSPS)

खबर में क्यों है?

- हाल में, बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय सागरमाला सीप्लेन सेवाओं (SSPS) के अपने महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करने जा रही है।

सागरमाला सीप्लेन सेवा (SSPS) के बारे में

- परियोजना का उद्देश्य कुछ चुने हुए मार्गों पर सीप्लेन सेवाओं के प्रचालन को शुरू करने का है। यह कार्य भावी एयरलाइन प्रचालकों के द्वारा विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) ढांचे के अंतर्गत किया जाएगा।
- इस परियोजना का निष्पादन और क्रियान्वयन सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड (SDCL) के द्वारा होगा जोकि जहाजरानी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है।



हब और स्पोक मॉडल के अंतर्गत प्रस्तावित मूल-गंतव्य युग्म में शामिल हैं:

- अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीप
- असम में गुवाहाटी रिवरफ्रंट एवं उमरांसो जलाशय
- यमुना रिवरफ्रंट/ दिल्ली (केंद्र के रूप में) से अयोध्या, टेहरी, श्रीनगर (उत्तराखंड), चंडीगढ़ और पंजाब व हिमाचल प्रदेश के कई पर्यटन स्थल
- मुंबई (केंद्र के रूप में) से शिरडी, लोनावला, गणपतिपुले
- सूरत (केंद्र के रूप में) से द्वारिका, मांडवी एवं कांडला, खिंडसी बांध, नागपुर एवं इराई बांध और चंद्रपुर (महाराष्ट्र में)

विशेष उद्देश्य वाहन (SPV)

- “सागरमाला सीप्लेन सेवा (SSPS)” के संयुक्त विकास और प्रचालन को विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) का निर्माण करके किया जाएगा। यह सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड (SDCL) के साथ होगा।

महत्व

- सीप्लेन सेवा विभिन्न दूरस्थ धार्मिक/पर्यटन स्थानों को वायु कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी।
- यह यात्रा के समय में कटौती करेगी और स्थानीय लघु दूरी यात्रा को बढ़ावा देगी विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा नदियों/झीलों के आरपार। साथ ही यह पर्यटन और व्यवसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी।
- यह रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी और इन नये स्थानों में पर्यटन को बढ़ावा देगी जोकि दीर्घावधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान देंगे।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अवसंरचना

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

विश्व बैंक के अनुसार 2021-22 में वैश्विक और भारत के उत्पादन में होगा विस्तार

खबर में क्यों है?

- विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना (GEP) रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 2021 में 4% की वृद्धि होने की संभावना है। इसमें पूरे वर्ष के दौरान कोविड-19 टीके के वृहद स्तर पर रोल आउट को मान कर चला जा रहा है।



रिपोर्ट की प्रमुख खास बातें

भारत के नेतृत्व में दक्षिण एशिया में मंदी

- दक्षिण एशियाई क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के महामारी की वजह से 2020 में 6.7% तक संकुचित होने की संभावना है।
- इसकी वजह भारत की गहरी मंदी रही, जहां अर्थव्यवस्था पहले से ही गैर-बैंक वित्तीय निगमों में तनाव की वजह से कमजोर हो गई थी।
- भारत के वित्त वर्ष 2021-22 में 5.4% की रफ्तार से और वित्त वर्ष 2022-23 में 5.2% की रफ्तार से वृद्धि की संभावना है। जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में संभावित संकुचन 9.6% है।

Five Agencies — One Group



भारत के संकुचन के पीछे कारण

- वर्तमान वित्त वर्ष में भारत के संभावित संकुचन के कारण घरेलू खर्च और निजी निवेश में जबर्दस्त गिरावट आई है।

आय हानि

- अनौपचारिक क्षेत्र में जबर्दस्त आय हानि हुई है जोकि रोजगार का 4/5 है।

नाटकीय असमानता

- गिरावट की असमानता और संभावित पुनर्वापसी नाटकीय है।
- अर्थव्यवस्था में गिरावट से सबसे ज्यादा नुकसान निम्नतम आय वर्ग वालों को हुआ और कोविड-19 बाद की अर्थव्यवस्था में नौकरियों को वापस पाने, स्वास्थ्य देखभाल, टीकों में सबसे ज्यादा देर इन्हीं को होगी।
- इसके विपरीत जिनके पास नौकरी की सुरक्षा है, और जो आय वर्ग में सबसे ऊपर हैं, वे अपनी संपत्तियों के लिए बड़े सरकारी और केंद्रीय बैंक समर्थन के प्रत्यक्ष लाभकर्ता रहे।

वैश्विक ऋण स्तरों में जबर्दस्त वृद्धि

- वैश्विक ऋण स्तरों में जबर्दस्त वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण उभरते हुए बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDE) के साथ महामारी है। 2020 में सरकारी ऋण में 9 प्रतिशत बिंदुओं की वृद्धि होने की संभावना है।
- दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई, जिसमें भारत के सरकारी ऋण के सकल घरेलू उत्पाद के 17 प्रतिशत बिंदुओं तक बढ़ने की संभावना है जबकि सेवा उत्पादन में 9% से ज्यादा का संकुचन देखा गया।

संबंधित सूचना

विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्ट

- व्यवसाय करने की सुगमता
- विश्व विकास रिपोर्ट
- बहुआयामी गरीबी सूचकांक
- मानव पूंजी सूचकांक
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन रिपोर्ट
- लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक
- वैश्विक आर्थिक संभावनाएं

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

सरकार ने भारतीय रेलवे माल व्यवसाय विकास पोर्टल की शुरुआत की

खबर में क्यों है?

- रेल मंत्रालय ने माल व्यवसाय विकास पोर्टल की शुरुआत की है।



माल व्यवसाय विकास पोर्टल के बारे में

- यह रेलवे माल व्यवसाय को बढ़ावा देने और विकास करने के लिए अलग पोर्टल है।

मुख्य विशेषताएं

- माल पोर्टल यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रचालन ग्राहक केंद्रित रहें, लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने वालों के लिए लागत कम हो, आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा उपलब्ध हो और वस्तुओं के परिवहन के प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाए।
- इसको भौतिक प्रक्रियाओं को ऑनलाइन से विस्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे मानव से मानव अन्योन्य क्रिया की जरूरत न्यूनतम की जा सके।

ग्राहकों को लाभ

- इस पोर्टल को सभी वर्तमान और नए ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और विकसित किया गया है जिसका मुख्य जोर व्यवसाय करने की सुगमता पर है, पारदर्शिता लाने पर है और पेशेवर समर्थन देने पर है।

प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन की ओर एक कदम

- यह नया पोर्टल प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन की ओर एक बड़ा कदम है और यह ना केवल माल प्रचालन की सुगमता में सुधार करेगा बल्कि साथ ही लागतों को कम करने में भी समक्ष होगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

वित्त वर्ष 21 में सरकार की सकल घरेलू उत्पाद के 7.7% संकुचन की संभावना

खबर में क्यों है?

- सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किये हैं।



प्रथम अग्रिम अनुमान क्या हैं (FAE)?

- किसी वित्त वर्ष के लिए, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय सकल घरेलू उत्पाद का नियमित अनुमान उपलब्ध कराता है।
- ऐसा प्रथम उदाहरण प्रथम अग्रिम अनुमान है।
- किसी विशेष वित्त वर्ष के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान 7 जनवरी को प्रस्तुत किया जाता है।

महत्व

- इसका महत्व इस तथ्य में है कि वे सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान हैं जिनका प्रयोग केंद्रीय वित्त मंत्रालय अगले वित्त वर्ष के बजट आवंटनों के निर्णय के लिए करता है।
- यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार ही है जिसने देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के वृद्धि अनुमान 2020-21 के लिए -7.5% किये हैं, जबकि इसका पूर्व में अनुमान -9.5% का था।

विधि का प्रयोग

- FAE बेंचमार्क संसूचक विधि पर आधारित हैं।
- क्षेत्रवार अनुमान संसूचकों के बहिर्वेशन के द्वारा प्राप्त किये जाते हैं जैसे:
 - वित्त वर्ष के पहले सात महीनों के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)।
 - निजी कार्पोरेट क्षेत्र में अधूसूचित कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन जोकि सितंबर 2020 को समाप्त हो रही तिमाही तक उपलब्ध हैं।
 - फसल उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान,
 - केंद्रीय और राज्य सरकारों के खातों,
 - जमाओं और ऋणों, रेलवे की यात्री और माल भाड़े से प्राप्तियां, नागरिक उड्डयन द्वारा हैंडल किये गये यात्री और माल, प्रमुख समुद्री बंदरगाहों पर हैंडल किया गया माल, व्यावसायिक वाहनों की बिक्री, इत्यादि जैसे संसूचकों पर सूचना वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों के लिए उपलब्ध।

प्रथम अग्रिम अनुमान की प्रमुख खास बातें

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर

- भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के 2020-21 में 7.7% तक संकुचित होने का अनुमान है, जबकि इसकी तुलना में वृद्धि दर 2019-20 में 4.2% थी।

- भारत 1979-80 के बाद कोविड 10 महामारी की वजह से ऋणात्मक GDP (सकल घरेलू उत्पाद) देखेगा।

सकल मूल्य वर्धन (GVA)

- यह आपूर्ति पक्ष की तरफ से अर्थव्यवस्था की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा मूल्य वर्धन का नक्शांकन करता है जैसे कि कृषि, उद्योग और सेवाएं। वास्तविक सकल मूल्य वर्धन 7.2% तक संकुचित होगा।

धनात्मक वृद्धि

- इस वर्ष केवल दो क्षेत्रों के सकल मूल्य वर्धन में वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है।
- कृषि (3.4%) और बिजली, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगिता सेवाएं (2.7%) पूर्वार्ध से उत्तरार्ध तक लगातार मजबूत स्थिति में हैं।
- लेकिन, महामारी से प्रभावित वर्ष में सबसे बड़ी गिरावट सेवा क्षेत्र में आने की है।

निजी अंतिम उपभोग खर्च (PFCE)

- वस्तुओं और सेवाओं की सबसे ज्यादा मांग उन निजी व्यक्तियों से आती है जो अपनी उपभोग जरूरतों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं।
- इस मांग को PFCE कहते हैं और यह कुल सकल घरेलू उत्पाद का 56% है। इसके लगभग उतना ही रहने की संभावना है जितना यह 2017-18 में था।

सकल निश्चित पूंजी निर्माण (GFCF)

- GDP के दूसरे सबसे बड़े घटक को GFCF कहते हैं और यह वस्तुओं और सेवाओं में सभी खर्चों का मापन करता है जिन्हें व्यवसाय और फर्म करती हैं जब वे अपने उत्पादक क्षमता में निवेश करती हैं।
- इस प्रकार की मांग भारत के GDP का लगभग 28% का हिस्सा है जोकि 2016-17 के स्तर से नीचे गिर चुका है।

सरकारी खर्च

- इसके वर्ष के उत्तरार्ध में 17% की मजबूत वृद्धि दिखलाने की आशा है, यह इसके बावजूद है कि सरकार ने राजकोषीय मजबूती पर चुनौतियों का सामना किया है और यह तथ्य कि सरकारी खर्च वर्ष के पूर्वार्ध में 3.9% तक गिरा है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू बिजिनेस लाइन

NCAVES इंडिया मंच-2021

खबर में क्यों है?

- हाल में, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा नेचुरल कैपिटल एकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज (NCAVES) इंडिया मंच-2012 का आयोजन किया जा रहा है।

NCAVES इंडिया मंच के बारे में

- इसका आयोजन सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

उद्देश्य

राष्ट्रीय मंच के उद्देश्य निम्न होंगे:

- प्राकृतिक पूंजी लेखांकन (NCA) के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रस्तुत करना
- भारत में NCA के लिए उभरते हुए अवसरों का प्राथमिकीकरण करना
- NCA के क्षेत्र में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा किये गए कार्य के साथ हितधारकों को परिचित करवाना, और
- चुने हुए अनुसंधान संस्थानों को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना जिससे पारितंत्र सेवाओं के मूल्यांकन में हुए अनुसंधान को प्रस्तुत किया जा सके।



संबंधित सूचना

NCAVES परियोजना के बारे में

- इस परियोजना की शुरुआत यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय विभाग (UNSD), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और जीववैज्ञानिक विविधता पर संधि के सचिवालय (CBD) द्वारा की गई है।
- भारत उन पांच देशों में से एक है जो इस परियोजना में भाग ले रहा है- अन्य देश हैं ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको।

वित्तीयन और अवधि

- इस परियोजना का वित्तीयन यूरोपीय संघ (EU) द्वारा किया जा रहा है और इसकी अवधि 2021 के अंत तक है।

भारत में परियोजना का क्रियान्वयन

- भारत में, NCAVES परियोजना का क्रियान्वयन MoSPI द्वारा पर्यावरण, वन और मौसम परिवर्तन मंत्रालय (MoFE&CC) और राष्ट्रीय दूरस्थ सेंसिंग केंद्र (NRSC) के साथ गठबंधन में की जा रही है।

भारत के लिए NCAVES परियोजना का महत्व

EnviStats India

- परियोजना में भागीदारी ने MoSPI को UN-SEEA ढांचे के अनुसार पर्यावरण खाते के संकलन को शुरू करने और 2018 से वार्षिक आधार पर "EnviStats India" के अपने प्रकाशन में पर्यावरणीय खाते को जारी करने में मदद दी है।

India-EVL Tool

- NCAVES परियोजना ने India-EVL Tool के विकास में भी मदद दी है जोकि मूल रूप से एक लुक अप टूल है जोकि विभिन्न पारितंत्र सेवाओं के मूल्यों का एक स्नैपशॉट देश के विभिन्न राज्यों में देता है, यह पूरे देश में लगभग कराए गए 80 अध्ययनों पर आधारित है।
- इस टूल का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि यह लिटरेचर पर एक महत्वपूर्ण दृष्टि प्रदान करता है जोकि उपलब्ध है और अनुमानों की अनुप्रयोगिता स्थानिक तौर पर पूरे भारत में जैव-भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

स्पेक्ट्रम की नीलामी

खबर में क्यों है?

- हाल में, दूरसंचार विभाग (DoT) ने घोषणा की कि 1 मार्च, 2021 से 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 में 4जी स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी की जाएगी।



स्पेक्ट्रम की नीलामी क्या है?

- सेलफोन और वायरलाइन टेलीफोन जैसे यंत्रों को एक दूसरे से जुड़ने के लिए संकेतों की जरूरत होती है।
- ये संकेत वायु तरंगों द्वारा पहुँचाये जाते हैं जिन्हें नामांकित आवृत्तियों में ही भेजना होता है जिससे किसी तरह के हस्तक्षेप से बचा जा सके।
- केंद्र सरकार देश की भौगोलिक सीमा के अंदर सभी सार्वजनिक उपलब्ध परिसंपत्तियों पर स्वामित्व रखती है, जिनमें वायु तरंगें भी शामिल हैं।
- सेलफोनों, वायरलाइन टेलीफोन और इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या में विस्तार के साथ, समय समय पर संकेतों को ज्यादा स्थान उपलब्ध कराने की जरूरत पड़ती है।
- इन परिसंपत्तियों को उन कंपनियों को बेचना जो एक तरफ से दूसरी तरफ इन तरंगों का परिवहन करने के लिए अवसंरचना की स्थापना करना चाहती हैं, केंद्र सरकार समय समय पर इनकी नीलामी DoT के द्वारा करती है।
- इन वायु तरंगों को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिन्हें बैंड्स में विभाजित किया जाता है जिनकी अलग आवृत्तियां होती हैं। यह सभी वायु तरंगें कुछ समय के लिए बेची जाती है, जिसके बाद उनकी वैधता समाप्त हो जाती है, जोकि सामान्यतया 20 वर्ष तय की जाती है।

अब क्यों स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा रही है?

- पिछली बार स्पेक्ट्रम की नीलामी 2016 की गई थी जब सरकार ने 2,354.55 मेगाहर्ट्ज आफर किये थे।
- हालांकि सरकार केवल 965 मेगाहर्ट्ज ही बेच पाई थी- अथवा जितना बिक्री के लिए तय किया गया था उसका 40% ही।
- नये स्पेक्ट्रम की नीलामी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कंपनियों द्वारा खरीदी गई वायु तरंगों की वैधता 2021 में समाप्त होने वाली है।

स्पेक्ट्रम के लिए कौन आगे आएगा?

- सभी तीनों निजी टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो इंफोकॉम, भारती एयरटेल और वाई पात्र उम्मीदवार हैं जो अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को खरीद सकते हैं जिससे उनके नेटवर्क पर बढ़ते हुए प्रयोगकर्ताओं को मदद मिले।
- इन तीनों के अतिरिक्त, नई कंपनियां, जिसमें विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं, भी वायु तरंगों को खरीदने के लिए पात्र हैं।
- विदेशी कंपनियां लेकिन, को या तो भारत में अपनी शाखा स्थापित करनी होगी और भारतीय कंपनी के रूप में पंजीकरण करवाना होगा अथवा किसी भारतीय कंपनी के साथ गठबंधन करना होगा जिससे उन्हें प्राप्त करने के बाद वे उसे अपने पास रख सकें।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अवसंरचना

स्रोत- द हिंदू

K-आकार की आर्थिक बहाली

खबर में क्यों है?

- हाल में, जे पी मॉर्गन में मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री ने कहा कि भारत और पूरे विश्व दोनों ही जगह कोविड से K-आकार की बहाली की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

K- आकार की बहाली क्या है?

- K- आकार की बहाली उस समय होती है जब एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्से अलग-अलग दरों से बहाल होते हैं।
- पिरामिड के उच्च शिखर वाले परिवारों की आय अधिकतम संरक्षित रहती है, लॉकडाउन के दौरान जबर्दस्ती थोपी गई बचत दरें भविष्य के उपभोग को प्रचालित करने के लिए ईंधन का काम कर रही हैं।
- इसी बीच में नीचे के परिवार को स्थाई तौर पर नौकरियों और आय की किल्लत देखनी पड़ सकती है।

K- आकार की बहाली के समिष्ट परिणाम

- भारत के ऊपरी 10 प्रतिशत परिवार देश के कुल उपभोग के 25-30 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं, कोई तर्क कर सकता है कि उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि अंदर दबी हुई मांग अपने को व्यक्त करेगी।
- ऊंची आय वाले परिवार दो तिमाही से ऊंची बचतों की वजह से लाभान्वित हो रहे हैं।

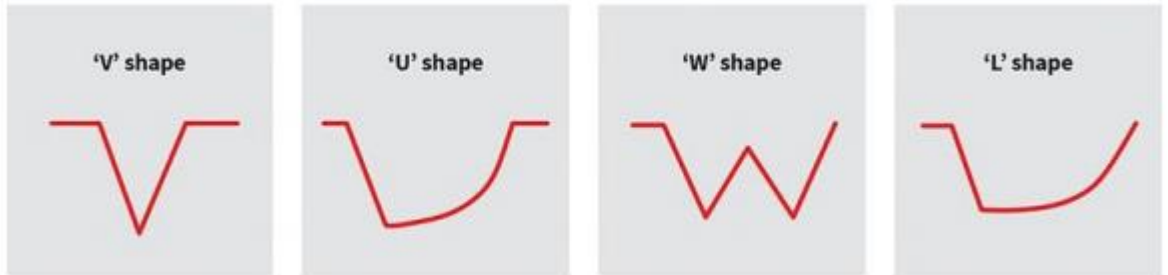
यह भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड के पहले से ही मंदी की ओर अग्रसर थी, और लॉकडाउन की वजह से यह समस्या कई गुना बढ़ चुकी है।

- एक Z- अथवा कम से कम V-आकार की बहाली सबसे ज्यादा मुफीद रहेगी।
- यदि नहीं तो हमें कम से कम U-आकार की बहाली अथवा स्क्वैश को प्राप्त करना होगा जिससे चंद वर्षों के दौरान हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
- आर्थिक बहाली के विभिन्न आकारों में हैं- Z, V, U, W, L, स्क्वैश और उल्टा वर्ग बहाली।

Z- आकार की बहाली

- यह सबसे ज्यादा आशावादी परिदृश्य है जिसमें अर्थव्यवस्था गिरने के बाद फीनिक्स की तरह से बढ़ती है।
- यह हानि से भी ज्यादा लाभ देती है सामान्य ट्रेड रेखा के पास पहुँचने के पहले (लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद रिवेंज बाईंग के बारे में सोचें), इससे Z- आकार का चार्ट बनता है।



V- आकार बहाली

- V आकार बहाली में, अर्थव्यवस्था जल्दी ही खोई हुई भूमि को प्राप्त कर लेती है और सामान्य वृद्धि पर वापस आ जाती है।

U- आकार बहाली

- यह नहाने के टब से मिलता-जुलता है, जिसमें अर्थव्यवस्था गिरने के बाद, संघर्ष करके थोड़े समय के लिए निम्न वृद्धि दर पर रहती है, बाद में वह धीरे-धीरे सामान्य स्तरों पर जाती है।

W- आकार बहाली

- यह काफी जोखिम भरी होती है- वृद्धि गिरकर उठती है, लेकिन फिर से गिरकर एक बार फिर पुनर्वापसी करती है, जिससे वह W-जैसा चार्ट बनाती है।
- W- आकार बहाली द्वारा निरूपित दोबार गिरावट के बारे में अर्थशास्त्री भविष्यवाणी कर रहे हैं यदि कोविड दुबारा वापसी करता है और प्रारंभिक बहाली केवल एक धोखा है।

L आकार बहाली

- यह सबसे ज्यादा खराब स्थिति है, जिसमें वृद्धि दर गिरने के बाद, निम्न स्तरों पर रहती है और लंबे समय तक पुनर्वापसी नहीं करती है।

स्क्वैश आकार बहाली

- यह नाइके के लोगो की तरह से है- जो V आकार और U आकार के बीच का है। यहां, गिरने के बाद, वृद्धि तेजी से बहाल होने लगती है लेकिन तब, बाधाओं की वजह से धीमी हो जाती है, बाद में धीरे-धीरे पुनर्वापसी करती है।

J आकार बहाली

- इसमें वृद्धि नीचे से तेजी से ऊपर जाती है और यह ट्रेंडलाइन से काफी ऊपर चली जाती है और वहां ठहर जाती है।

उल्टा वर्गमूल आकार बहाली

- इस परिदृश्य में जहां नीचे से थोड़ी पुनर्वापसी हो सकती है, वृद्धि दर धीमी हो जाती है और थोड़ी नीचे पहुँच जाती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

RBI पैनल डिजीटल उधार जोखिमों की जांच करेगा

खबर में क्यों है?

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजीटल उधार पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की है जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप शामिल हैं- इसके द्वारा विनियमित वित्तीय क्षेत्र में साथ ही गैर विनियमित खिलाड़ियों द्वारा डिजीटल उधार गतिविधियों के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा।

RBI कार्यकारी समूह के बारे में

- कार्यकारी समूह में दोनों ही आंतरिक और बाह्य सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता जयंत कुमार दास, कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाएगी।

कार्यकारी समूह के कार्य

- वे डिजीटल उधार गतिविधियों का मूल्यांकन करेंगे और RBI विनियमित संस्थाओं में आउटसोर्सड डिजीटल उधार गतिविधियों के मानकों और भेदन का आकलन करेंगे ;
- वित्तीय स्थिरता, विनियमित संस्थाओं और उपभोक्ताओं के गैर विनियमित डिजीटल उधार द्वारा पैदा किये गये जोखिमों की पहचान करना; और
- डिजीटल उधार की क्रमबद्ध वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए विनियामक परिवर्तनों के सुझाव देना।
- यह विशेष विनियामक अथवा वैधानिक परिमाण के प्रसार के लिए उपायों की अनुशंसा करेगा और विभिन्न विनियामक और सरकारी एजेंसियों की भूमिका का सुझाव देगा।
- यह डिजीटल उधार खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत उचित प्रथा संहिता की अनुशंसा भी करेगा।
- यह समूह तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

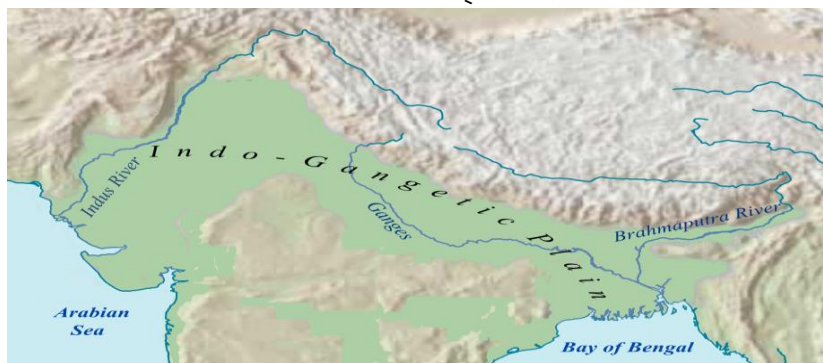
ILO ने 'घर से कार्य' पर राष्ट्रीय स्तर की नीति बनाने का आह्वान किया

खबर में क्यों है?

- अपनी नई रिपोर्ट में, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने घर आधारित कर्मचारियों के लिए प्रभावी नीति विकसित करने पर जोर दिया है और सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उसका ठीक से क्रियान्वयन किया जाए क्योंकि यह प्रथा नोवेल कोरोनावायरस रोग (COVID-19) महामारी के आने के बाद से बढ़ी है।

रिपोर्ट की खास बातें

- रिपोर्ट तीन प्रकार के घर आधारित कर्मचारियों की बात करती है:
 - औद्योगिक घर आधारित कर्मचारी, जो वस्तुओं के उत्पादन में शामिल हैं जिसमें शामिल है दस्तकारी उत्पादन, जैसे कि दस्तकारी को बनाना, बीड़ी को बनाना, फीतों को बनाना इत्यादि।
 - टेली कर्मचारी, जो सूचना और संचार तकनीकों का प्रयोग दूरस्थ स्थानों से कार्य करके करते हैं।
 - गृह आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मचारी जोकि भीड़ कर्मचारी हैं जो सेवा क्षेत्र कार्य करते हैं जैसा कि नियोक्ताओं अथवा मध्यवर्तियों द्वारा कहा जाता है।



- रिपोर्ट ने बेहतर अनुपालन, कानूनी संरक्षण, व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की बात औद्योगिक घर से कार्य करने वाले कर्मियों के लिए कही है।

ऐसी नीति की क्यों जरूरत है?

- घर से कार्य करने वाले लोग, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग वाले देशों के, अब भी खराब कार्यकारी स्थितियों में कार्य कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में योगदान देने के बावजूद, घर आधारित कार्य अदृश्य रहा है।

ILO की अनुशंसाएं

- सरकार को घर से कार्य करने वाले कर्मियों को संरक्षित करने में मुख्य भूमिका निभानी है।
- लैंगिक प्रतियुत्तर वाले कानूनी और नीति ढांचे को विकसित और क्रियान्वित करने की जरूरत जो अन्य वेतन भोगियों के सापेक्ष घर आधारित कर्मियों की सभी श्रेणियों को समान व्यवहार प्रदान कर सकें। इसमें शामिल है अनौपचारिक कर्मियों को औपचारिक नियोजन के संक्रमण की ओर ले जाना।
- ILO ने यह भी कहा कि टेलीकर्मियों के ज्यादा समय तक कार्य करने का खतरा हो सकता है और इसलिए अपनी तरफ से उन्हें अलग होने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।

नोट: अभी तक घर से कार्य करने पर संधि की 10 देशों ने पुष्टि की है जिसे 25 वर्ष पूर्व जून 20, 1996 को अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में अपनाया गया था।

- ये हैं अल्बानिया, अर्जेंटीना, बेल्जियम, बोस्निया और हर्जगोविना, बुल्गारिया, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, उत्तरी मकदूनिया और ताजिकिस्तान।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I+II- सामाजिक मुद्दे, अर्थव्यवस्था

स्रोत- डाउन टू अर्थ

खराब बैंक की बैलेंसशीट

खबर में क्यों है?

- हाल में, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर (RBI) ने इंगित किया कि केंद्रीय बैंक अनर्जक संपत्तियों (NPAs) से निपटने के लिए खराब बैंक के विचार पर विचार कर सकती है।

पृष्ठभूमि

- अपनी हाल की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में, RBI ने नोट किया कि बैंकिंग क्षेत्र के सकल अनर्जक संपत्तियों के अग्रिमों के 13.5% तक सितंबर 2021 तक बढ़ने की संभावना है, जबकि सितंबर 2020 में यह 7.5% था। गवर्नर ने कहा कि बैंक और गैर बैंक वित्तीय कंपनियां (NBFCs) को जल्दी जोखिम पहचानने की आवश्यकता है, उन्हें पास से निगरानी रखने की जरूरत है और उन्हें प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।
- RBI के गवर्नर ने नोट किया कि वर्तमान कोविड-19 महामारी से संबंधित झटका अनर्जक संपत्तियों के संदर्भ में बैंकों की बैलेंसशीटों पर ज्यादा महत्वपूर्ण दबाव बनायेगा। जिससे पूंजी का क्षरण होगा।

खराब बैंक के बारे में

- एक खराब बैंक वह बैंक है जिसे खराब ऋण और किसी अन्य वित्तीय संस्थान की अन्य गैर तरल होल्डिंग्स को खरीदने के लिए स्थापित किया गया है।
- वह संस्था जो काफी अनर्जक संपत्तियों को रखती है बाजार मूल्य पर खराब बैंक को यह होल्डिंग्स बेच देगी।
- खराब बैंक को यह संपत्तियां हस्तांतरित करने के बाद, मूल संस्थान अपनी बैलेंसशीट को साफ कर सकती है- यद्यपि उसे फिर भी राइट डाउन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
- एक खराब बैंक संरचना एकल बैंक के स्थान पर वित्तीय संस्थानों के समूह की जोखिम भरी संपत्तियों को भी ले सकती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

ऑफ-बजट उधारियाँ

खबरों में क्यों है?

- वित्त मंत्री 1 फरवरी को केन्द्रीय बजट 2021 पेश करने जा रही हैं, जिसमें सभी की आशाएं वित्तीय घाटे को कम करने के लिए बजट के बाहर की उधारियों पर हैं।



ऑफ-बजट उधारियाँ क्या हैं?

- ऑफ-बजट उधारियाँ वे ऋण हैं जिसे केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न लेकर केंद्र सरकार के निर्देश पर अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा लिया जाता है।
- इस तरह के कर्ज का उपयोग सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए लिया जाता है।

राजकोषीय घाटे से बाहर रखा जाता है

- चूंकि केंद्र सरकार ऋण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होती है, इसलिए ऋण को राष्ट्रीय वित्तीय घाटे में शामिल नहीं किया जाता है।
- यह देश के वित्तीय घाटे को स्वीकार्य सीमाओं के अंदर रखने में मदद करता है।

यदि हम ऑफ-बजट उधारियों को शामिल करें, तो वित्तीय घाटा क्या होगा?

- ऑफ-बजट उधार के विभिन्न स्रोतों के कारण, सही राजकोषीय घाटे की गणना करना मुश्किल है। हालांकि, जुलाई 2019 में, कैग ने 2017-18 के लिए वास्तविक वित्तीय घाटे को जीडीपी के 3.85% के बजाय जीडीपी के 5.85% पर आंका था।

ऑफ-बजट ऋण किस प्रकार लिया जाता है?

- सरकार किसी कार्यान्वयन एजेंसी को ऋण या बांड जारी करके बाजार की आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए कह सकती है।
- उदाहरण के लिए, खाद्य सब्सिडी केंद्र सरकार का एक प्रमुख व्यय होता है।
- **2020-21 के लिए बजट प्रस्तुति में**, सरकार ने खाद्य सब्सिडी बिल के लिए बजट की आधी राशि का भुगतान भारतीय खाद्य निगम को किया था।
- इस कमी को **राष्ट्रीय लघु बचत कोष** से ऋण के माध्यम से पूरा किया गया।
- इसने केंद्र को वर्ष 2020-21 में अपने खाद्य सब्सिडी बिल को 1,51,000 करोड़ रुपये से आधा करके 77,892 करोड़ रुपये करने की अनुमति दी।

ऑफ-बजट व्ययों के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का भी इस्तेमाल किया जाता है

- उदाहरण के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को पिछले दिनों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के लिए भुगतान करने के लिए कहा गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उपयोग ऑफ-बजट खर्चों को निधि देने के लिए भी किया जाता है।

- उदाहरण के लिए, पीएसयू बैंकों के ऋणों का उपयोग उर्वरक सब्सिडी को जारी करने में कमी की भरपाई करने के लिए किया गया था।

ऑफ-बजट व्यय पर विभिन्न राय

ऑफ-बजट खर्च पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

- हाल ही में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 2019 की रिपोर्ट बताती है, वित्तपोषण का यह मार्ग संसद के नियंत्रण के बाहर धन का प्रमुख स्रोत बनाता है।
- “इस तरह के ऑफ-बजट वित्तपोषण राजकोषीय निहितार्थ के बावजूद राजकोषीय संकेतकों की गणना का हिस्सा नहीं है।

अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर पंद्रहवां वित्त आयोग

- अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में, पंद्रहवां वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों दोनों को अतिरिक्त बजट उधार को खत्म करने की सलाह दी।
- आयोग ने उल्लेख किया कि संघ और राज्य सरकारों की समेकित निधि के बाहर उधार लेने की बढ़ती प्रवृत्ति, अतिरिक्त बजटीय देनदारियों के संचय के लिए अग्रणी है।
- इसलिए, आयोग ने सिफारिश की कि संघ और राज्यों दोनों को पारदर्शिता के हित में अतिरिक्त बजटीय उधार का पूरा खुलासा करना होगा।
- बकाया अतिरिक्त बजटीय देनदारियों को 2018 के संशोधित एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार समयबद्ध तरीके से पहचानने और समाप्त करने की आवश्यकता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

विज्ञान एवं तकनीक

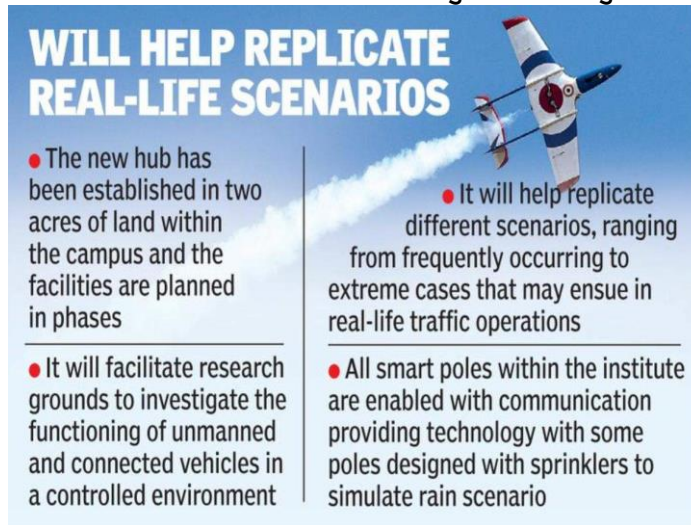
“TIHAN-IIT” टेस्टबेड की स्थापना हुयी

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल में ‘TIHAN-IIT हैदराबाद’ की वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी।

TIHAN-IIT के बारे में

- यह स्वायत्त नौपरिवहन प्रणालियों और आंकड़े अधिग्रहण प्रणालियों के लिए भारत का पहला तकनीकी नवाचार केंद्र है जिसे IIT हैदराबाद ने स्थापित किया है।
- उन्होंने कहा, यह केंद्र दोनों ही भूमि और वायु अनुप्रयोगों के लिए मानवरहित स्वायत्त वाहनों के वास्तविक समय अपनाने में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को सुलझाने में ध्यान केंद्रित करेगा।



वित्तीयन

- इसे अंतरविषयी साइबर भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS) के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीक विभाग (DST) द्वारा स्वीकृत और वित्तीयन किया गया था।

मुख्य जोर वाले क्षेत्र

- केंद्र के जोर वाले क्षेत्रों में बुद्धिमत्ता, स्वायत्त परिवहन एवं प्रणालियां, कृषि, निगरानी और पर्यावरणीय एवं अवसंरचना निगरानी शामिल हैं।

लाभ

- विकसित टेस्ट बेड सभी उद्योगों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, स्वायत्त नौपरिवहन के वृहद क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने वाले अकादमिक के प्रयोग के लिए उपलब्ध होगा।
- यह 'आत्मनिर्भर भारत', 'स्किल इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' की तरफ भी एक बड़ा कदम है।

संबंधित सूचना

- मार्च 2020 में, विज्ञान एवं तकनीक विभाग (DST) ने अंतरविषयी साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS) के अंतर्गत IIT मंडी में एक तकनीकी नवाचार केंद्र (TIH) की स्थापना का निर्णय लिया।

तकनीकी नवाचार केंद्र के बारे में

- इस लक्ष्य मानव-कम्प्यूटर अन्योन्य क्रिया (HCI) अनुसंधान पर जोर देना है जहां परियोजनाएं कम्प्यूटर तकनीक (इंटरफेस) के डिजाइन और विकास पर केंद्रित होगी। साथ ही मानवों (प्रयोगकर्ताओं) और कम्प्यूटरों के बीच में अन्योन्य क्रिया के अध्ययन पर भी जोर होगा।

साइबर भौतिक प्रणालियों (CPS) के बारे में

- ये एक नये वर्ग के इंजीनियर्ड प्रणालियां हैं जो एक गत्यात्मक पर्यावरण में गणना और भौतिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करती हैं।
- इसमें साइबरनेटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), बिग डाटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और कई अन्य के तकनीकी क्षेत्र शामिल हैं।
- इसके संभावित अनुप्रयोग हैं a) बिना ड्राइवर की कारें जो स्मार्ट रोडों पर सुरक्षित रूप से एक दूसरे के साथ संचार करती हैं b) घरों में संसूचक जिससे बदलती हुई स्वास्थ्य स्थितियों को पहचाना जा सके।

अंतरविषयी साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS) के बारे में

- इसकी शुरुआत 2018 में पांच वर्षों की अवधि के लिए विज्ञान एवं तकनीक विभाग द्वारा की गई थी।

उद्देश्य

- समन्वय और राष्ट्रव्यापी प्रयासों को एकीकृत करके CPS के लिए बाधरहित पारिप्रणाली का निर्माण करना जिसमें ज्ञान निर्माण, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान, तकनीक, नवाचार और व्यावसायीकरण शामिल हैं।

मिशन की विशेषताएं

- इसके अंतर्गत, तकनीकी नवाचार केंद्रों (TIH), अनुप्रयोग नवाचार केंद्रों (AIH) और तकनीक ट्रांसलेशन अनुसंधान पार्को (TTRP) की स्थापना की जाएगी।
- ये केंद्र अकादमिक, उद्योग, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार से जुड़ेंगी और केंद्र और स्पोक मॉडल में पूरे देश में जाने-माने अकादमिक, अनुसंधान एवं विकास और अन्य संगठनों में हलों का विकास करेंगे।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

औषधीय पौधों के लिए राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड ने भागीदारी की शुरुआत की

खबर में क्यों है?

- आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों के लिए भागीदारी की शुरुआत की है, जिसकी संकल्पना औषधीय पौधों की आपूर्ति चेन और मूल्य चेन में हितधारकों के बीच में जुड़ाव की जरूरत पैदा करने की है।

औषधीय पौधे के लिए भागीदारी के बारे में

- यह गुणवत्ता वाले पौध पदार्थों, अनुसंधान एवं विकास, खेती, औषधीय पौधे/बाजार जुड़ाव के व्यापार इत्यादि को देखेगा/चर्चा करेगा (इतने पर ही सीमित नहीं)।

बीज से अलमारी तक का दृष्टिकोण

- यह किसानों और विनिर्माणकर्ताओं के मध्य जुड़ाव स्थापित करेगा। बीज से अलमारी तक का दृष्टिकोण को लागू किया जा रहा है जहां गुणवत्ता वाले पौध पदार्थों (QPM), अच्छी कृषि प्रथाओं (GAPs), फसल कटने के बाद की अच्छी प्रथाओं (GPHPs) को भी सुलझाया जाएगा।



पहले चरण में, NMPB भागीदारी औषधीय पौध प्रजातियों जो निम्न हैं, के लिए प्रस्तावित है

- अनोला (फाइलेन्थस इम्बलिका)
- गुगुल्लु (कम्मीफोरा वेटाई)
- अश्वगंधा (विथेनिया सोमिनीफेरा)
- पिप्पली (पाइपर लॉगम)
- शतावरी (एस्पेरागस रेसमोसस)

संबंधित सूचना

राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड के बारे में

- इसकी स्थापना 2000 में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी (आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)।

उद्देश्य

- इसका मुख्य उद्देश्य औषधीय पौधों पर नीतियों/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के बीच में एक मजबूत समन्वय का विकास करके औषधीय पौध क्षेत्र का विकास करना है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

CSIR ने केले की ग्रिट का विकास किया

खबर में क्यों है?

- हाल में, CSIR- केरल में राष्ट्रीय अंतरविषयी विज्ञान एवं तकनीक संस्थान (NIIST) ने एक नए उत्पाद केला ग्रिट अथवा रवे का विकास किया है।

केला ग्रिट के बारे में

- इसे कच्चे नेन्द्रान केले से विकसित किया गया है जो कि रवा अथवा टूटे हुए गेहूँ से मिलता-जुलता है।

उद्देश्य



- इस उत्पाद को स्वास्थ्यकर आहार के लिए एक आदर्श घटक माना जा रहा है क्योंकि यह केले में उपस्थित प्रतिरोधक स्टार्च का उपयोग करता है जिसे पेट के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है।
- इस संकल्पना का उद्देश्य केले में प्रतिरोधक स्टार्च की उपस्थिति का उपयोग करना है जिससे पेट का स्वास्थ्य ठीक होता है।

महत्व

- यह किसानों के लिए सहायक होगा जिन्हें अक्सर केलों के गिरते हुए मूल्य से जुझना पड़ता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- स्वास्थ्य+ विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- द हिंदू

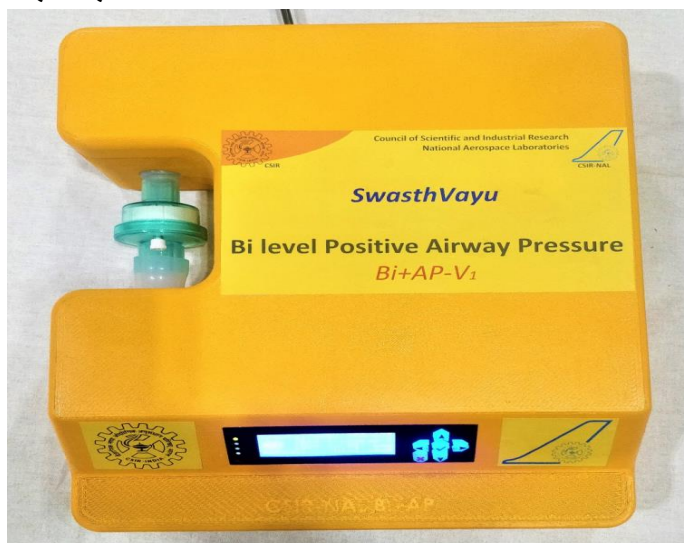
स्वस्थ वायु

खबर में क्यों है?

- हाल में, CSIR-IGIB से चिकित्सा पेशेवरों के साथ CSIR-NAL के वैज्ञानिक आगे आए जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी की शुरुआत में वेंटीलेटरों की कमी को सुलझाना था और स्वदेशी गैर-इनवैसीनेबीलेवल पॉजीटिव एयरवे दवाब वेंटीलेटर की डिजाइन और विकसित करना था। इन्हें स्वस्थ वायु कहा जाता है।

स्वस्थ वायु के बारे में

- स्वस्थवायु का प्रयोग कोविड-19 रोगियों पर किया जा सकता है जिनको 35% तक ऑक्सीजन संपूरक की जरूरत होती है।



विशेषताएं

- स्वस्थवायु माइक्रोकंट्रोलर आधारित सटीक क्लोज्ड लूप एडेप्टिव नियंत्रण प्रणाली है जिसमें अंदर ही बायोकम्पैटिबल 3डी प्रिंटेड मैनीफोल्ड और कपलर लगा हुआ है। साथ ही HEPA फिल्टर (हाइली एफीसिएंट पार्टिकुलर एयर फिल्टर) भी लगा हुआ है।
- ये विशिष्ट विशेषताएं वायरस के फैलने के डर को समाप्त करती हैं।
- इसमें CPAP, बाई टाइम्ड, स्पॉन्टेनियस/ऑटो मोड्स भी हैं जिसके साथ ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर अथवा इनरिचमेंट इकाई को बाह्य रूप से जोड़ा जा सकता है।

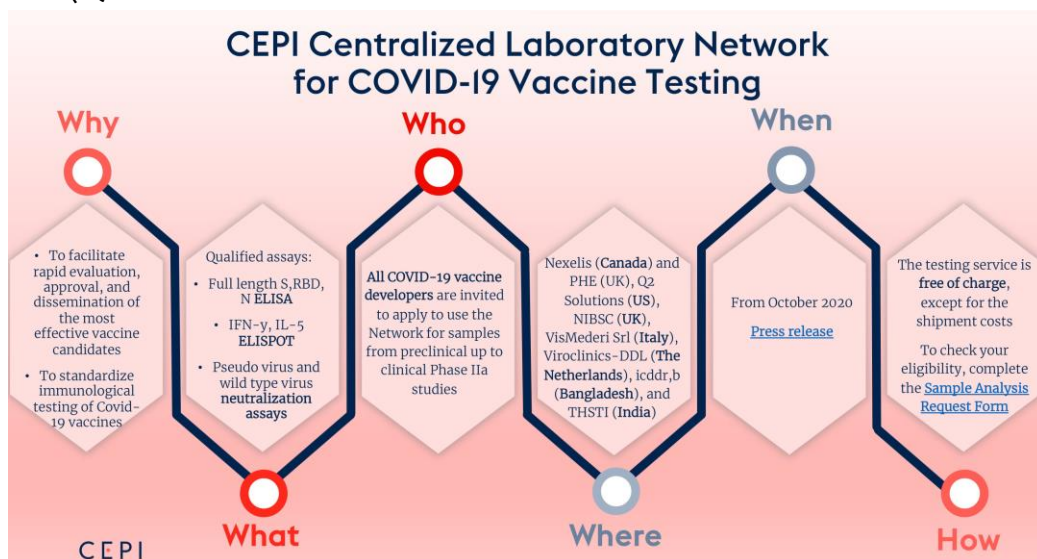
विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- PIB

CEPI केंद्रीकृत नेटवर्क प्रयोगशाला

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीक मंत्री ने विश्व की सात प्रयोगशालाओं में से एक का उद्घाटन किया है जिसे महामारी तैयारी नवाचार के लिए गठबंधन की केंद्रीकृत नेटवर्क प्रयोगशाला (CEPI) कहा जा रहा है। इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं तकनीक संस्थान (THSTI), फरीदाबाद में की गई है।



CEPI केंद्रीकृत नेटवर्क प्रयोगशाला के बारे में

- DBT-THSTI फरीदाबाद में CEPI केंद्रीकृत प्रयोगशाला भारत में अपने प्रकार की पहली है और पूरी दुनिया में सात में से एक है।
- यह भारत में अपनी प्रकार की पहली प्रयोगशाला है और इसका प्रमाणीकरण राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशाला (NABL) (ISO 17025: 2017) द्वारा किया गया है।

महामारी तैयारी नवाचार के लिए गठबंधन (CEPI) के बारे में

- CEPI सार्वजनिक, निजी, धर्मार्थ और नागरिक संगठनों के बीच में नवाचार साझेदारी है, इसकी शुरुआत डावोस में 2017 में की गई थी जिससे भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए टीकों का विकास किया जा सके।
- जैवतकनीक विभाग, विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय, भारत सरकार Ind-CEPI मिशन का क्रियान्वयन कर रहे हैं।
- Ind-CEPI मिशन जिसका शीर्षक 'तीव्र टीका विकास के द्वारा भारत आधारित महामारी तैयारी: महामारी तैयारी नवाचारों (CEPI) के लिए गठबंधन की वैश्विक पहल के साथ समायोजित भारतीय टीका विकास को समर्थन' है।
- Ind-CEPI मिशन का लक्ष्य भारत में महामारी संभावना के रोगों के लिए टीके के विकास को मजबूत करना है। साथ ही इसका एक अन्य लक्ष्य भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और टीका उद्योग में समन्वित तैयारी को निर्मित करना है, जिससे भारत में वर्तमान और उभरते हुए संक्रामक खतरों से निपटा जा सके।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- PIB

मीलवार्म

खबर में क्यों हैं?

- यूरोपीय खाद्य सुरक्षा एजेंसी (EFSA) ने हाल में यूरोप के पास्ता बोल और डिनर डिशेज में मीलवार्म को स्वीकृति दे दी, यह मानव भोजन में कीड़े की स्वीकृति देने वाली पहली संस्था है।

हाल के निर्णय के बारे में

- यूरोपीय संघ की एजेंसी ने इसे **अनोखे भोजन** विनियमन के अंतर्गत आकलित किया है जो 2018 में प्रभाव में आया था।
- यूरोपीय खाद्य सुरक्षा एजेंसी (EFSA) के इस निर्णय ने पीले भृंगक को करी और व्यंजन विधि में खड़े और सूखे रूप में प्रयोग करने का रास्ता खोल दिया है। साथ ही इसका प्रयोग बिस्कुट, पास्ता और ब्रेड बनाने के आटे के रूप में भी किया जाएगा।
- इनमें प्रोटीन, वसा और रेशा प्रचुर मात्रा में होती है।

मीलवार्म के बारे में



- ये मीलवार्म बीटल के लार्वा के रूप हैं, जिन्हें **टेनेब्रिओ मोलिटॉर** कहते हैं, यह डार्कलिंग बीटल की एक प्रजाति है।
- ये होलोमेटाबॉलिक कीड़े होते हैं।

नोट:

- होलोमेटाबॉलिज्म जिसे पूर्णतया रूपांतरण भी कहा जाता है, यह कीड़े के विकास का एक रूप है जिसमें चार जीवन के चरण शामिल होते हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और इमेगो अथवा वयस्क।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

भारत में 5जी तकनीक

खबर में क्यों है?

- हाल में, दूरसंचार विभाग (DoT) ने 5जी बैंड्स सहित अगले दस वर्षों के लिए रेडियोफ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रयोग और बिक्री पर टेलकोज और अन्य उद्योग विशेषज्ञों से जानकारी मांगी है।



क्या है 5जी तकनीक?

- यह दीर्घावधि विकास (LTE) मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्कों में नवीनतम उन्नयन है।

- यह मुख्य रूप से 3 बैंडों में कार्य करता है, जिनके नाम निम्न, मध्य और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम हैं- इन सभी के अपने उपयोग और सीमाएं हैं।

निम्न बैंड आवृत्ति स्पेक्ट्रम

- निम्न बैंड स्पेक्ट्रम ने कवरेज एवं इंटरनेट गति और डाटा विनिमय गति के संदर्भ में काफी ज्यादा आशा दिखाई है।
- इसकी अधिकतम गति 100 Mbps (मेगाबिट्स प्रति सेकंड) तक सीमित है।

मध्य-बैंड स्पेक्ट्रम

- मध्य बैंड स्पेक्ट्रम की निम्न बैंड की अपेक्षा ऊंची गतियां हैं लेकिन कवरेज क्षेत्र और संकेत भेदन के संदर्भ में इसकी सीमाएं हैं।
- उद्योग और विशेषीकृत फैक्ट्री इकाईयां इस बैंड का प्रयोग कैप्टिव नेटवर्क के निर्माण में कर सकते हैं जिसे उस विशेष उद्योग की जरूरतों के अनुसार ढाला जा सकता है।

ऊंचा बैंड स्पेक्ट्रम

- ऊंचा बैंड स्पेक्ट्रम तीनों बैंडों में सबसे ऊंची गति देता है, लेकिन इसका कवरेज और संकेत भेदन शक्ति कम से कम होती है।
- इसकी अधिकतम गति का 20 Gbps (गीगाबिट्स प्रति सेकंड) तक परीक्षण किया जा चुका है जबकि 4जी के मामले में अधिकतम इंटरनेट डाटा गति 1 Gbps तक रिकॉर्ड की गई है।

भारत 5जी तकनीक की दौड़ में कहां खड़ा है?

- 2018 में भारत ने जल्दी से जल्दी 5जी सेवाओं को आरंभ करने की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य बेहतर नेटवर्क गतियों का और जैसा कि तकनीक वादा कर रही है उसकी शक्ति का फायदा उठाना।
- सभी तीनों निजी दूरसंचार कंपनियां, रिलायंस जियो इंफोकॉम, भारती एयरटेल और वाई DoT से कह रही हैं वह स्पेक्ट्रम आवंटन और 5जी आवृत्ति बैंड्स का एक स्पष्ट रोडमैप जारी करे जिसके अनुसार उनकी सेवाओं के रोलआउट की योजना बनाई जा सके।
- दूसरी ओर, रिलायंस जियो स्वदेश में ही तैयार देश के लिए इस वर्ष के उत्तरार्ध में 5जी नेटवर्क को उतारने की योजना बना रहे हैं।

5जी पर वैश्विक प्रगति क्या है?

- वैश्विक दूरसंचार कंपनियों ने 5जी नेटवर्कों को निर्मित करना शुरू कर दिया है और परीक्षण के आधार पर अपने ग्राहकों को इस रोलआउट करना शुरू कर दिया है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में, AT&T, T-मोबाइल और वेरीजॉन जैसी कंपनियां आगे बढ़ गई हैं जहां तक उनके प्रयोगकर्ताओं के लिए व्यावसायिक 5जी रोलिंग आउट का संबंध है।
- दक्षिण कोरिया की कंपनी, सैमसंग जिसने 2011 में ही 5जी तकनीक पर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया था, ने दूसरी तरफ, बढ़त ले ली है जहां तक कई कंपनियों के लिए 5जी नेटवर्कों के लिए हार्डवेयर को निर्मित करने की बात है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

रक्षिता

खबर में क्यों है?

- हाल में, परमाणु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (INMAS), दिल्ली आधारित DRDO की प्रयोगशाला ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को रक्षिता सौंपा।



रक्षिता के बारे में

- यह बाइक आधारित आपात परिवहन आपातकालीन वाहन है।
- इसमें एक कस्टमाइज्ड रिकलाइनिंग कैजुअल्टी इवैकुएशन सीट (CES) लगाई गई है, जिसे जरूरत के अनुसार लगाया और निकाला जा सकता है।
- अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं हेड इम्मोबिलाइजर, सेफ्टी हारनेस जैकेट, सुरक्षा के लिए हाथ और पैर के स्ट्रैप, शारीरिक मानदंडों को जांचने वाले उपकरण सहित बेतार की निगरानी क्षमता और चालक के लिए स्वतः चेतावनी प्रणाली भी शामिल है।



महत्व

- बाइक एम्बुलेंस भारतीय सुरक्षा बलों और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं से निपटने में मदद देगी।
- यह निम्न तीव्रता वाले लड़ाई के क्षेत्रों से घायल रोगियों को निकालने के लिए जीवनदायिनी सहायता प्रदान करेगी।
- यह भीड़भाड़ वाली सड़कों और दूरस्थ स्थानों में काफी काम आएगी, जहां एम्बुलेंस के द्वारा पहुँचना काफी कठिन और समय खपाने वाला है।
- एक बाइक चार पहिया वाहन की अपेक्षा रोगियों की चिकित्सा आपात जरूरतों तक पहुँचने में ज्यादा तीव्र होगी क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली सरल और इसमें एकीकृत आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रणाली लगी होती है।

- यह बाइक एम्बुलेस न केवल अर्ध सैनिक बलों और सैन्य बलों के लिए उपयोगी है बल्कि संभावित नागरिक अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी है।

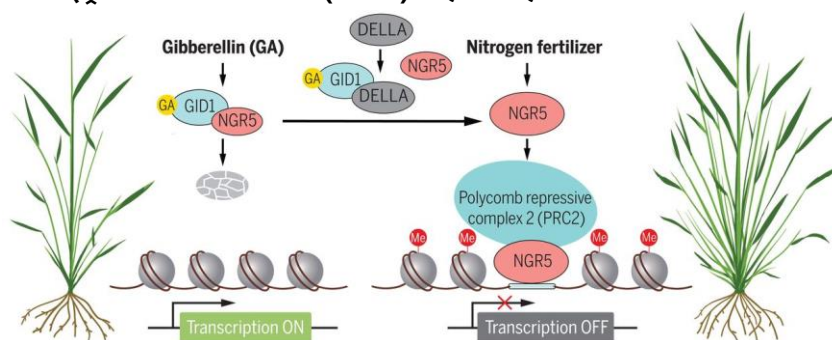
विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक + रक्षा

स्रोत- PIB

वैज्ञानिकों ने धान में नाइट्रोजन प्रयोग सामर्थ्य सुधारने के तरीके की खोज की

खबर में क्यों है?

- हाल में, भारतीय जैवतकनीक वैज्ञानिकों ने फसल सुधार करने के तरीके की खोज की है जिससे अरबों रुपये मूल्य की नाइट्रोजनीकृत (N) खादों के बेकार जाने को कम करने में मदद मिलेगी।
- यह समर्थ्य नाइट्रोजन प्रयोग सामर्थ्य (NUE) कहलाता है।



नाइट्रोजन प्रयोग सामर्थ्य (NUE) के बारे में

- यह उपयोजित नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा है जो अवशोषित होती और पौधे द्वारा प्रयोग की जाती है।
- अनाज उत्पादन के लिए (गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, जई और राई) NUE 33% तक निम्न है।
- अनाज देश में नाइट्रोजनीकृत खादों के कुल उपभोग के 69% के लिए जिम्मेदार है जिसमें 37% के साथ चावल सबसे ऊपर है, जिसमें के बाद गेहूँ का स्थान है (24 प्रतिशत)।
- फसलों के लिए निम्न NUE का अर्थ है उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए ऊंची लागतें, नाइट्रोजन खाद पर ज्यादा आयात निर्भरता, निक्षालन इत्यादि।

NUE की गणना कैसे की जाती है?

- NUE की गणना उपयोग की गई नाइट्रोजन और फसल के बीच के अनुपात से की जाती है। ऊंची संख्या निम्न बरबादी को निरूपित करता है।

नाइट्रोजन प्रयोग सामर्थ्य के लाभ

- कृषि भारत में सभी नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जनों के 70% के लिए जिम्मेदार है। यह किसानों को नाइट्रोजनीकृत खादों को सही तरीके से प्रयोग करने और लागतों को बचाने में मदद करेगी।
- यह नाइट्रोजन से जुड़े प्रदूषण को सीमित करने में मदद देगा, जो मौसम परिवर्तन में योगदान देता है।

पौधे में नाइट्रोजन का प्रयोग

- नाइट्रोजन (N) की अक्सर फसलों में बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, प्राथमिक रूप से बल और उपज के लिए।
- नाइट्रोजन क्लोरोफिल उत्पादन और प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका अदा करती है।

- क्लोरोफिल हरे पौधे का रंग जोकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। जब नाइट्रोजन की कमी होती है, पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं और उनकी वृद्धि कम हो जाती है।

नोट:

- भारतीय नाइट्रोजन आकलन (2017) के अनुसार, कृषि भारतीय पर्यावरण में 70% से ज्यादा सभी नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। इनमें से मुख्य रूप से यूरिया का योगदान 77 प्रतिशत है।
- नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीनहाउस गैस (GHG) है जो कार्बन डाईऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा शक्तिशाली है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- डाउन टू अर्थ

को-वैक्सीन यू.के. किस्म के विषाणु के खिलाफ प्रभावी है - अध्ययन

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान शोध परिषद (ICMR) और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV) ने एक नए अध्ययन में कोवैक्सीन को नए ब्रिटेन संस्करण के खिलाफ कारगर पाया है।



मुख्य बिंदु

- वैक्सीन लेने वाले 38 लोगों के सीरम (रक्त का थक्का जमने के बाद रक्त से निकाला गया प्रोटीन युक्त द्रव) लेकर “प्लेक रिडक्शन न्यूट्रलाइज़ेशन” टेस्ट (PRNT50) किया गया।
- कोवाक्सिन यूके के नए स्ट्रेन के साथ-साथ विषम SARS-CoV-2 स्ट्रेन के खिलाफ कारगर है।
- ब्रिटेन किस्म के लिए सेरा के 50% निष्प्रभावी का माध्य अनुपात 80% था और भारत में फैले स्ट्रेन के लिए 90% था, लेकिन यह वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए सेरा से अलग था।

यह निष्प्रभावी अध्ययन कैसे किया गया?

- सबसे पहले, लोगों से लिए गए वायरस को कोशिका रेखाओं (cell lines) का उपयोग करके प्रयोगशाला में उगाया जाता है।

- जब वायरस सफलतापूर्वक विकसित होते हैं, तो कोशिकाओं में वायरस के रोगजनक प्रभाव देखे जाते हैं।
- टीकाकृत लोगों से लिए गए सेरा को फिर सेल लाइन कल्चर सिस्टम में जोड़ा जाता है, और इसकी वायरस को रोगजनक प्रभाव पैदा करने से रोकने की क्षमता देखी जाती है।
- इस मामले में, टीकाकृत लोगों से लिए गए सेरा ने वायरस को निष्प्रभावी कर दिया है और इसलिए वायरस वाले सेल लाइनों में उत्पन्न होने वाले रोगजनक प्रभावों को रोकती है।

कोवैक्सीन के बारे में

- यह भारतीय आयुर्विज्ञान शोध परिषद (आईसीएमआर) के सहयोग से भारत बायोटेक कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
- यह हैदराबाद (तेलंगाना) में स्थित कंपनी के बायो-सेफ्टी लेवल 3 (BSL-3) हाई कन्टेनमेंट सुविधा में निर्मित एक निष्क्रिय टीका है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दे

(AFSPA) के अंतर्गत नागालैंड अशांत क्षेत्र घोषित

खबर में क्यों है?

- हाल में, गृह मंत्रालय द्वारा छह महीने के लिए संपूर्ण नागालैंड राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।



- इससे यहां पर विवादास्पद सैन्य बल (विशेष शक्ति) कानून जारी रहेगा जो सुरक्षा बलों को किसी को भी कहीं भी और बिना पूर्व वारंट के गिरफ्तार करने और ऑपरेशन चलाने का अधिकार प्रदान करता है।

सैन्य बल (विशेष अधिकार) कानून के बारे में

- AFSPA सैन्य बलों को “अशांत क्षेत्रों” में शांति बनाये रखने का अधिकार प्रदान करता है।
- AFSPA अधिकारी को एक क्षेत्र में पांच अथवा ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने का निषेध करने का अधिकार प्रदान करती है। वे बल का प्रयोग कर सकते हैं अथवा किसी व्यक्ति द्वारा कानून के उल्लंघन करने की स्थिति में फायरिंग भी कर सकते हैं।
- AFSPA के अंतर्गत अधिकारियों को दी गई शक्तियां हैं:
 - सेना भी बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।
 - बिना वारंट के किसी भी परिसर में प्रवेश अथवा छानबीन कर सकती है; और
 - अग्नेयास्त्रों को रखने पर रोक लगा सकती है।
- कोई भी गिरफ्तार अथवा कस्टडी में लिया गया व्यक्ति निकटतम पुलिस स्टेशन के अधिकारी को सौंपा जा सकता है। साथ ही उसके गिरफ्तार होने की परिस्थितियों के विस्तृत रिपोर्ट भी होगी।

“अशांत क्षेत्र” की परिभाषा

- कोई भी अशांत क्षेत्र वह है जोकि AFSPA के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अधिसूचना के द्वारा घोषित किया गया है।
- एक क्षेत्र इसलिए भी अशांत हो सकता है कि वहां विभिन्न धर्मों के सदस्यों, जातीय, भाषाई अथवा क्षेत्रीय समूहों अथवा जातियां अथवा समुदायों के सदस्यों के मध्य मतभेद अथवा विवाद हैं।

- केंद्रीय सरकार अथवा राज्य की सरकार अथवा केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक संपूर्ण अथवा राज्य के किसी हिस्से को अथवा केंद्र शासित क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकता है।

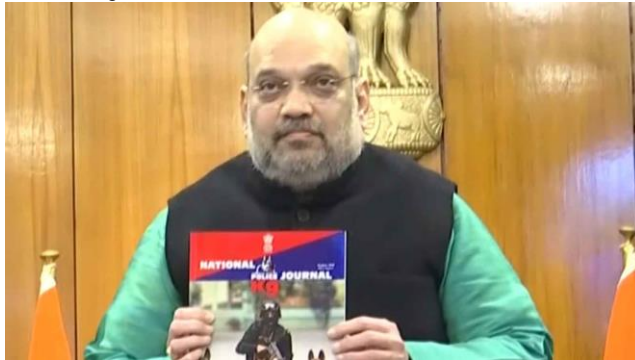
विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा एवं सुरक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

राष्ट्रीय नीति K-9 जर्नल

खबर में क्यों है?

- हाल में, केंद्रीय गृह मंत्री ने “राष्ट्रीय नीति K-9 जर्नल” के पहले संस्करण को जारी किया।



पृष्ठभूमि

- एक विशेष पुलिस K9 सेल को नवंबर 2019 में स्थापित किया गया था। जोकि गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग के अंतर्गत था। इसका शासनादेश ‘देश में पुलिस सेवा K9 की मुख्यधारा और मजबूती’ है।

राष्ट्रीय पुलिस K-9 जर्नल के बारे में

- यह पुलिस सेवा K9 (PSKs) अर्थात पुलिस डॉग्स के विषय पर पहला ऐसा प्रकाशन है।
- यह एक विशिष्ट पहल है जोकि देश में पुलिस सेवा डॉग (k-9) (PSK) टीमों से संबंधित विषयों पर और भी ज्ञान देगा।
- पुलिस डॉग दस्ता एक बल गुणक के रूप में कार्य कर सकता है जोकि ड्रोंनों और उपग्रहों के समान ही समाज की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, जिनका प्रयोग देश में किया जा रहा है।
- इस जर्नल में हिंदी और अंग्रेजी में विभिन्न अनुच्छेद हैं।
- यह द्विवार्षिक जर्नल है जिसे प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में प्रकाशित किया जाएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- सुरक्षा और रक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

समुद्री सतर्कता 2021

खबर में क्यों है?

- हाल में, भारतीय नौसेना तटीय रक्षा अभ्यास के दूसरे संस्करण ‘समुद्री सतर्कता’ को समन्वित करने जा रही है।



समुद्री सतर्कता अभ्यास के बारे में

- यह द्विवार्षिक अभ्यास है जो जनवरी 2019 में शुरू हुआ था।
- यह प्रमुख थियेटर स्तर के अभ्यास TROPEX (थियेटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज) की ओर तैयारी है।
- इसका आयोजन 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद में तटीय सुरक्षा में अंतरालों को भरने के लिए किये गए उपायों के सामर्थ्य को जांचने के लिए किया जा रहा है।

संबंधित सूचना

थियेटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज (TROPEX) के बारे में

- यह अंतर-सेवा सैन्य अभ्यास है जिसे प्रत्येक दूसरे वर्ष भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है।
- इस अभ्यास का लक्ष्य भारतीय नौसेना के संयुक्त बेड़े के लड़ाई तैयारियों की जांच करना है। साथ ही यह भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की परिसंपत्तियों की जांच करता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

कैबिनेट समिति ने रु. 48,000 करोड़ के तेजस सौदे को मंजूरी दी

खबर में क्यों है?

- सरकार ने हाल में भारतीय वायुसेना (IAF) के लिए स्वदेश में विकसित 83 हल्के लड़ाकू एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद को स्वीकृति दे दी।

HAL तेजस के बारे में



- HAL तेजस एक भारतीय एकल इंजन, चौथी पीढ़ी का बहुभूमिका वाला हल्का लड़ाकू विमान है जिसे भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए वैमानिकी विकास एजेंसी (ADA) ने हिंदुस्थान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के एयरक्राफ्ट अनुसंधान एवं डिजाइन केंद्र (ARDC) के साथ सहयोग में बनाया है।
- यह हल्के लड़ाकू एयरक्राफ्ट (LCA) कार्यक्रम से आया है जिसे भारत के पुराने पड़ रहे MiG-21 लड़ाकू विमानों को विस्थापित करने के लिए 1980 के दशक में शुरू किया गया था।
- 2003 में LCA को आधिकारिक तौर पर “तेजस” नाम दिया गया।
- तेजस HAL HF-24 मारुत के बाद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित किया गया दूसरा सुपरसोनिक लड़ाकू जहाज है।
- Mk1A रूप में LCA- तेजस के 50 प्रतिशत स्वदेशी उपकरण हैं।
- यह समकालीन सुपरसोनिक लड़ाकू एयरक्राफ्ट के अपने वर्ग में सबसे छोटा और सबसे हल्का है।

तकनीक का प्रयोग

- यह तकनीकों जैसे कि रिलेक्स्ड स्टेटिक स्टेबिलिटी, फ्लाय बाई वायर फ्लाइट कंट्रोल प्रणाली, मल्टी मोड रडार, इंटीग्रेटेड डिजीटल एवॉयनक्स प्रणाली और कंपोजिट मैटेरियल स्ट्रक्चर्स को एकीकृत करता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

अमेरिका के छोड़ने के बाद रूस ओपेन स्काईज संधि से हटा

खबरों में क्यों है?

- रूस ने हाल में घोषणा की है कि वह ओपेन स्काईज संधि से हट जाएगा जोकि सैन्य सुविधाओं के ऊपर से पर्यवेक्षण उड़ानों की इजाजत देगी। इसके पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस संधि से बाहर निकल चुका है।

हटने का कारण

- मास्को का तर्क है कि अमेरिका के हटने से वैश्विक सुरक्षा का हास होगा जिससे सरकारों के लिए अन्य देशों की मंशाओं को समझना और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा, विशेष रूप से 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर रूसी अधिकार के बाद बढ़ते रूस-पश्चिम तनाव के मध्य में।

ओपेन स्काईज संधि क्या है?

- इसे सर्वप्रथम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्विट आइजनहावर द्वारा शीतयुद्ध के दौरान तनाव घटाने के माध्यम के रूप में प्रस्तावित किया गया था। अंतोगत्वा यह ऐतिहासिक संधि 1992 में NATO सदस्यों और पूर्व वारसा संधि के देशों के बीच में सोवियत संघ के विखंडन के बाद हुई।
- यह 2002 में प्रभावी हुई और वर्तमान में एक गैर पुष्टिकारी सदस्य (किर्गिजस्तान) सहित इसके कुल 35 सदस्य देश हैं।

लक्ष्य

- ओपेन स्काई संधि का लक्ष्य आपसी खुलेपन के द्वारा सदस्य देशों के मध्य आत्मविश्वास का निर्माण करना है, इस तरह से दुर्घटना के रूप में शुरू होने वाले युद्ध की संभावनाएं घट जाएंगी।
- संधि के अंतर्गत, एक सदस्य देश मेजबान देश के किसी भाग में जासूसी कर सकता है जिसके लिए उसे उसकी अनुमति लेनी होगी।
- एक देश मेजबान देश के वायु से चित्र ले सकता है जिसके लिए उसे 72 घंटे पूर्व नोटिस देनी होगी, और उसे उसके सही उड़ान पथ के बारे में 24 घंटे पहले बताना होगा।
- इस तरह से एकत्रित सूचना, जैसे कि फौज की आवाजाही, सैन्य अभ्यास और मिसाइल तैनाती को सभी सदस्य देशों के साथ साझा करना होगा।
- केवल स्वीकृति चित्र लेने वाले यंत्रों की ही निगरानी उड़ानों में इजाजत होगी, और मेजबान देश से अधिकारी भी नियोजित यात्रा के दौरान ऑनबोर्ड रह सकते हैं।

ओपेन स्काईज संधि का महत्व

- यह वर्तमान में जासूसी करने का पसंदीदा तरीका है।
- यह गुप्त उपग्रह आंकड़े प्राप्त करने के लिए वाशिंगटन पर निर्भरता को भी कम करता है, जोकि OST निगरानी रिकार्डों को प्राप्त करने की तुलना में ज्यादा मुश्किल होगा जिसे संधि के दायित्व के अनुसार सभी सदस्यों के साथ साझा करना अनिवार्य है।

संबंधित सूचना

नई START संधि के बारे में

- नई रणनीतिक शस्त्र नियंत्रण संधि (START) संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी गणराज्य के मध्य एक संधि है जिसका उद्देश्य रणनीतिक आक्रमक शस्त्रों को और भी घटाना और सीमित करना है।
- यह 5 फरवरी, 2011 को लागू हुई।
- यह 1991 के START ढांचे की उत्तराधिकारी है (शीतयुद्ध की समाप्ति पर) जिसने दोनों पक्षों तक 1,600 रणनीतिक डिवीलरी व्हेकिल्स और 6,000 आयुधों तक सीमित कर दिया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि नये START के प्रसार से चीन और रूस के साथ शस्त्रों के सौदे का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- उसे चिंता है कि चीन का नाभिकीय जमाव दुगुना हो सकता है यदि नई START संधि इसी रूप में जारी रहती है, जिसमें चीन शामिल नहीं है।
- नई START संधि पुष्टीकरण अपर्याप्तता से भी प्रभावित हुई है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए शस्त्र नियंत्रण शासन को स्थापित करने का प्रयास किया है जिसमें चीन शामिल हो।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा + अंतरराष्ट्रीय संबंध

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास

खबर में क्यों है?

- भारतीय वायुसेना (IAF) और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल (Armée de l'Air et de l'Espace) के बीच में डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास हाल में जोधपुर, राजस्थान में होगा।

डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास के बारे में

- इस अभ्यास की मेजबानी भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल (Armée de l'Air et de l'Espace) द्वारा की जा रही है।



इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है?

- यह ऑपरेशनल अनुभव उपलब्ध कराएगा और लड़ाई क्षमता के उन्नयन की ओर प्रथाओं को साझा करने में सहायता करेगा।

इस अभ्यास के बारे में क्या अनूठा है?

- यह पहली बार है कि भारतीय आकाश दोनों तरफ से राफेल एयरक्राफ्ट की मेजबानी करेगा।

भारत और फ्रांस के बीच में रक्षा अभ्यास

- वरुणा- नौसैनिक अभ्यास
- गरुड़- वायु अभ्यास
- शक्ति- थलसेना अभ्यास

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन (SAAW)

खबर में क्यों है?

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वेदश में निर्मित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन (SAAW) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका परीक्षण ओडिशा तट पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के हाक-1 से किया गया।
- यह भारतीय हाक-MK132 से फायर किया गया पहला स्मार्ट हथियार है।



स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन (SAAW) के बारे में

- यह एक लंबी दूरी की सटीक रूप से निर्देशित एंटी एयरफील्ड हथियार है जिसको **DRDO** के अनुसंधान केंद्र इमारात (**RCI**) हैदराबाद ने विकसित किया है।
- हथियार की डिजाइन भूमि के लक्ष्यों पर प्रहार करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से दुश्मन की एयरफील्ड अवसंरचना अथवा समान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अधिष्ठानों के लिए।
- यह हथियार दुश्मनों की एयरफील्ड परिसंपत्तियों को फंसाये रखने के लिए है जैसे कि रडार, बंकर, टैक्सी के रास्ते और 100 किमी. की रेंज वाली हवाईपट्टियां।
- इसकी उच्च शक्ति वाला सटीक तरीके से निर्देशित बम अपने वर्ग की अन्य हथियार प्रणालियों की तुलना में हल्के वजन का है।

RCI हैदराबाद द्वारा विकसित अन्य हथियार

- यह भारत का पहला स्वदेशी निर्मित प्रति विकिरण वायु से सतह में मार करने वाली मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया है।
- इस मिसाइल को **SU-30 Mk1** एयरक्राफ्ट में एकीकृत किया गया है।
- इसको दुश्मन के रडार, संचार संपत्तियों और अन्य रेडियो आवृत्ति स्रोतों को पहचानने, ढूंढने और निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया है। ये सभी चीजें सामान्यतया उनके वायु रक्षा प्रणालियों के हिस्से होते हैं।

नोटः

- यह अभी तक किया गया **DRDO** का 9वां सफलतापूर्वक **SAAW** मिशन है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दे

एशियाई जलपक्षी जनगणना

खबर में क्यों है?

- हाल में, बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) से विशेषज्ञों की निगरानी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में दो दिवसीय एशियाई जलपक्षी जनगणना-2020 शुरू हुई।



एशियाई जलपक्षी जनगणना के बारे में

- यह वैश्विक जलपक्षी निगरानी कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय जलपक्षी जनगणना (IWC) का एक अविभाज्य हिस्सा है जिसका समन्वय नमभूमि अंतरराष्ट्रीय द्वारा किया जाता है।
- यह अफ्रीका, यूरोप, पश्चिम एशिया, नवउष्णकटिबंधीय और कैरेबियाई में अंतरराष्ट्रीय जलपक्षी जनगणना के अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ समानांतर चलता है।

पृष्ठभूमि

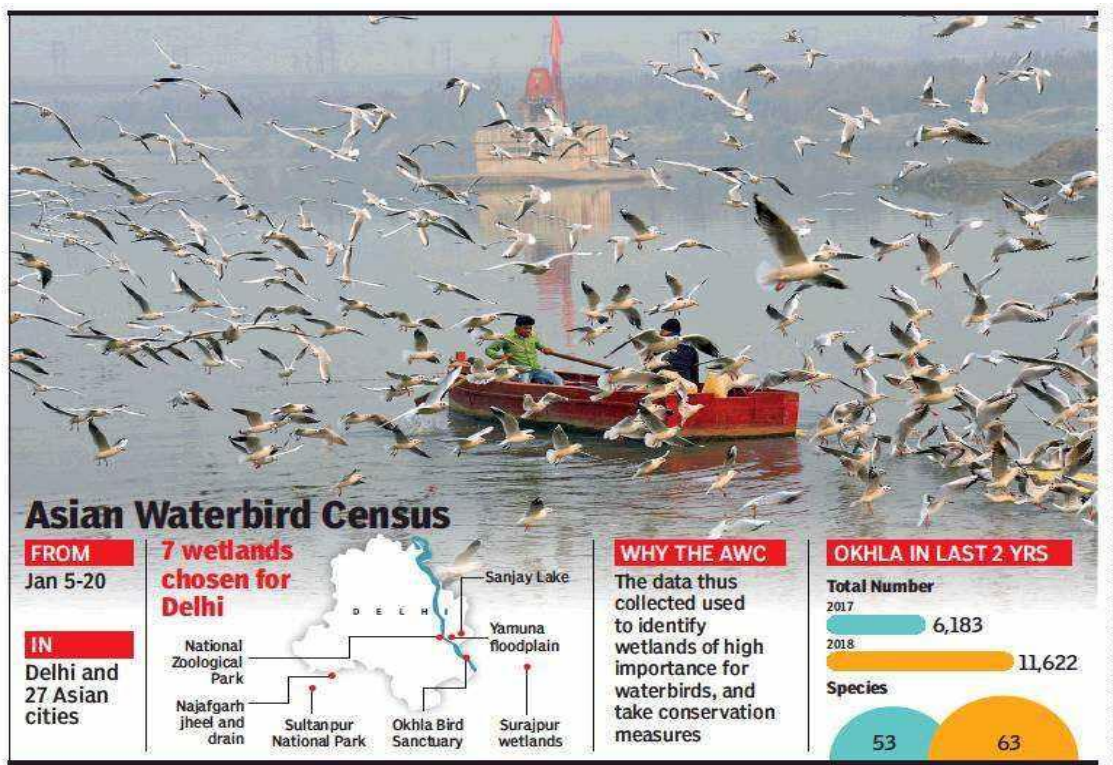
- भारतीय उपमहाद्वीप में AWC की शुरुआत 1987 में हुई थी तब से इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। तबसे इसने एशिया के प्रमुख क्षेत्र, पूर्व में अफगानिस्तान से लेकर जापान, दक्षिणपूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया को आच्छादित कर लिया है।
- इस तरह से यह जनगणना पूरे पूर्व एशिया- ऑस्ट्रेलेशियाई फ्लाईओवर और मध्य एशियाई फ्लाईओवर के बड़े हिस्से को आच्छादित कर चुकी है।
- इस जनगणना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
 - नमभूमियों में जलपक्षी जनसंख्याओं की वार्षिक आधार पर सूचना हासिल करना। यह अधिकांश प्रजातियों के गैर-प्रजनन समय के दौरान (जनवरी) के दौरान होना चाहिए जिससे स्थलों के मूल्यांकन और जनसंख्याओं की निगरानी के लिए आधार तय हो सके।
 - नमभूमियों की स्थितियों की वार्षिक आधार पर निगरानी करना
 - नागरिकों के मध्य जलपक्षियों और नमभूमियों में ज्यादा रुचि को प्रोत्साहित करना।

महत्व

- इस तरह से एकत्रित की गई सूचना सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के वृहद स्तर को उपलब्ध होती हैं। इससे स्थानीय से वैश्विक स्तर पर संरक्षण गतिविधियों में योगदान होता है जिसमें शामिल हैं:
 - a. जलपक्षियों और जलपक्षी संरक्षण मामलों पर जागरूकता पैदा करना
 - b. नमभूमियों में स्थानीय संरक्षण गतिविधियों को समर्थन करना
 - c. नमभूमियों पर रामसर संधि, अंतरराष्ट्रीय महत्व की नमभूमियों की पहचान और निगरानी में

- d. प्रवासी प्रजातियों पर संधि (CMS), प्रवासी जलपक्षियों और उनके आवासों की स्थिति की निगरानी के द्वारा
- e. जैववैज्ञानिक विविधता पर संधि (CBD) के जैवविविधता के संरक्षण और सतत प्रयोग के लक्ष्य में
- f. महत्वपूर्ण और फ्लाइवे नेटवर्क स्थलों की निगरानी के द्वारा पूर्व एशियाई-ऑस्ट्रेलेशियाई फ्लाइवे साझेदारी पहल (EAAFP) और मध्य एशियाई फ्लाइवे कार्ययोजना के क्रियान्वयन से
- g. पक्षी जीवन अंतरराष्ट्रीय का महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBA) कार्यक्रम
- h. IUCN/पक्षीजीवन अंतरराष्ट्रीय का वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम (लाल सूची)
- i. नमभूमि अंतरराष्ट्रीय का जलपक्षी जनसंख्या आकलन कार्यक्रम

भारत और एशियाई जलपक्षी जनगणना



भारत में शामिल स्थल

- यह कई स्थलों को शामिल करता है जिसमें शामिल हैं कोरिंगा वन्यजीवन अभ्यारण्य, कोल्लेरु झील और कृष्णा अभ्यारण्य।
- गोदावरी मुहाना, कुम्भाभिसेखम कीचड़दार भूमि, कोरोमंडल औद्योगिक क्षेत्र के विपरीत नमभूमि और अन्य महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBAs) को भी शामिल किया गया है।
- इस जनगणना में, भारतीय स्किमर मुख्य चिंता का कारण है। इसके लिए ज्यादा अध्ययन की जरूरत है जिससे स्थापित हो सके कि यह प्रजाति काकीनाड़ा तट पर प्रजनन करती है जो बड़ी संख्या में भारतीय स्किमर के लिए सहायक है।

भारतीय स्किमर के बारे में (रिनचॉप्स एल्बीकोलिस)

- यह एक जल पक्षी प्रजाति है।
- भारत में, इस प्रजाति को मध्य भारत में चंबल नदी के पास देखा जा सकता है, साथ ही ओडीशा के कुछ भागों और आंध्र प्रदेश में भी।

संरक्षण की स्थिति

- इन पक्षियों को IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में अधिसूचित किया गया है।

संबंधित सूचना

बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) के बारे में

- यह संपूर्ण भारत का वन्यजीवन अनुसंधान संगठन है और 1883 से प्रकृति के संरक्षण के कार्य को प्रोत्साहित कर रहा है।

मिशन

- प्रकृति का संरक्षण, मूलतः जीववैज्ञानिक विविधता जिसके लिए अनुसंधान, शिक्षा और लोक जागरूकता के आधार पर कार्य किया जाता है।

दृष्टि

- प्रमुख स्वतंत्र वैज्ञानिक संगठन जिसका वृहद आधार है, यह संकटग्रस्त प्रजातियों और आवासों के संरक्षण में पारंगत है।

विषय- सामान्य अध्ययन III- पर्यावरण एवं जैवविविधता

स्रोत- द हिंदू

बर्ड फ्लू: दिल्ली की संजय झील 'सतर्क क्षेत्र' घोषित

खबर में क्यों है?

- हाल में, दिल्ली की संजय झील को बर्ड फ्लू की वजह से परिसरों में 10 बतखों की मौत के बाद 'सतर्क क्षेत्र' घोषित कर दिया गया।

संबंधित सूचना

बर्ड फ्लू अथवा एवियन इन्फ्लूएंजा के बारे में

- यह एक नाम है जिसका प्रयोग वायरल संक्रमण को बताने के लिए किया जाता है जो मुख्य रूप से पक्षियों में देखा जाता है लेकिन इसके मानवों और अन्य जानवरों को प्रभावित करने की क्षमता है।

बर्ड फ्लू अथवा एवियन इन्फ्लूएंजा की उत्पत्ति

- इस वायरस को पहली बार 1996 में चीन में कलहंस में पाया गया था।
- तबसे, नियमित तौर पर यह रोग पूरी दुनिया में फैलता रहता है। भारत में 2006 में नानदरबार, महाराष्ट्र में इस वायरस की उपस्थिति की पुष्टि हुई थी।

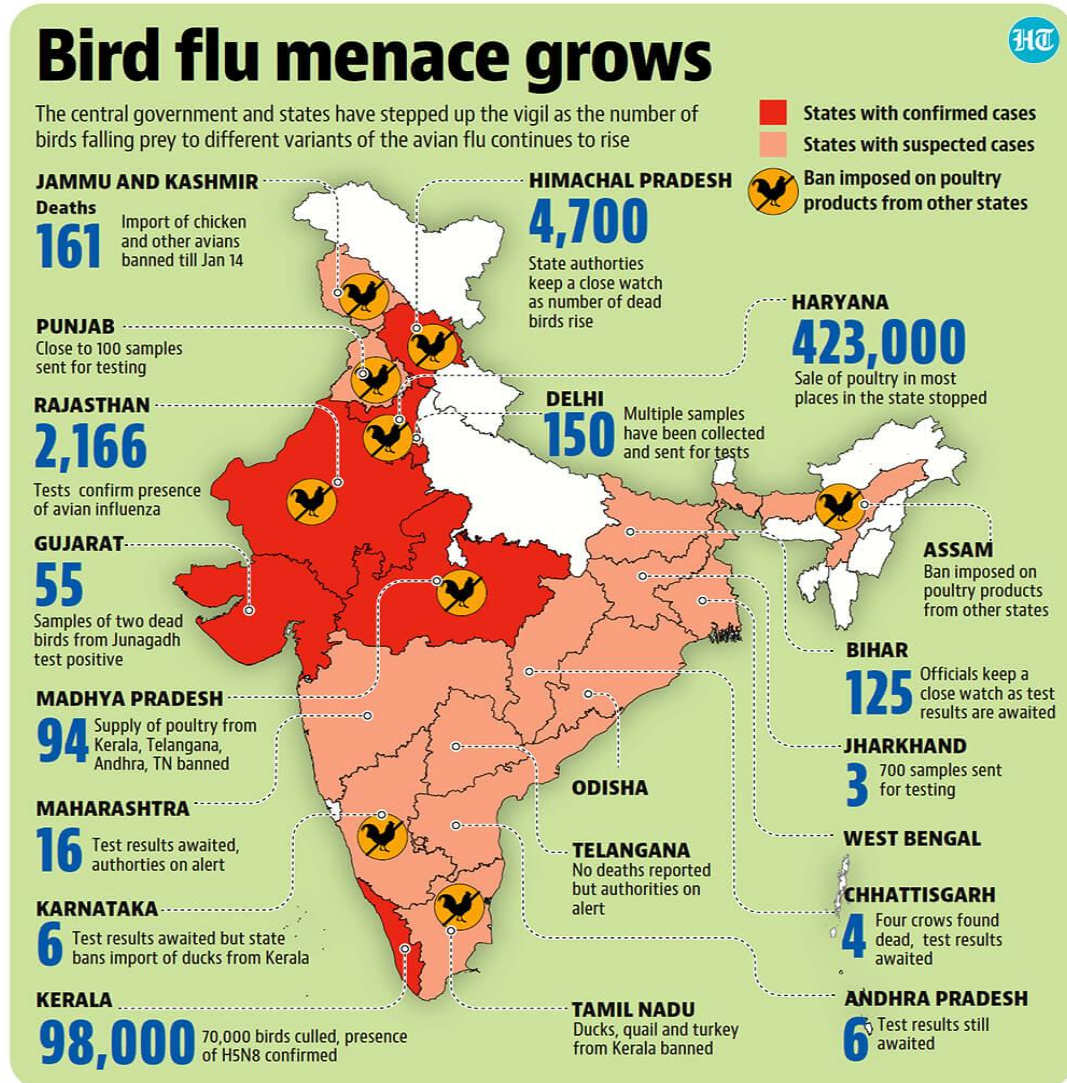
संप्रेषण

मानव संप्रेषण

- H5N1 वायरस एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जा सकता है और संक्रमित पक्षियों से मानव को संक्रमण हो सकता है।
- मानवों में H5N1 संक्रमण का पहला मामला हांगकांग में 1997 में दर्ज किया गया, जब पोल्ट्री के कर्मचारी ने संक्रमित पक्षियों से यह संक्रमण पाया।

मानव से मानव का संक्रमण

- मानवों में उच्च मृत्यु दर लगभग 60% है जोकि बर्ड फ्लू के फैलने की चिंता का मुख्य कारण है।
- लेकिन, इसके वर्तमान रूप में, मानव से मानव को संक्रमण ज्ञात नहीं है- मानव संक्रमण केवल उन लोगों में दर्ज किया गया है जिन्होंने संक्रमित पक्षियों अथवा उनके शवों को संभाला है।



सामान्य स्ट्रेन

- वायरस का सबसे सामान्य स्ट्रेन जोकि पक्षियों में गंभीर श्वांस की बीमारी पैदा कर देता है H5N1 है; कई अन्य स्ट्रेन जैसे H7, H8 भी संक्रमण पैदा करते हैं।



भारत में वर्तमान स्थिति

- हाल में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल से सैंपल वायरस के A स्ट्रेन (H5N5) के लिए धनात्मक आया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के सैंपल ने A (H5N1) की उपस्थिति को दर्शाया है।
- अधिकांश संक्रमण जंगली पक्षियों, कौओं अथवा प्रवासी पक्षियों में दर्ज किये गये हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- द हिंदू

स्याहगोश को गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के बहाली कार्यक्रम में रखा गया

खबर में क्यों है?

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने हाल में स्याहगोश के लिए एक बहाली कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। यह एकीकृत वन्यजीवन आवास विकास (IDWH) योजना के अंतर्गत है।
- स्याहगोश को जोड़ने के साथ ही, अब गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के बहाली कार्यक्रम में 22 प्रजातियां होंगी।



स्याहगोश के बारे में

- यह मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है जो अफ्रीका, मध्य-पूर्व, मध्य एशिया और भारत की स्थानीय निवासी है।
- इसकी विशेषता मजबूत शरीर, लंबे पैर, छोटा मुँह, लंबे गुच्छेदार कान और लंबे कुक्कुरीय दांत हैं।
- भारत में यह जंगली बिल्लियां राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं।
- कच्छ के अर्ध बंजर क्षेत्र भी भारत में इन बिल्ली प्रजातियों के दो आवासों में से एक है।

संरक्षण की स्थिति

- अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ (IUCN) स्याहगोश को 'सबसे कम चिंता' वाली प्रजातियों के रूप में अधिसूचित करती हैं क्योंकि ये अफ्रीका में बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। लेकिन भारत में यह 'संकटग्रस्त' के रूप में अधिसूचित हैं।
- ये प्रजातियां वन्यजीवन (संरक्षण) कानून 1972 की अनुसूची I में अधिसूचित की गई हैं।

गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के बहाली कार्यक्रम के बारे में

- यह एकीकृत वन्यजीवन आवास विकास (IDWH) के तीन घटकों में से एक है।

एकीकृत वन्यजीवन आवास विकास

- इसकी शुरुआत 2008-09 में केंद्रीय प्रायोजित योजना के तौर पर हुई थी।

- यह संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीवन अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और बाघ रिजर्वों को छोड़कर समुदाय रिजर्व), संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवन के संरक्षण और गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और आवासों के बचाने के बहाली कार्यक्रम को सहायता प्रदान करने के लिए है।

बहाली कार्यक्रम के अंतर्गत 22 वन्यजीवन प्रजातियां हैं:

- पहाड़ी तेंदुआ, बस्टर्ड (फ्लोरिकैंस सहित), डॉल्फिन, हंगुल, नीलगिरि तह, समुद्री कछुए, इयूगांग, एडीबल नेस्ट स्विफ्टलेट, एशियाई जंगली भैंसे, निकोबार मेगापोड, मणिपुर के ब्रो एंटलर्ड हिरण, गिद्ध, मालाबार गंधबिलाव, भारतीय गैंडे, एशियाई शेर, बारहसिंगा, जर्डनी क्षिप्रचला, उत्तरी नदी टेरेपिन, धूमिल तेंदुए, अरब सागर कूबड़ वाली व्हेल, लाल पांडा और स्याहगोश।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- PIB

भारतीय चिड़ियाघरों का प्रबंधन प्रभावीपन मूल्यांकन (MEE-ZOO)

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भारतीय चिड़ियाघर प्रबंधन प्रभावीपन मूल्यांकन (MEE-ZOO) ढांचा की शुरुआत की है।



MEE-ZOO ढांचे के बारे में

- यह एक ढांचा है जो देश के चिड़ियाघरों के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश, मानदंड और संसूचकों को प्रस्तावित करता है जिसके लिए प्रबंधन प्रभावीपन मूल्यांकन प्रक्रिया (MEE-ZOO) का प्रयोग किया जाता है। यह इस तरह से किया जाता है कि यह असतत, संपूर्ण और स्वतंत्र रहे।
- आकलन मानदंड और संसूचक पारंपरिक संकल्पनाओं के परे देखते हैं, जिसमें पशु कल्याण, पशुपालन और संसाधनों और वित्त की सततता के मामले शामिल होते हैं।
- MEE-ZOO अभ्यास पूरे भारत में चिड़ियाघरों के लिए उच्च मानक विकसित करने की ओर बढ़ रहा है और साथ ही यह जवाबदेही, पारदर्शिता, नवाचार, तकनीक के प्रयोग, सहयोग और निष्ठा के केंद्रीय मूल्यों का पालन कर रहा है जिससे संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के शासनादेश को हासिल किया जा सके।

संबंधित सूचना

- हाल में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने देश में 146 राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीवन अभ्यारण्यों के लिए प्रबंधन प्रभावीपन मूल्यांकन (MEE) को जारी किया।

देश में राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीवन अभ्यारण्यों के प्रबंधन प्रभावीपन मूल्यांकन के बारे में

- वर्तमान में, भारत में पूरे देश के अंदर 903 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है जोकि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5% कवर करता है।

- संरक्षित क्षेत्रों के सामर्थ्य के आकलन के लिए, प्रबंधन प्रभावीपन का मूल्यांकन जरूरी है।

संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन प्रभावीपन मूल्यांकन (MEE)

- संरक्षित क्षेत्र प्रबंधकों के लिए प्रमुख टूल के रूप में उभरे हैं और सरकारों और अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन प्रणालियों की मजबूती और कमजोरियों को समझने के लिए प्रयोग किये जाते हैं।
- वर्तमान आकलन के परिणाम उत्साहवर्धक हैं जिनका कुल माध्य MEE स्कोर 62.01% है, जोकि वैश्विक माध्य के 56% से ज्यादा है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- PIB

एक ग्रह शिखर सम्मेलन 2021

खबर में क्यों है?

- हाल में, फ्रांस के राष्ट्रपति ने वर्चुअल रूप से एक ग्रह शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य मौसम परिवर्तन और जैवविविधता और पारिस्थितिकीयतंत्रों के संरक्षण पर चर्चा करना था।
- पूर्व में इस शिखर सम्मेलन को दक्षिणी फ्रांसीसी बंदरगाह शहर मर्सीय में 2020 में होना निश्चित था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया था।



एक ग्रह शिखर सम्मेलन 2021 के बारे में

- इसका आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के साथ सहयोग में किया जा रहा है।
- इस शिखर सम्मेलन का आयोजन “प्रकृति के लिए मिलकर कार्य करें” नामक थीम के अंतर्गत हो रहा है।

जीवन के संरक्षण के लिए चार प्रमुख थीमों का चुनाव किया गया है।

भूमि और समुद्री पारिस्थितिकीय प्रणालियों का संरक्षण करना

- भूमि और समुद्री पारिस्थितिकीय प्रणालियों का संरक्षण जैवविविधता के पक्ष में कार्रवाई में एक जरूरी स्तम्भ है। संरक्षित क्षेत्र, और वहां रहने वाली प्रजातियों का संरक्षण, जैवविविधता के संरक्षण और पुनरोद्धार में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं और वर्तमान प्रवृत्ति को उलटने को हासिल करने में एक निर्धारक कारक होंगे।

कृषि पारिस्थितिकी को प्रोत्साहन

- कृषि पारिस्थितिकी को बढ़ावा प्रदूषण को घटाकर पारितंत्रों की विविधता के संरक्षण को संभव बनाते हैं जबकि इसके साथ ही ज्यादा नौकरियों का सृजन होता है और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।
- यह शिखर सम्मेलन सहारा और साहेल के लिए महान हरित दीवार के क्रियान्वयन को तीव्र करने पर जोर देगा।

जैवविविधता के संरक्षण के लिए वित्तीयन को बढ़ावा देना

- जैवविविधता के लिए वित्तीयन की लामबंदी प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से पारितंत्रों के संरक्षण, सतत प्रबंधन और पुनरोद्धार के लिए परियोजनाओं की ओर ज्यादा प्रत्यक्ष सार्वजनिक और निजी निवेश के लिए नवाचार वित्तीयन और पहलों की नई प्रतिबद्धताओं के साथ अथवा मौसम और जैवविविधता के लिए सार्वजनिक वित्तीयन के जरूरी संमिलन के लिए।

निर्वनीकरण और मानवों एवं जानवरों के स्वास्थ्य के बीच में संबंधों की पहचान करना

- निर्वनीकरण, प्रजातियों और मानव स्वास्थ्य के बीच में संबंध लोगों की निगाह में है।
- भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए मिलकर बेहतर कार्य को यह शिखर सम्मेलन संभव बनाएगा। इसके लिए निर्वनीकरण के खिलाफ लड़ाई और जंगली प्रजातियों के साथ हमारे संपर्क से संबंधित जोखिमों की रोक की जाएगी।

एक ग्रह शिखर सम्मेलन के बारे में

- यह फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष की एक पहल है।

लक्ष्य

- इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य **पेरिस मौसम समझौते (COP 15)** के क्रियान्वयन में तेजी लाना है।
- पहले एक ग्रह शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस में 2017 में किया गया था जिसका मुख्य ध्येय **“आइये उस समय तक इंतजार न करें जबतक कार्य करने में बहुत देर न हो जाए”**।
- **2018 और 2019** के शिखर सम्मेलन क्रमशः **न्यूयॉर्क और नौरोबी** में हुए थे।

नोट:-

- शिखर सम्मेलन ने **प्रेजोड** नामक कार्यक्रम की शुरुआत की थी जोकि **पशुजन्य रोगों और महामारियों** के उभरने से रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पहल है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

2020 में इंडो-गांगेय मैदान के शहरों में बुरी वायु की तुल्यकालिक बढ़ोतरी: CSE विश्लेषण

खबर में क्यों है?

- 2020-2021 के जाड़े के दौरान इंडो-गांगेय मैदान के शहरों में वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई। यह पूरे देश में लॉकडाउन लगे होने के बावजूद रहा। लेकिन, यह वृद्धि तुल्यकालिक थी और **CSE** विश्लेषण के अनुसार विभिन्न अनुक्रमों को दर्शाया।

- इस विश्लेषण को दिल्ली आधारित गैर लाभकारी विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र **(CSE)** ने किया और यह भी दर्शाया कि मैदान के छोटे शहरों में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ा है।
- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार से पूरे उत्तरी भारत में 26 शहरों को विश्लेषण के लिए चुना गया।
 - अमृतसर
 - भटिंडा
 - जालंधर
 - खन्ना
 - मंडी
 - गोबिंदगढ़
 - पटियाला
 - रूपनगर
 - चंडीगढ़
 - अंबाला
 - फतेहगढ़
 - हिसार
 - कैथल
 - कुरुक्षेत्र
 - पंचकुला
 - सिरसा
 - यमुनानगर
 - आगरा
 - कानपुर
 - मुरादाबाद
 - वाराणसी
 - लखनऊ
 - पटना
 - मुजफ्फरनगर और हाजीपुर

विशेष की खास बातें

- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्र की आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल- वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से प्राप्त ग्रेनुलर वास्तविक समय आंकड़े के आधार पर, इस आंकड़े को 11 जनवरी 2021 तक विश्लेषित किया गया था।
- कुल पार्टिकुलेट मैटर **(PM2.5)** औसत चल रही लॉकडाउन और प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के स्थगन की वजह से नीचे था। फिर भी, यह चिंता का कारण है।

अनुशंसाएं

विशेषज्ञों के अनुसार निम्नलिखित कदम से समस्या से निपटा जा सकता है:

- पूरे राज्यों में विद्युत संयंत्र मानकों को लागू करना
- कोयले और अन्य प्रदूषक ईंधनों का न्यूनतम प्रयोग (उत्सर्जन नियंत्रणों में सुधार करना)

- सार्वजनिक परिवहन और वाहन पर रोक लगाने वाले उपाय को बढ़ाना और अवशिष्ट का इस तरह से प्रबंधन कि शून्य अवशिष्ट हो और शून्य लैंडफिल रणनीति हो।

विषय- सामान्य अध्ययन III- (पर्यावरण)

स्रोत- डाउन टू अर्थ

अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2020

खबर में क्यों है?

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने हाल में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2020 के 5वें संस्करण को जारी किया है।



अनुकूलन के बारे में

- यह मौसम परिवर्तन पर पेरिस समझौते के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है।
- इसमें शामिल हैं मौसम से संबंधित आपदाओं से देशों और समुदायों की कमजोरियों को कम करना और क्षमता को बढ़ाना।
- इस क्षमता को राष्ट्रीय प्रयासों और वित्तीय तंत्रों के द्वारा निर्मित किया जाएगा।

लक्ष्य

- रिपोर्ट का लक्ष्य अनुकूलन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को इंगित करना।

रिपोर्ट के प्रमुख परिणाम

वित्त

- मौसम परिवर्तन के प्रभावों से अनुकूलन की वार्षिक लागत विकासशील देशों के लिए 2050 तक कम से कम चार गुना ज्यादा अनुमानित की गई है।
- विकासशील देशों में वार्षिक अनुकूलन लागत \$70 अरब के स्तर पर काफी ज्यादा है, जबकि वर्तमान में अनुकूलन के लिए वार्षिक लागत \$30 अरब है।
- अनुकूलन की लागत में शामिल हैं अनुकूलन उपायों की योजना, तैयार करना, सुगम बनाना और क्रियान्वयन करना।
- वास्तविक संदर्भ में अनुकूलन लागत विकसित देशों में ऊंची हैं, लेकिन विकासशील देशों के लिए अनुकूलन का बोझ ज्यादा है जोकि उनके सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में है।

तापमान में बढ़ोतरी

- इस शताब्दी में दुनिया कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की ओर बढ़ रही है। यद्यपि देश वैश्विक उष्णता को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर सीमित करने में कामयाब हो सकते हैं, और यहां तक कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, गरीब देशों को नतीजे भुगतने होंगे।

महामारी का प्रभाव

- कोविड-19 महामारी से देशों के अनुकूलन कार्यों के वित्तीयन और क्रियान्वयन करने की क्षमता प्रभावित होने की संभावना है।
- यह गैर समानुपातिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर देशों और जनसंख्या समूहों को प्रभावित करेगा।

संबंधित सूचना

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र का अग्रणी वैश्विक पर्यावरणीय प्राधिकरण है जो वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा को तय करता है, सतत विकास के पर्यावरणीय आयामों के ठीक क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करता है।
- इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है।

यह सात वृहद विषय क्षेत्रों में कार्य करता है:

- i. मौसम परिवर्तन,
- ii. आपदाएं एवं संघर्ष,
- iii. पारितंत्र प्रणाली प्रबंधन,
- iv. पर्यावरणीय शासन,
- v. रसायन और अपशिष्ट,
- vi. संसाधन समर्थन, और
- vii. समीक्षा के अंतर्गत पर्यावरण

UNEP की अन्य रिपोर्ट

- वैश्विक पर्यावरण दृष्टि
- उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट
- वायु गुणवत्ता पर कार्यवाही एवं पर्यावरणीय अपराध रिपोर्ट में बढ़ोतरी (INTERPOL के साथ)

नोट:

- UNEP ने हाल में नेतृत्व श्रेणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “चैम्पियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार” से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें उनके अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को आगे बढ़ाने के अद्वितीय कार्य और 2022 तक भारत में सभी एकल प्रयोग प्लास्टिक को समाप्त करने की आसाधारण शपथ के लिए दिया गया।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

भारतीय स्टार कछुए

खबर में क्यों है?

- वन विभाग के अधिकारियों ने हाल में आंध्र प्रदेश से ओडिशा तस्करी किये जा रहे 414 ज़िंदा संकटग्रस्त भारतीय स्टार कछुओं को जल्द किया है।

भारतीय स्टार कछुओं के बारे में

- भारतीय स्टार कछुए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाये जाते हैं, विशेष रूप से भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में, पश्चिम पाकिस्तान और श्रीलंका में।
- वे मानसून के मौसम के आदी हैं।
- इन कछुओं को उनके तारा अनुक्रम वाले खोलों के द्वारा पहचाना जाता है।



संरक्षण की स्थिति

- इन्हें IUCN की लाल सूची के अनुसार **कमजोर** के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- इन्हें **वन्यजीवन संरक्षण कानून 1972** की अनुसूची IV और **प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर संधि (CITES): परिशिष्ट I** के अंतर्गत संरक्षित किया गया है।

खतरे

- यह दुनिया में ताजाजल कछुए की सबसे ज्यादा जब्त की जाने वाली प्रजाति है।
- इसे कृषि से आवास को नुकसान और पालतू व्यापार के लिए गैरकानूनी संचय जैसे खतरे हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

ZSI का कहना है कि सुंदरबन में पक्षियों की 428 प्रजातियां निवास करती हैं

खबर में क्यों है?

- भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (ZSI) के हाल के प्रकाशन के अनुसार भारतीय सुंदरबन, जोकि वैश्विक रूप से सबसे बड़ा मैंग्रोव वन का हिस्सा है, में पक्षियों की 428 प्रजातियां निवास करती हैं।

सुंदरबन बायोमंडल रिजर्व के पक्षी

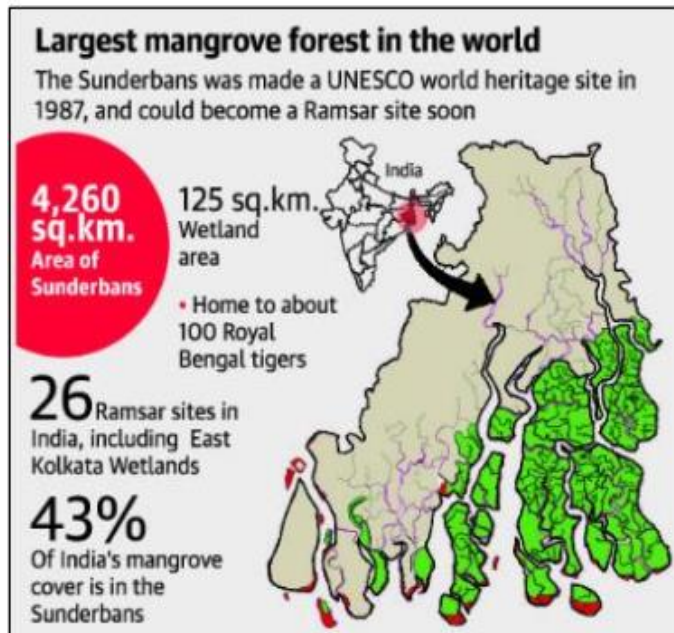
- प्रकाशन, सुंदरबन बायोमंडल रिजर्व के पक्षी, जिसे **ZSI** ने जारी किया है, सुंदरबन के पक्षी प्राणिजात का प्रलेखन करता है और इस क्षेत्र के लिए समग्र फोटोग्राफिक फील्ड गाइड का कार्य करता है।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि सूचीकृत 428 पक्षी, कुछ जैसे कि मास्कड फिनफुट और बफी फिश उल्लू, केवल सुंदरबन में ही पाये जाते हैं।
- देश में पाई जाने वाली **किंगफिशर और विरल प्रजातियां जैसे गोलिण्थ हेरोन और स्पून बिल्ड सैंडपाइपर** की 12 में से 9 प्रजातियां इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं।

भारतीय सुंदरबन के बारे में

- भारतीय सुंदरबन को 1987 में **UNESCO** विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, इसे जनवरी 2019 में रामसर संधि के अंतर्गत 'अंतरराष्ट्रीय महत्व की नमभूमि' और 1989 में एक बायोमंडल रिजर्व घोषित किया गया था।



- यह क्षेत्र वृहद स्तर के प्राणिजात के लिए जाना जाता है, जिसमें 260 पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। साथ ही यहां कई विरल और वैश्विक रूप से संकटग्रस्त वन्यजीवन प्रजातियां जैसे कि एस्चुएराइन मगरमच्छ, रॉयल बंगाल बाघ, जलीय मॉनीटर छिपकली, गांगेय डाल्फिन और ऑलिव रिडले कछुए शामिल हैं।



संरक्षण की स्थिति

- इसके संरक्षण के लिए, डिस्कवरी इंडिया और विश्व व्यापी कोष (WWF) भारत ने 2019 में सुंदरबन में स्थानीय समुदायों और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साझेदारी की है।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

वायु गुणवत्ता आयोग ने निर्णय समर्थन प्रणाली के गठन के लिए सर्वोच्च तकनीकी संस्थानों की सेवाएं लीं

खबर में क्यों है?

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वेब, GIS और बहु मॉडल आधारित प्रचालनात्मक एवं योजना निर्णय समर्थन टूल के साथ एक निर्णय समर्थन प्रणाली (DSS) के गठन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

निर्णय समर्थन प्रणाली के बारे में

- यह टूल विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जनों के स्थैतिक एवं गत्यात्मक विशेषताओं को पकड़ने में महती सहायता करेगा।
- रासायनिक परिवहन मॉडल का प्रयोग करके दोनों प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रदूषकों के निपटारे के लिए इसमें एक एकीकृत ढांचा होगा।
- यह प्रणाली ढांचे के साथ स्रोत-विशेष हस्तक्षेपों का भी निपटारा करेगी जिससे हस्तक्षेपों के लाभों का आकलन किया जाएगा। यह विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के लिए समग्र प्रयोग हितैषी और सरल प्रारूप में बेहतर परिणामों को प्रस्तुत करने पर जोर देगी।

संबंधित सूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और जुड़े हुए क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर आयोग के बारे में

- इस आयोग की अध्यक्षता एक पूर्णकालिक अध्यक्ष द्वारा की जाएगी जो भारत सरकार में सचिव अथवा राज्य सरकार में मुख्य सचिव रहा होगा।
- कार्यकाल:** अध्यक्ष इस पद पर तीन वर्षों के लिए होगा अथवा जब उसकी आयु 70 वर्ष की हो जाएगी।
- इस आयोग में विभिन्न मंत्रालयों साथ ही सभी हितधारक राज्यों से प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
- इसमें **CPCB**, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (**ISRO**) और नागरिक समाज से विशेषज्ञ होंगे।

शक्तियां

- वायु प्रदूषण और वायु गुणवत्ता प्रबंधन में, आयोग सभी वर्तमान निकायों जैसे कि **CPCB**, और यहां तक कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से भी ऊपर होगा।
- इसे राज्यों को निर्देश देने का अधिकार होगा।
- यह आयोग वायु प्रदूषण पर रोक लगाने और क्षेत्र के लिए गुणवत्ता मानदंडों को बनाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों के साथ समन्वय करेगा।
- इसे कमजोर क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को रोकने का अधिकार होगा और यह औद्योगिक इकाइयों की स्थल जांच को करने में सक्षम होगा।
- यदि इसके निर्देशों का उल्लंघन होता है, आयोग को **₹. 1 करोड़ तक का अर्थदंड और 5 वर्ष तक का कारावास देने का अधिकार होगा।**

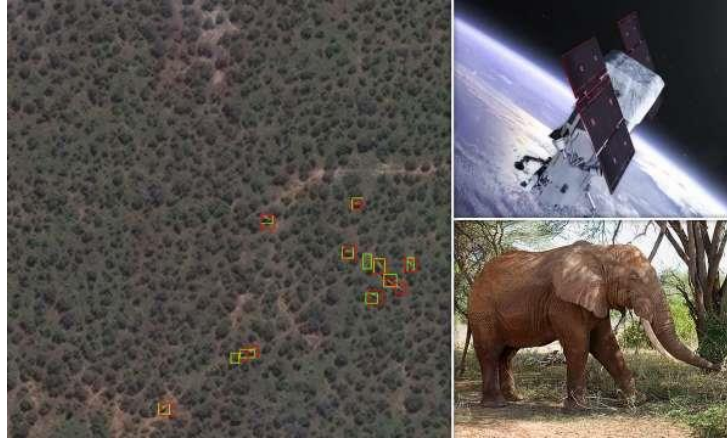
विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- PIB

अंतरिक्ष से हाथियों की गणना

खबर में क्यों है?

- हाल में, ऑक्सफोर्ड वन्यजीवन संरक्षण अनुसंधान इकाई विश्वविद्यालय और मशीन लर्निंग अनुसंधान समूह के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अंतरिक्ष से दक्षिण अफ्रीकी हाथियों की पहचान की।



प्रमुख खास बातें

- वैज्ञानिक काफी उच्च पृथ्थकरण उपग्रह चित्रों का प्रयोग वन्यजीवन प्रजातियों की पहचान और गणना के लिए कर रहे हैं।
- वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग इस सटीकता के साथ कर रहे हैं कि इसकी तुलना मानव पहचान क्षमताओं से की जा सकती है।
- नई विधि के परीक्षण के लिए, अनुसंधानकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका में अड्डो हाथी राष्ट्रीय पार्क को चुना है।
- वैज्ञानिकों ने उपग्रह चित्रों का प्रयोग किया जिनको हाथियों की निगरानी के लिए भूमि पर उपस्थित रहने की जरूरत नहीं है।

अनुसंधानकर्ताओं ने उच्चतम पृथ्थकरण उपग्रह चित्र का प्रयोग किया जो वर्तमान में उपलब्ध हैं, जिन्हें **वर्ल्ड व्यू3** कहा जाता है।

अड्डो हाथी राष्ट्रीय पार्क के बारे में

- यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा पार्क है।
- यह पार्क जुरबर्ग पहाड़ों के ऊपर अर्ध बंजर कारू के उत्तर से सनडेज नदी घाटी के द्वारा तट तक जाता है, यह सनडेज और बुशमैन्स नदियों के मुखों के बीच में स्थित है।
- यह बड़े हाथी समूहों के अवशेषों को संरक्षित करता है जो किसी समय पूर्वी केप में घूमा करते थे।

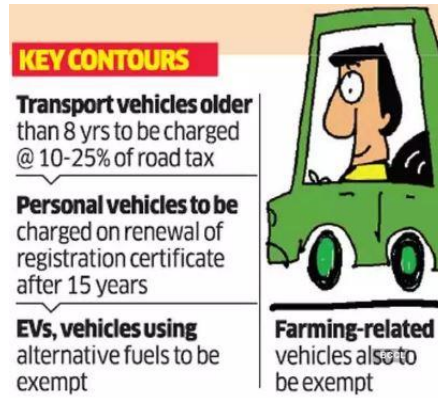
विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

15 वर्षों से पुराने वाहनों पर हरित कर (Green Tax)

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने पुराने वाहनों पर 'ग्रीन टैक्स' लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- यह नीति 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी।



ग्रीन टैक्स क्या है?

- ग्रीन टैक्स, या प्रदूषण कर या पर्यावरण कर, जो भी कहें, पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनने वाले सामानों पर उत्पाद शुल्क है।
- यह माना जाता है कि उत्सर्जन पर कर लगाने से फर्मों और घरों में बदलाव लाने में मदद मिलेगी।
- प्रदूषण पैदा करने वाले उत्सर्जन पर कर लगाने से घरों और कंपनियों, जिन्हें अपना प्रदूषण कम करने की आवश्यकता है, में व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित कर, एक किफायती ढंग से पर्यावरण नुकसानों को कम करने में मदद मिलेगी।
- ग्रीन टैक्स को प्रदूषण कर या पर्यावरण कर भी कहा जाता है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनने वाले सामानों पर लगाया जाने वाला कर है।

ग्रीन टैक्स का उद्देश्य

- यह कर लोगों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वाहनों का उपयोग करने से हतोत्साहित करेगा। यह उन्हें नए, कम प्रदूषण वाले वाहनों का उपयोग करने, समग्र प्रदूषण स्तर को कम करने और इसके लिए प्रदूषण का भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगा।

निम्नलिखित श्रेणियों में वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू किया जाएगा:

- 8 वर्षों से पुराने यातायात वाहनों पर उनके फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराते समय सड़क कर का 10-15% लगाया जाएगा।
- 15 साल के बाद पंजीकरण प्रमाणन के नवीनीकरण के समय निजी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।
- सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे सिटी बसों पर कम कर लगाया जाना जाएगा।
- दिल्ली-एनसीआर जैसे अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों के लिए **रोड टैक्स के 50% तक** उच्च ग्रीन टैक्स।
- ईंधन (पेट्रोल / डीजल) और वाहन के प्रकार के आधार पर अलग-अलग कर।

ग्रीन टैक्स का इस्तेमाल कैसे होगा?

- ग्रीन टैक्स से एकत्रित राजस्व को एक अलग खाते में रखा जाएगा।
- इस राशि का उपयोग प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए किया जाएगा।

- राज्य उत्सर्जन की निगरानी के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं को स्थापित करने के लिए भी कर का उपयोग करेंगे।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना

खबर में क्यों है?

- हाल में, पर्यावरण वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने 'समुद्री वृहद वनस्पतिजात स्ट्रेण्डिंग दिशा-निर्देश' और 'राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना' जारी की।



राष्ट्रीय कछुआ कार्य योजना के बारे में

- इस दस्तावेज में संरक्षण के लिए अंतर-क्षेत्रीय कार्य के तरीके और माध्यम शामिल हैं।
- यह सरकार, नागरिक समाज और सभी प्रासंगिक हितधारकों के बीच समुद्री स्तनपायियों के फंसने, चोट अथवा मौत एवं साथ ही समुद्री कछुओं के संरक्षण के मामलों पर प्रतियुत्तर के लिए सुधरे हुए समन्वय के लिए सुझाव भी देता है।

समुद्री कछुओं के संरक्षण की जरूरत

- भारत में समुद्री आवासों की जबर्दस्त आर्थिक, पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बावजूद, समुद्री वृहद वनस्पतिजात प्रजातियां एवं समुद्री कछुएं फंसने सहित वृहद किस्म की चुनौतियों का सामना करते हैं।
- इस तरह की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का प्रबंधन करने के लिए समन्वय, कार्ययोजना और लोगों की भागीदारी की जरूरत है जो कि समुद्री प्रजातियों और उनके आवासों के दीर्घावधि संरक्षण में मदद प्रदान करेंगे।

संबंधित सूचना

भारतीय तट पर समुद्री कछुए

- भारत की 8000 किमी. से भी ज्यादा लंबी तटरेखा है, जोकि जैवविविधता से परिपूर्ण है।
- मत्स्यन भूमि को पोषित करने के अतिरिक्त, भारत की तट रेखीय जल और समुद्री तट समुद्री कछुओं सहित समुद्री प्रजातियों की किस्मों के लिए भोजन ढूंढने और रहने के स्थान को उपलब्ध कराते हैं।

भारतीय तटीय जल और द्वीप समुद्री कछुओं की पांच प्रजातियों के आवास के लिए जाने जाते हैं

- ये हैं ऑलिव रिडली (लेपीडोचेलीस ओलिवासी), ग्रीन (चेलोनिया माइडस), हाक्सबिल (इरेटमोचेलिस इम्ब्रिकाटा), लॉगरहेड (करेट्टा करेट्टा) और लेदरबैक (डर्मोचेलिस कोरियासी) कछुएं।

लॉगरहेड के अतिरिक्त, चार बची हुई प्रजातियां भारतीय तट पर घोंसले बनाती हैं

- ओडिशा का तटीय राज्य जोकि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, पर अक्टूबर से अप्रैल माह के दौरान ऑलिव रिडली के दुनिया की सबसे बड़े घोंसले बनते हैं या अरिबाडा होता है।

ऑलिव रिडली कछुओं के बारे में

- यह दुनिया भर में पाये जाने वाले सबसे छोटे और सबसे बड़ी मात्रा वाले समुद्री कछुए हैं।
- ये कछुए मांसाहारी होते हैं और जैतून के रंग की पृष्ठवर्म गुहिका की वजह से उनका यह नाम है।

आवास

- ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म जल में पाये जाते हैं।

संरक्षण की स्थिति

- इन्हें IUCN लाल सूची कमजोर के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन्हें CITES के परिशिष्ट I में डाला गया है।
- इन्हें भारतीय वन्यजीवन (संरक्षण) कानून, 1972 के परिशिष्ट I में अधिसूचित किया गया है।

संरक्षण के लिए गये उठाए गए कदम

- ओडिशा सरकार ने हाल में ट्राइलों में कछुआ एक्सक्लूडर उपकरण (TEDs) प्रयोग करने को अनिवार्य कर दिया है, यह एक जाल है जिसमें एक बाहर निकलने के लिए कवर लगा होता है जो कछुओं को बाहर निकलने देता है जबकि मछलियां इसमें फंस जाती हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- PIB

2021: ज्यादा हरित ग्रह की ओर भारत-फ्रांस गठबंधन का वर्ष

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और फ्रांसीसी पारिस्थितिकीय संक्रमण मंत्री ने भारत-फ्रांस पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की है।

पर्यावरण के लिए भारत-फ्रांस वर्ष के बारे में

उद्देश्य

- इसका मूलभूत उद्देश्य सतत विकास में भारत-फ्रांस के सहयोग को मजबूत करना, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण को समर्थन देने वाले कार्यों के प्रभावीपन को बढ़ाना और उन्हें ज्यादा दृश्यता उपलब्ध कराना है।
- पर्यावरण पर भारत-फ्रांस वर्ष जोकि 2021-2022 तक मनाया जाएगा कुल पांच थीमों पर आधारित होगा:
 1. पर्यावरणीय संरक्षण
 2. मौसम परिवर्तन
 3. जैवविविधता संरक्षण
 4. सतत शहरी विकास
 5. पुनर्नवीकृत ऊर्जाओं और ऊर्जा सामर्थ्य का विकास

- यह पर्यावरण और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करने का एक प्लेटफार्म है।
- पर्यावरण मंत्रालय भारतीय पक्ष से समन्वय करेगी। इसमें वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) साथ ही विदेश मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, नव्य एवं नवीकृत ऊर्जा मंत्रालय एवं अन्य संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन शामिल होंगे।

भारत और पुनर्नवीकृत ऊर्जा

- भारत ने मौसम परिवर्तन कार्य की ओर काफी महत्वपूर्ण प्रगति की है और अभी से इसने 26% उत्सर्जन तीव्रता कटौती को हासिल कर लिया है।
- 2020 तक, भारत की पुनर्नवीकृत क्षमता 90 गीगावाट है, जिसमें 36 गीगावाट सौर ऊर्जा और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- PIB

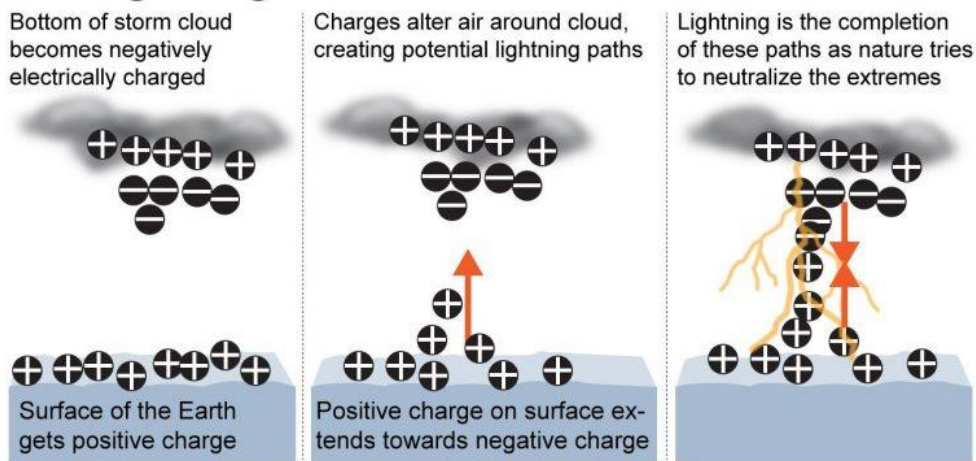
भूगोल सम्बन्धी मुद्दे

बिजली गिरना भारत में मौतों का प्रमुख कारण

खबर में क्यों है?

- हाल में, क्लाइमेट रिसिलियेंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल (CROPIC) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में प्रमुखता से दर्शाया गया है कि अप्रैल 1, 2019 से मार्च 31, 2020 के बीच में बिजली गिरने की वजह से कुल 1,771 मौतें हुई हैं।

How lightning strikes the Earth's surface



Sources: Ariel Cohen, Tina Stall; Meteorologists NOAA National Weather Service @latimesgraphics

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- 293 मौतों के साथ उत्तर प्रदेश, 248 मौतों के साथ मध्य प्रदेश, 221 मौतों के साथ बिहार, 200 मौतों के साथ ओडिशा और 172 मौतों के साथ झारखंड कुल मिलाकर कुल हुई मौतों का 60 प्रतिशत हैं।

- ये मौतें इस समयावधि के दौरान सभी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली कुल मौतों का 33 प्रतिशत हैं।
- 2018-19 की अवधि के दौरान, कुल 2800 मौतें हुईं और इस गिरावट के पीछे विभिन्न हितधारकों जिनमें CROPC शामिल है, के प्रयासों का भी हाथ है।
- रिपोर्ट सुझाव देती है कि लाइटनिंग रिसिलियेंट इंडिया अभियान में आक्रमक तरीके से भागीदारी और लाइटनिंग रिस्क मैनेजमेंट को ज्यादा समग्रता से करना होगा जिससे मौतों को घटाया जा सके।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार और अधिकांश राज्यों ने बिजली गिरने को आपदा के रूप में अधिसूचित नहीं किया है।

संबंधित सूचना

बिजली गिरने के बारे में

- यह प्राकृतिक रूप से होना वाला वैद्युतस्थिर डिस्चार्ज है जिसमें वायुमंडल अथवा भूमि में दो वैद्युत रूप से आवेशित क्षेत्र अस्थाई रूप से अपने को बराबर करते हैं, जिससे तुरंत ऊर्जा निकलती है।
- यह डिस्चार्ज वैद्युतचुंबकीय विकिरण के वृहद स्तर को उत्पादित करता है, जिसमें इलेक्ट्रानों की तेजी से गति से पैदा होने वाले गर्म प्लाज्मा से लेकर ब्लैक बॉडी विकिरण के रूप में दृश्य प्रकाश की जबर्दस्त चमक होती है।
- बिजली से गरज होती है, जोकि शॉक तरंगों से पैदा होने वाली आवाज है जोकि डिस्चार्ज के पास के क्षेत्र में गैसों के रूप में विकसित होती है जिससे अचानक स्थान का दबाव बढ़ जाता है।
- बिजली आंधी तूफान के समय सामान्यतया होती है, साथ ही अन्य प्रकार के ऊर्जामयी मौसम प्रणालियों के समय में, लेकिन ज्वालामुखी फटने के दौरान ज्वालामुखीय बिजली भी हो सकती है।

बिजली की भविष्यवाणी

- CROPC का भारतीय मौसम विभाग (IMD) के साथ एक सहमति ज्ञापन है जिसके द्वारा बिजली गरजने की पहले से ही चेतावनी दी जाती है जिसके लिए उपग्रह पर्यवेक्षणों, डॉप्लर और अन्य रडारों के नेटवर्क से इनपुट, बिजली पहचान संसूचकों साथ ही अन्य का प्रयोग किया जाता है।
- यह बिजली की भविष्यवाणी को अनूठा बनाता है जिसकी भविष्यवाणी एक सप्ताह पहले तक की जा सकती है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि मानसून पूर्व आंधी-तूफान के दौरान काफी नुकसान होता है।

बिजली गिरने से निपटने की अनुशंसाएं

- NDMA ने बिजली कार्य योजना की तैयारी के लिए समय दिशा-निर्देशों को जारी किया है, लेकिन बड़ी संख्या में मौतें यह दर्शाती हैं कि क्रियान्वयन के लिए ज्यादा वैज्ञानिक और केंद्रित समुदाय आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

- बिजली गिरने का नक्शांकन एक बड़ी सफलता है जिससे बिजली गिरने की आवृत्ति, वर्तमान तीव्रता, ऊर्जा मात्रा, उच्च तापमान और अन्य खराब प्रभावों के संदर्भ में सटीक जोखिमों को पहचान होती है।
- बिजली गिरने का मौसम विज्ञान भारत के लिए बिजली जोखिम एटलस नक्शे को देगा जोकि बिजली जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम का आधार होगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल (साथ ही आपदा प्रबंधन)

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

ज्वार-वर्षा बाढ़ गुणक

खबर में क्यों है?

- हाल में, भारतीय तकनीक संस्थान बांबे की एक टीम ने एक नये मीट्रिक अथवा मापन को प्रकल्पित किया है जिसे ज्वार-वर्षा बाढ़ गुणक कहते हैं।

ज्वार-वर्षा बाढ़ गुणक के बारे में



- यह यदि एक तटीय शहर ज्वारीय घटनाओं अथवा चरम वर्षा की वजह से बाढ़ के प्रति ज्यादा उन्मुख है, को समझने में सहायता करता है।

यह कैसे कार्य करता है?

- यह पूर्व के वर्षा आंकड़े, ज्वारीय आंकड़े और क्षेत्र की स्थलाकृति का प्रयोग करता है। इस ढांचे को कार्य कर रहे प्रमुख कारकों को समझाने में प्रयुक्त किया जा सकता है।
- टीम ने नए मीट्रिक के परीक्षण के लिए तीन भौगोलिक रूप से विविध बाढ़ उन्मुख तटीय क्षेत्रों को चुना।
 - a. मुंबई, महाराष्ट्र में मीठी जलग्रहण
 - b. ओडिशा में जगतसिंहपुर जिला
 - c. तमिलनाडु में बृहत्तर चेन्नई निगम
- इस नई विधि ने इस क्षेत्र को 'तूफान-ज्वार वर्चस्व वाला' अथवा 'वर्षा वर्चस्व वाला' क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने में मदद की।
- यह मीट्रिक आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों को बेहतर बाढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को बनाने में मदद कर सकती हैं जो कि दीर्घावधि की योजना की ओर उन्मुख हों।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल, स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

2020, 1901 के बाद का सबसे गर्म वर्ष था

खबर में क्यों है?

- हाल में, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपनी मौसम रिपोर्ट की स्थिति के बारे में कहा कि 2020, 1901 के बाद का आठवां सबसे गर्म वर्ष है।

IMD आंकड़े की प्रमुख खास बातें

वार्षिक माध्य तापमान

- 1901-2020 के दौरान देश के औसत वार्षिक माध्य तापमान ने दर्शाया कि प्रत्येक 100 वर्षों में 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की प्रवृत्ति है। साथ ही प्रति 100 वर्षों में अधिकतम तापमान में बढ़ने की प्रवृत्ति 0.99 डिग्री सेंटीग्रेड है और न्यूनतम तापमान में प्रति 100 वर्षों में 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड के बढ़ने की प्रवृत्ति है।
- 2020 के दौरान भारत में औसत वार्षिक माध्य भूमि सतह वायु तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस है जोकि सामान्य से अधिक है लेकिन यह तापमान 2016 के दौरान भारत में देखे गये उच्चतम गर्म तापमान से काफी कम है।
- 2020 में तापमान में अधिकांश वृद्धि मानसून और मानसून उपरांत मौसमों की वजह से हुई। इस दौरान जाड़े में भी माध्य तापमान सामान्य से अधिक रहा।
- भारत की 0.3 डिग्री की बढ़ोतरी औसत वैश्विक तापमान वृद्धि 1.2 डिग्री से काफी कम है।
- रिकार्ड के अनुसार पांच सबसे गर्म वर्ष क्रमशः हैं- 2016 (0.71 डिग्री सेल्सियस), 2009 (0.55 डिग्री सेल्सियस), 2017 (0.541 डिग्री सेल्सियस), 2010 (0.539 डिग्री सेल्सियस), और 2015 (0.42 डिग्री सेल्सियस)।

वार्षिक वर्षा

- 2020 में वार्षिक वर्षा देश में संपूर्ण रूप से दीर्घावधि औसत (LPA) की 109 प्रतिशत रही। यह 1961-2010 के आंकड़े पर आधारित है।
- 2020 की उत्तरपूर्व मानसून मौसम की वर्षा (अक्टूबर-दिसंबर) पूरे देश में संपूर्ण रूप से सामान्य रही (दीर्घावधि औसत का 101 प्रतिशत)।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

ओंकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा तैरने वाली सौर परियोजना

खबर में क्यों है?

- हाल में, भारत सरकार ने विश्व के सबसे बड़े तैरने वाली सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण की घोषणा की है।



परियोजना के बारे में

- यह दुनिया की सबसे बड़ी तैरने वाली 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है जिसका निर्माण मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर आँकारेश्वर बांध पर किया जाएगा।

वित्तीयन

- अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड ने परियोजना विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए सिद्धांततः अपनी सहमति प्रदान कर दी है।
- परियोजना का प्राथमिक व्यवहार्यता अध्ययन विश्व बैंक के साथ सहयोग में समाप्त कर लिया गया है।

परियोजना का निर्माण

- इस परियोजना के वर्ष 2022-23 तक बिजली उत्पादन शुरू करने की संभावना है।

प्रमुख विशेषताएं

- इस परियोजना में आँकारेश्वर बांध के अप्रवाही जल में 600 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमताओं के तैरने वाले सौर पैनल होंगे।
- ये सौर पैनल जलाशय में जल की सतह पर तैरेंगे।
- जब बांध का जल स्तर नीचे होगा तो ये अपने आप को स्वतः नीचे और ऊपर समायोजित कर लेंगे।
- ऊंची तरंगों और बाढ़ों का इनपर कोई असर नहीं होगा।
- यह अनुमानित है कि 2 वर्षों में, परियोजना सस्ती और अच्छी गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध कराना शुरू कर देगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल

स्रोत- द हिंदू

मेग्नेटो-टेलोरिक (MT)

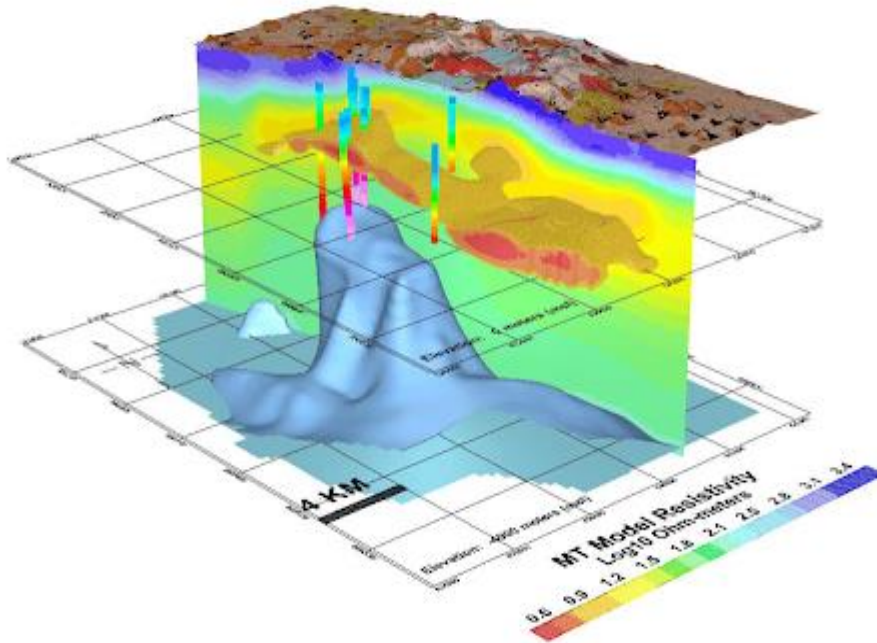
खबर में क्यों है?

- हाल में, भूभौतिक सर्वेक्षण जिसका नाम मेग्नेटो टेलोरिक (MT) है, दिल्ली क्षेत्र में किया जा रहा है।



पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने अप्रैल-अगस्त 2020 के दौरान 4 छोटे भूकंपों को महसूस किया।
- इन भूकंपों के बाद एक दर्जन सूक्ष्म घटनाएं ($M < 3.0$) हुईं जिसमें कुछ बाद के झटके शामिल थे।
- इन सभी घटनाओं को राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान नेटवर्क (NSN) के द्वारा जाना गया जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) द्वारा प्रचालित और देखभाल की जाती है।



शामिल संस्थान

- इस भूभौतिक सर्वेक्षण को वाडिया हिमालियाई भूगर्भ संस्थान (WIHG), देहरादून द्वारा करवाया गया।

मेग्नेटो-टेलोरिक (MT) के बारे में

- मेग्नेटो टेलोरिक (MT) एक भूभौतिक विधि है जो भूगर्भीय (भूमिगत) संरचना और प्रक्रियाओं को समझने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्रों के प्राकृतिक समय अंतर का प्रयोग करती है।
- ये मापन तीन प्रमुख भूकंपीय स्रोतों में किये जाते हैं, जिनके नाम हैं महेंद्रगढ़-देहरादून भंश (MDF), सोहना भंश (SF) और मथुरा भंश (MF)।
- ये मापन द्रव्य की उपस्थिति का पता लगायेंगे जो भूकंपों के आने की संभावना को बढ़ा देते हैं।

सर्वेक्षण का महत्व

- इस सर्वेक्षण की सूचना का प्रयोग भूकंप रोधक भवनों, औद्योगिक इकाईयों और महत्वपूर्ण संरचनाएं जैसे अस्पताल और विद्यालय इत्यादि के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है।

संबंधित सूचना

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के बारे में

- राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र **केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** का एक कार्यालय है।
- इसका कार्य **भूकंप की निगरानी करना** और जोखिमों के बारे में **सरकारी एजेंसियों को रिपोर्ट देना** है।

उद्देश्य

- भूकंप विज्ञान **अनुसंधान और निगरानी** के द्वारा **भूकंप प्रक्रियाओं की समझ** और उनके प्रभावों के प्रति सुधार पैदा करना।

NCS द्वारा वर्तमान में की जा रही प्रमुख गतिविधियां हैं:

- **24X7** आधार पर भूकंप की निगरानी
- 115 स्टेशनों वाले राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान नेटवर्क का प्रचालन और रखरखाव
- भूकंप विज्ञान डाटा केंद्र और सूचना सेवा का रखरखाव
- भूकंप के जोखिम के सूक्ष्मीकरण से संबंधित अध्ययन
- बाद के झटके/भूकंप वृंद निगरानी/सर्वेक्षण
- भूकंप प्रक्रियाओं की समझ
- सामान्य लोगों तक पहुँच

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

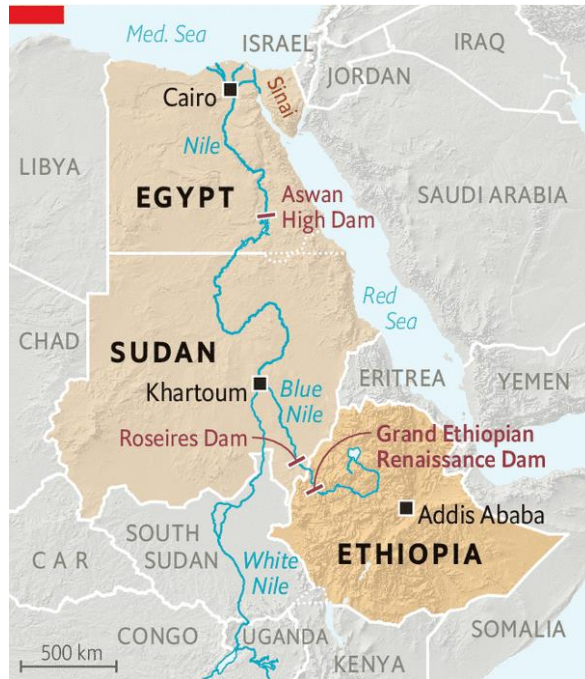
ग्रेंड रेनेसां बांध जलबिजली परियोजना

खबर में क्यों है?

- हाल में **इथियोपिया, सूडान और मिस्र हॉर्न ऑफ अफ्रीका** में **ग्रेंड रेनेसां बांध जलबिजली परियोजना** के ऊपर अपने दशक लंबे जटिल विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हो गए।

ग्रेंड इथियोपियाई रेनेसां बांध के बारे में

- इसका नाम पहले **मिलेनियम बांध** था जोकि **इथियोपिया** में स्थित है। यह स्थान **सूडान के लगभग 40 किमी. पूर्व में ब्लू नील नदी** पर स्थित है।
- यह बांध **अफ्रीका में सबसे बड़ा जलबिजली विद्युत संयंत्र** होगा। पूरा होने पर यह **दुनिया का सातवां सबसे बड़ा** होगा।



विवाद क्या है?

- नील नदी इस विवाद के केंद्र में है जिसमें कई देश शामिल हैं जोकि नदी के जल पर निर्भर हैं।
- इस विवाद में इथियोपिया, मिस्र और सूडान अग्रणी हैं।
- नील नदी के मुख्य जलमार्ग युगांडा, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र से होकर बहते हैं और इसका ड्रेनेज बेसिन पूर्व अफ्रीका में कई देशों से होकर बहता है जिसमें इथियोपिया शामिल है, वह हिस्सा जहां बांध बनाया जा रहा है।
- मिस्र ने बांध के निर्माण पर यह लेकर आपत्ति उठाई कि ब्लू नील की सहायक धारा पर बांध की स्थिति से इथियोपिया नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित कर लेगा और इससे उसकी सीमा में जल का स्तर कम हो जाएगा।
- सूडान भी चिंतित है कि यदि इथियोपिया का नदी के ऊपर नियंत्रण हो गया तो यह सूडान को मिलने वाले जल स्तर को प्रभावित करेगा।

नोट:

- बांध का निर्माण कार्य 2011 में शुरू हुआ था जोकि ब्लू नील की सहायक धारा पर स्थित है। यह नदी इथियोपिया के द्वारा होकर बहती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I+II- भूगोल+अंतरराष्ट्रीय संबंध

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

अरुणाचल के पास एक वेनेडियम का स्रोत है

खबर में क्यों है?

- अरुणाचल प्रदेश जिसे सोता हुआ पनबिजली जापेंट माना जाता है, भारत का प्रमुख वेनेडियम उत्पादक हो सकता है, यह एक उच्च मूल्य की धातु है जिसका प्रयोग इस्पात और टाइटेनियम की मजबूती में किया जाता है।



खोज के बारे में

- भारत भूगर्भ सर्वेक्षण (GSI) ने अरुणाचल प्रदेश के पारे जिले के डेपो और तमांग क्षेत्रों में पेलिओ प्रोटेरोजोइक कार्बोनेसियस फाइलाइट शैलों में वेनेडियम के अच्छी मात्रा की खोज की है।
- यह भूगर्भीय रूप से स्टोन कोयले की तरह से ही है, जोकि कार्बोनेसियस शैल में चीन के वेनेडियम जमाओं में है।
- यह उच्च वेनेडियम ग्रेफाइट से संबंधित है जिसमें 16% तक कार्बन है।

Vanadium

atomic number	23	50.942	atomic weight
symbol	V		acid-base properties of higher-valence oxides
electron configuration	[Ar]3d ³ 4s ²		crystal structure
name	vanadium		physical state at 20 °C (68 °F)

	Transition metals		Solid
	Body-centred cubic		Equal relative strength

© Encyclopædia Britannica, Inc.

महत्व

- GSI द्वारा उपलब्ध कराए गये आंकड़े के अनुसार, 2017 में पूरे विश्व में उत्पादित 84,000 मीट्रिक टन वेनेडियम के 4% का उपभोग भारत ने किया।
- चीन, जो विश्व के 57% वेनेडियम का उत्पादन करता है, ने धातु के 44% का उपभोग किया।
- अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के मिलने से स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

वेनेडियम के बारे में

- अपने शुद्ध रूप में वेनेडियम एक मुलायम, धूसर और मुड़ने वाला तत्व है जोकि प्राथमिक रूप से खनन वाले लौह अयस्क, कार्बोनेसियस शैल अथवा फाइलाइट्स और स्टील स्लैग से पाया जाता है।
- यह वेनेडिफेरियस मैग्नेटाइट अयस्कों (लौह अयस्क) के प्रसंस्करण से इकट्ठा धातु तलछट का सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।

- वेनेडियम का संकेत V और इसकी परमाणु संख्या 23 है।

गुण

- वेनेडियम मिश्रधातु चरम तापमानों और पर्यावरणों में विश्वसनीय हैं और जंग प्रतिरोधी हैं।
- इसके प्रयोग से इस्पात की लचीलेपन और भवनों, सुरंगों और पुलों के लिए प्रयोग किये गए सरियों में सुधार आ जाता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल

स्रोत- द हिंदू

भारत में लीथियम के भंडार

खबर में क्यों है?

- खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय (AMD) के प्रारंभिक सर्वेक्षणों ने कर्नाटक के मांड्य जिले के मार्लगल्ला अल्लापटना क्षेत्र के आग्नेय शैलों में लीथियम संसाधन के 1,600 टन की उपस्थिति को दर्शाया है।

लीथियम के बारे में

- प्रथम लीथियम खनिज पेटालाइट, LiAlSi₄O₁₀ की खोज स्वीडिश द्वीप के ऊटो पर ब्राजीलियाई जोजे बोनीफेसियो डि एंड्राल्डा ई सिल्वा द्वारा 1790 के दशक में की गई थी।
- 1817 में, स्टॉकहोम के जोहान ऑगस्ट आर्फवेडसन ने इसका विश्लेषण किया और यह बताया कि यह पूर्व में अज्ञात धातु है, जिसे उन्होंने लीथियम नाम दिया।

आवर्त सारिणी में स्थान

- लीथियम (Li), आवर्त सारिणी में समूह 1(IA) का रासायनिक तत्व है और इसका संकेत Li और परमाणु संख्या 3 है।

विशेषताएं

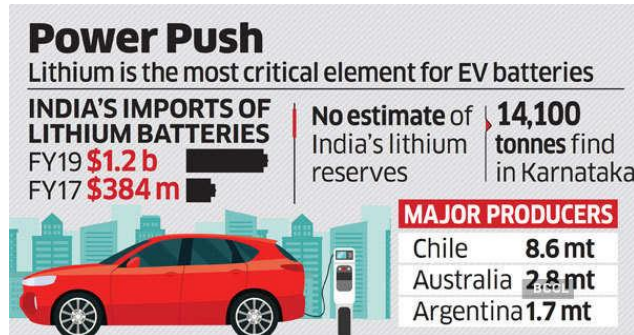
- यह एक मुलायम, चांदी के रंग की सफेद क्षारीय धातु है।
- मानक परिस्थितियों के अंतर्गत, लीथियम सबसे हल्की धातु है और सबसे हल्का ठोस तत्व है।
- सभी क्षारीय धातुओं की तरह से, लीथियम अत्यन्त प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील है।
- यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी काफी उच्च होती है।

लीथियम का निष्कर्षण

- लीथियम का निष्कर्षण अलग तरीके से किया जा सकता है, जोकि भंडार के प्रकार पर निर्भर करता है- इसे या तो बड़े लवणजल कुंड के सौर वाष्पोत्सर्जन अथवा अयस्क के कड़े शैल निष्कर्षण के द्वारा किया जाता है।

लीथियम के प्रयोग

- लीथियम और उसके यौगिक के कई औद्योगिक अनुप्रयोग हैं, जिसमें ऊष्मा रोधी ग्लास और सेरेमिक, लोहे, इस्पात और अल्युमिनियम उत्पादन के लिए फसक्स योगशील, लीथियम की बैटरियां और लीथियम आयन बैटरियां शामिल हैं।
- यह जैववैज्ञानिक प्रणालियों में भी अल्प मात्रा में उपस्थित होता है; इसके कार्य निश्चित नहीं हैं।
- मानवों में बाइपोलर डिसऑर्डर के उपचार में मूड स्थिर करने की औषधि के रूप में लीथियम लवणों की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है।



लीथियम का सबसे बड़ा उत्पादक

- 2019 में, लीथियम का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद चिली और चीन था।

भारत में लीथियम

- भारत वर्तमान में अपनी जरूरतों के लिए लीथियम का आयात करता है।

भारत में लीथियम की खोज

- भारत वर्तमान में घरेलू खोज की कोशिश में लगा हुआ है, जिसमें शामिल हैं राजस्थान और गुजरात के लवणजल कुंडों और ओडिशा और छत्तीसगढ़ की माइका पट्टियों से लीथियम के निष्कर्षण के लिए खोज कार्य।
- नागमंगला शिस्ट पट्टी के साथ मार्गल्ला-अल्लापटना क्षेत्र, जो खनिजमय जटिल पेगमाटाइट्स (आग्नेय शैलों) को दर्शाता है, को लीथियम और अन्य विरल धातुओं की संभावित खोज के लिए सबसे संभावित भूगर्भीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है।
- राजस्थान के सांभर और पचपाद्रा और गुजरात में कच्छ के रन के लवण जलों से कुछ लीथियम के प्राप्त होने की संभावना है।
- राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में प्रमुख माइका पट्टियों और ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पेगमाटाइट पट्टियां, साथ ही कर्नाटक अन्य संभावित भूगर्भीय क्षेत्रों में से एक हैं।

संबंधित सूचना

Li-आयन बैटरी के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- जून 2018 में, तमिलनाडु के कराईकुडी में केंद्रीय वैद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान (CECRI) ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के अंतर्गत RAASI सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भारत के प्रथम लीथियम (Li-आयन) बैटरी परियोजना के लिए तकनीक हस्तांतरण के लिए हस्ताक्षर किये।
- ऐसी बैटरियों के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, 2019 में केंद्रीय कैबिनेट ने एक कार्यक्रम को स्वीकृति दी, जिसे नीति आयोग में नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज का नाम दिया गया। इसका उद्देश्य स्वच्छ, जुड़ी हुई, साझा, सतत और संपूर्ण गतिशीलता पहलों का प्रचालन करना है।
- सरकार ने \$1.4 अरब के निवेश की घोषणा की है जिससे भारत को 2040 तक बिजली के वाहनों के लिए सबसे बड़े विनिर्माण केंद्रों में से एक बनाया जा सके।
- हाल में, भारत की प्रथम लीथियम रिफाइनरी, जोकि लीथियम अयस्क का प्रसंस्करण करेगी जिससे बैटरी ग्रेड पदार्थ का उत्पादन किया जाएगा, की स्थापना गुजरात में की जाएगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल

स्रोत- द हिंदू

सेमेरू पर्वत

खबर में क्यों है?

- हाल में, इंडोनेशिया की भूगर्भीय एजेंसी ने रिपोर्ट दी कि सेमेरू पर्वत पर एक ज्वालामुखी फटा है।



सेमेरू पर्वत के बारे में

- यह एक मिश्रित ज्वालामुखी है जो पूर्वी जावा, इंडोनेशिया में स्थित है, जिसमें महामेरू शिखर में सक्रिय जांग्गरिंग सेलोको छिद्र है।
- यह घटबढ़ क्षेत्र में स्थित है, जहां इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यूरेशियाई प्लेट के अंदर दबती है।
- यह जावा के द्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे महामेरू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ संस्कृत में “महान पर्वत” है।



संबंधित सूचना

प्रशांत रिंग ऑफ फायर के बारे में

- रिंग ऑफ फायर को सरकम प्रशांत पट्टी भी कहा जाता है, यह प्रशांत महासागर में एक पथ है जहां सक्रिय ज्वालामुखी हैं और अक्सर भूकंप आते हैं।
- इन स्थानों पर पृथ्वी के सभी सक्रिय ज्वालामुखियों में से 75% स्थित हैं।
- यहां कई विवर्तनिक प्लेटों के बीच सीमाएं स्थित हैं जिसमें प्रशांत, जुआन डि फुका, कोकोज, भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई, नाज्का, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपींस की प्लेटें शामिल हैं।
- रिंग ऑफ फायर पर ज्वालामुखी और भूकंपों की बहुतायत का कारण क्षेत्र में विवर्तनिक प्लेटों की गति की मात्रा है।
- इससे प्रभावित देश हैं न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और अन्य द्वीपीय देश जैसे सोलोमन द्वीपसमूह, फिजी और मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलीनेशिया में कई अन्य देश।



संबंधित शब्दावली

कूलिंग रिंग

- प्रशांत प्लेट जोकि रिंग ऑफ फायर में विवर्तनिक गतिविधि को संचालित करती है, ठंडी हो रही है।
- वैज्ञानिकों ने खोज की है कि प्रशांत प्लेट का सबसे युवा हिस्सा (लगभग 2 मिलियन वर्ष पुराना) ठंडा हो रहा है और प्लेट के पुराने हिस्से की अपेक्षा तेज दर से संकुचित हो रहा है (लगभग 100 मिलियन वर्ष पुराना)।
- प्लेट का सबसे नया हिस्सा उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में पाये जाते हैं- जो रिंग ऑफ फायर का सबसे सक्रिय हिस्सा है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल

स्रोत- द हिंदू

रैटल पनबिजली परियोजना

खबर में क्यों है?

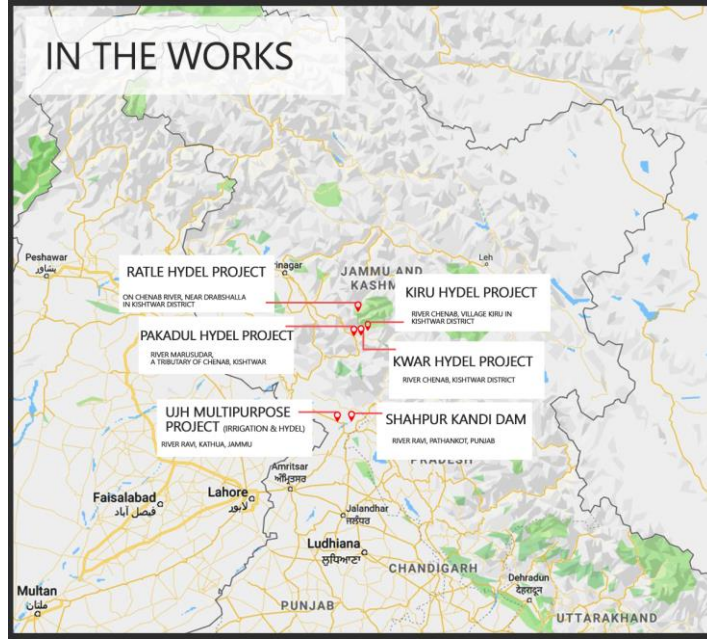
- हाल में केंद्रीय कैबिनेट ने 850 मेगावाट रैटल पनबिजली परियोजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

रैटल पनबिजली परियोजना के बारे में

- यह पनबिजली परियोजना जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है।
- इस परियोजना से उत्पन्न की गई बिजली ग्रिड के संतुलन में सहायता देगी और बिजली आपूर्ति स्थिति में सुधार करेगी।

उद्देश्य

- परियोजना की निर्माण गतिविधियों के परिणामस्वरूप लगभग 4000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। वे जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित क्षेत्र के संपूर्ण सामाजार्थिक विकास में अपना योगदान देंगे।



संबंधित सूचना

जम्मू एवं कश्मीर की अन्य महत्वपूर्ण पनबिजली परियोजनाएं

किरू पनबिजली परियोजना

- यह रन ऑफ रिवर योजना है। यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में स्थित है।
- यह 624 मेगावाट संस्थापित क्षमता की एक पनबिजली परियोजना है और चिनाब नदी पर प्रस्तावित है।

पाकल डल (धांगधुरान) पनबिजली परियोजना

- यह जलाशय आधारित योजना है जिसे मारुसुदार नदी पर प्रस्तावित किया गया है, यह जम्मू एवं कश्मीर में डोडा जिले के किश्तवाड़ तहसील में चिनाब नदी की मुख्य सीधी तटीय सहायक नदी है।

किशनगंगा विद्युत स्टेशन

- यह किशनगंगा नदी पर स्थित है, यह जम्मू एवं कश्मीर के बांदीपुरा जिले में झेलम नदी की एक सहायक नदी है।

दुलहस्ती बिजली स्टेशन

- यह 390 मेगावाट (3x130 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता के साथ पॉन्डेज योजना के साथ रन ऑफ द रिवर है। इसका उद्देश्य चिनाब नदी की पनबिजली क्षमता का दोहन करना है।
- यह जम्मू एवं कश्मीर के डोडा जिले में स्थित है।

उड़ी पनबिजली संयंत्र

- यह जम्मू एवं कश्मीर के बारामुला जिले के उड़ी क्षेत्र में झेलम नदी पर रन ऑफ द रिवर बिजली परियोजना है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

योजनायें, रिपोर्ट, सूचकांक एवं समितियां

डिजीटल भुगतान सूचकांक (DPI)

खबर में क्यों है?

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल में 'डिजीटल भुगतान सूचकांक (DPI)' की शुरुआत की है।



डिजीटल भुगतान सूचकांक (DPI) के बारे में

उद्देश्य

- हाल के दिनों में डिजीटल लेनदेन में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए पूरे देश में भुगतानों के डिजीटलीकरण के दायरे को मापने में मदद करता है।

मानदंड

- यह पांच मानदंडों पर आधारित है जिसपर RBI डिजीटल भुगतानों के भेदन को मापेगा।
- पांच प्रमुख मानदंडों में शामिल हैं:
 - भुगतान का प्रदर्शन (45%)
 - भुगतान को सक्षम बनाने वाले (25%)
 - भुगतान अवसंरचना - आपूर्ति- पक्ष के कारक (15%)
 - भुगतान अवसंरचना - मांग- पक्ष कारक (10%)
 - उपभोक्ता केंद्रीयता (5%)

आधार अवधि

- RBI-DPI सूचकांक को मार्च 2018 के आधार अवधि के साथ निर्धारित किया गया था जिसमें 100 स्कोर सेट किया गया था।
- मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए DPI क्रमशः 153.47 और 207.84 है, जो कि अच्छी वृद्धि की ओर संकेत कर रहा है।

सूचकांक जारी करने की अवधि

- सूचकांक को RBI की वेबसाइट में अर्ध वार्षिक आधार पर मार्च 2021 के आगे चार महीनों के अंतर के साथ प्रकाशित किया जाएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) योजना

खबर में क्यों है?

- सरकार ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) के लिए योजना के लाभ को विस्तारित करने का फैसला लिया है। यह निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सभी निर्यात वस्तुओं के लिए होगा।



हाल के विकास

- यह योजना निर्यातकों को सन्निहित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों को वापस देगी जो अब तक न तो छूट के रूप में और ना ही वापस दिये गये हैं।
- वापसी को निर्यातक के लेजर खाते में डाल दिया जाएगा जोकि सीमा शुल्क के साथ होगा जिसका प्रयोग पहले आयातित वस्तुओं पर मूलभूत सीमा शुल्क के भुगतान में किया जाता था।
- ये जमा अन्य आयातकों को भी हस्तांतरित किये जा सकते हैं।
- RoDTEP दरों को जल्दी ही वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित कर दिया जाएगा, जोकि एक समिति की अनुशंसाओं पर आधारित है जिसके मुखिया पूर्व वाणिज्य और गृह सचिव डॉ. जी. के. पिल्लई हैं।

पृष्ठभूमि

- ✓ निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) योजना के बारे में
- इस योजना का क्रियान्वयन 1 जनवरी 2020 से किया जा रहा है।
- यह वर्तमान भारत से पण्य निर्यात योजना (MEIS) का स्थान लेगी।

लाभ

- भारतीय निर्यातक निर्यातों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में सक्षम होंगे क्योंकि देश में ही निर्यातकों को वहनीय परीक्षण और प्रमाणीकरण को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जबकि अभी तक देश इस मामले में अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर निर्भर था।
- साथ ही, इसके अंतर्गत, निर्यातकों के लिए कर आकलन पूरी तरह से स्वचालित होने वाला है।

- व्यवसाय अब GST के लिए अब अपनी वापसी के लिए पहुँच तक एक स्वचालित वापसी मार्ग तक जाएंगे।
- इससे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी और उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी बढ़ेगी।
- RoDTEP विश्व व्यापार संगठन (WTO) के साथ समन्वय करेगा जिससे निर्यातकों के लिए उत्पादन के बाद की लेनदेन लागतों में कटौती होगी।
- ✓ भारत से पण्य निर्यात योजना (MEIS) के बारे में
- इसे विदेश व्यापार नीति (FTP) 2015-20 में लागू किया गया जोकि 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी हो गई।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य वस्तुओं/उत्पादों के निर्यातों में शामिल लागतों और अवसंरचनात्मक अक्षमताओं को समाप्त करना है जिनका विनिर्माण अथवा उत्पादन भारत में होता है जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र द्वारा उत्पादित अथवा विनिर्मित उत्पाद शामिल हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- इकोनॉमिक्स टाइम्स

लॉन्गिट्यूइनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया (LASI)

खबर में क्यों है?

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लॉन्गिट्यूइनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया (LASI) वेव-1 पर भारतीय रिपोर्ट को जारी किया है।



लॉन्गिट्यूइनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया (LASI) के बारे में

- यह संपूर्ण स्तर पर भारत में स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक निर्धारकों और जनसंख्या के उम्र बढ़ने के परिणामों पर राष्ट्रीय वैज्ञानिक जांच सर्वेक्षण है।
- यह भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है जो सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक के वृहद क्षेत्रों में बूढ़ी जनसंख्या के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की डिजाइन के लिए लॉन्गिट्यूइनल डाटाबेस उपलब्ध कराते हैं।

शामिल संस्थान

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम ने अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS), मुंबई के द्वारा लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया को लिया है। इसका गठबंधन हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, यूनीवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलीफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, Dte, GHS, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) और राष्ट्रीय वृद्धावस्था संस्थान के साथ है।

कवरेज

- LASI, वेव-1 ने 45 वर्ष या इससे ऊपर उम्र के 72,250 व्यक्तियों और उनके जीवनसाथियों के बेसलाइन सैंपल को कवर किया है जिसमें 60 वर्ष या इससे ऊपर उम्र वाले 31,464 वृद्ध व्यक्ति और 75 वर्ष या इससे ऊपर उम्र वाले 6,749 वृद्धतम व्यक्ति शामिल हैं। ये सभी लोग भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से हैं (सिक्किम को छोड़कर)।

विधि

- LASI ने अत्याधुनिक बड़े पैमाने वाले सर्वेक्षण प्रोटोकाल और क्षेत्र क्रियान्वयन रणनीतियों को अपनाया है जिसमें भारत और उसके राज्यों के प्रतिनिधि सैंपल, सामाजार्थिक स्पेक्ट्रम, एक विस्तृत विषय वाला केंद्र, एक लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन और आंकड़े एकत्रित करने, गुणवत्ता नियंत्रण और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के लिए कम्प्यूटर सहायता वाली व्यक्तिगत साक्षात्कार (CAPI) तकनीक शामिल है।

जैवचिह्न का प्रयोग

- LASI की एक विशिष्ट विशेषता समय जैवचिह्नों का कवरेज है।
- भारत में कोई अन्य सर्वेक्षण परिवार और सामाजिक नेटवर्क, आय, परिसंपत्तियों और उपभोग पर सूचना के साथ स्वास्थ्य और जैवचिह्नों पर विस्तृत आंकड़े नहीं एकत्रित करता है।

LASI की खास बातें

- 2011 की जनगणना में, 60 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 8.6 प्रतिशत थी, इस तरह से कुल 103 मिलियन वृद्ध व्यक्ति हैं।
- वार्षिक रूप से 3 प्रतिशत की गति से बढ़ते हुए, 2050 में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या 319 मिलियन हो जाएगी।
- 75 प्रतिशत वृद्ध व्यक्ति किसी न किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं।
- लगभग 40 प्रतिशत वृद्ध व्यक्तियों को एक या अन्य अक्षमता है और 20 प्रतिशत लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है।

महत्व

- LASI से प्राप्त साक्ष्यों को वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम के दायरे को और ज्यादा मजबूत और विस्तृत करने में प्रयोग किया जाएगा।
- यह निरोधात्मक और स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों के दायरे को स्थापित करने में भी मदद देगा जो कि वृद्ध जनसंख्या के लिए होगा और उनमें से सबसे कमजोर लोगों के लिए।

संबंधित सूचना

वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE) के बारे में

- वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 2010 में की गई थी।

- यह सरकार के अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की अभिव्यक्ति है जिसकी संकल्पना अक्षमताओं के साथ व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की संधि (UNCRPD), राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति कार्यक्रम (NPOP) के अंतर्गत की गई जिसे भारत सरकार ने 1999 में और “माता पिता और वृद्ध नागरिकों की देखभाल और कल्याण कानून, 2007” के अनुच्छेद 20 द्वारा अपनाया गया जो वृद्ध नागरिकों की चिकित्सा देखभाल के प्रावधानों से संबंधित है।

दृष्टि

- वहनीय, पहुँच योग्य और उच्च गुणवत्ता वाला दीर्घावधि, समग्र और समर्पित देखभाल सेवा वृद्ध जनसंख्या के लिए।
- वृद्ध होने के लिए नए आर्किटेक्चर का निर्माण करना।
- सभी आयुओं के लिए समाज के लिए एक सक्षम वातावरण के सृजन के लिए ढांचे का निर्माण करना।
- सक्रिय और स्वास्थ्यपूर्ण वृद्ध होने की संकल्पना को प्रोत्साहित करना।
- तृतीयक स्तर की देखभाल को देने के लिए क्षेत्रीय वृद्धचिकित्सा केंद्रों को जिलों के साथ जोड़ा जाएगा।

वित्तीयन का तरीका

- केंद्र कुल बजट का 75% वहन करता है और राज्य सरकारें बजट के 25% का योगदान देती हैं, जिला स्तर की गतिविधियों के लिए।

पात्र लाभकर्ता

- देश में सभी वृद्ध व्यक्ति (60 वर्ष से अधिक आयु के)।

विशिष्ट उद्देश्य

- प्रोत्साहनात्मक, निरोधात्मक, रोगनिवारक और पुनर्वासात्मक सेवाएं वृद्ध लोगों को जिसके लिए समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाएगा।
- वृद्ध लोगों में स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानना और मजबूत परामर्श बैंकअप समर्थन के साथ समुदाय में उपयुक्त स्वास्थ्य हस्तक्षेप को उपलब्ध कराना।
- चिकित्सा और पैरामेडिकल पेशेवरों की क्षमता का निर्माण करना साथ ही वृद्धों को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के लिए परिवार के अंदर ही केयरटेकर उपलब्ध कराना।
- जिला अस्पतालों, क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थानों के द्वारा वृद्ध रोगियों को परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय जैसे अन्य लाइन विभागों के साथ संमिलन।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सामाजिक मामले

स्रोत- PIB

UJALA और SLNP के छह वर्ष

खबर में क्यों है?

- भारत सरकार की सभी के लिए वहनीय LEDs के द्वारा उन्नत ज्योति (UJALA) और सड़क लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (SLNP) शून्य सब्सिडी ने हाल में छह वर्षों के अपने क्रियान्वयन को पूरा कर लिया है।



प्रमुख खास बातें

UJALA की उपलब्धियां

- UJALA के अंतर्गत, ऊर्जा सामर्थ्य सेवा लिमिटेड (EESL) ने पूरे भारत में 36.69 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया है।
- इसके परिणामस्वरूप अनुमानित 47.65 अरब किलोवाट प्रतिवर्ष ऊर्जा की बचत हुई है जिसने 9,540 मेगावाट की सर्वोच्च मांग से बचाया है।
- इससे अनुमानित 38.59 मिलियन टन कार्बन डाईआक्साइड प्रतिवर्ष के बराबर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटा है।

SLNP की उपलब्धियां

- SLNP के साथ, ऊर्जा सामर्थ्य सेवा लिमिटेड ने लगभग 1.14 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइटों को पूरे भारत में लगाया है।
- इसके परिणामस्वरूप अनुमानित 7.67 अरब किलोवाट प्रतिवर्ष की ऊर्जा की बचत हुई है जिसने 1280 मेगावाट की सर्वोच्च मांग को बचाया है।
- इसने अनुमानित 5.29 मिलियन टन कार्बन डाईआक्साइड प्रतिवर्ष के बराबर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया है।
- इन कार्यक्रमों ने प्रतिष्ठित दक्षिण एशिया प्रोक्योरमेंट इनोवेशन एवार्ड (SAPIA) 2017 जैसे वैश्विक पुरस्कार हासिल किये हैं।

नोटः

- UJALA और SLNP दोनों ने ही ग्लोबल सॉलिड-स्टेट लाइटिंग (SSL) एवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर द ट्रांसफॉर्मेशनल कांटीब्यूशन टू द LED सेक्टर पुरस्कार हासिल किया है।

संबंधित सूचनाः

सभी के लिए वहनीय एलईडी के द्वारा उन्नत ज्योति (UJALA)

- सभी के लिए वहनीय LEDs के द्वारा उन्नत ज्योति की शुरुआत 1 मई 2015 को की गई थी, जिसने “बचत लैम्प योजना” को विस्थापित किया था।
- इस योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से LED वितरण को पूरे देश में स्थापित करने के लिए किया गया था जिससे लोगों को वहनीय LED बल्बों और ऊर्जा सामर्थ्य उपकरणों को उपलब्ध कराया जा सके।
- इसका उद्देश्य सामर्थ्य वाली लाइटिंग, ऊर्जा सामर्थ्य वाले उपकरणों के प्रयोग के लिए लोगों को जागरूक करना है। साथ ही बिजली का बिल कम करना और पर्यावरण का संरक्षण करना है।

स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (SLNP) के बारे में

- इसकी शुरुआत 2015 में पूरे भारत में स्मार्ट और ऊर्जा सामर्थ्य वाली LED स्ट्रीटलाइटों के द्वारा पारंपरिक स्ट्रीटलाइटों को विस्थापित करने से हुई थी।
- ऊर्जा सामर्थ्य सेवा लिमिटेड ने LEDs के साथ पारंपरिक स्ट्रीटलाइटों को विस्थापित किया है। इसके लिए उसकी अपनी लागत है और इसके फलस्वरूप ऊर्जा प्रयोग में गिरावट आई है और म्युनिसिपैलिटी की रखरखाव लागत का प्रयोग समय के एक काल में EESL को पुनर्वापसी में किया जा रहा है।

क्रियान्वयन एजेंसी

- ऊर्जा सामर्थ्य सेवा लिमिटेड, एक सार्वजनिक ऊर्जा सेवा कंपनी है जोकि बिजली, मंत्रालय के प्रशासन के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत है। यह SLNP के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है।
- यह दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीटलाइट विस्थापन कार्यक्रम है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप

स्रोत- PIB

जम्मू एवं कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना

खबर में क्यों है?

- हाल में, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार के प्रोत्साहन के लिए विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

New Industrial Development Scheme For Jammu & Kashmir



जम्मू एवं कश्मीर के लिए नई औद्योगिक विकास योजना के बारे में

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में उद्योगों का विकास करना है।
- इस योजना को वर्ष 2037 तक कुल रु. 28,400 करोड़ के आवंटन के साथ स्वीकृति दी गई है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करना है जो सीधे तौर पर क्षेत्र को सामाजिक विकास की ओर ले जाएगा।



उद्देश्य

- इस योजना का लक्ष्य जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में औद्योगिक विकास को ब्लाक स्तर तक ले जाने का है जोकि भारत सरकार की पहली औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है और पूरे केंद्र शासित क्षेत्र में ज्यादा सतत और संतुलित औद्योगिक वृद्धि की कोशिश करती है।
- संयंत्र और मशीनरी में रु. 50 करोड़ के निवेश के साथ छोटी इकाईयां को रु. 7.5 करोड़ तक का पूंजी प्रोत्साहन दिया जाएगा और अधिकतम 7 वर्षों के लिए 6% की दर पर पूंजी ब्याज छूट मिलेगी।
- इस योजना को व्यवसाय करने की सुगमता के अनुसार सरलीकृत किया गया है जिसके लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन को लाया गया है अर्थात GST से जुड़ा हुआ प्रोत्साहन जो बिना पारदर्शिता के साथ समझौता किये हुए कम अनुपालन बोझ को सुनिश्चित करेगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- PIB

भारतीय और विश्व अर्थव्यवस्था में इंटरनेट शटडाउन का आर्थिक असर

खबर में क्यों है?

- यूनाईटेड किंगडम आधारित निजता और सुरक्षा अनुसंधान फर्म टॉप VPN की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2020 में सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन भारत में हुआ।

रिपोर्ट की खास बातें

वैश्विक प्रभाव

- वैश्विक रूप से, इंटरनेट शटडाउन से विश्व अर्थव्यवस्था को \$4 अरब का झटका लगा।
- लेकिन, यह 2019 के \$8.05 अरब की तुलना में 50% प्रभाव की कमी है।

भारत पर प्रभाव

- 2020 में इंटरनेट शटडाउन की वजह से भारत ने सबसे बड़ा आर्थिक झटका सहन किया जोकि कुल 8,927 घंटे का था और कुल नुकसान \$2.8 अरब का हुआ।
- पिछले वर्ष इंटरनेट पर रोक लगाने वाले 21 देशों में से भारत को इससे होने वाली हानि सूची में अगले 20 देशों के लिए संयुक्त लागत से दुगुनी रही।
- भारत ने किसी अन्य देश की अपेक्षा ज्यादा इंटरनेट तक पहुँच पर रोक लगाई- 2020 में 75 बार से ज्यादा।
- यह छोटे ब्लैकआउट की अधिकांश संख्या उच्च तौर पर लक्षित थी, जिसने गांवों के समूहों अथवा व्यक्तिगत शहर जिलों को प्रभावित किया।

- रिपोर्ट में जम्मू एवं कश्मीर में इंटरनेट प्रयोग पर विस्तारित रोक का अलग से उल्लेख किया गया जोकि पूरी दुनिया की किसी लोकतंत्र में सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन था।

संबंधित सूचना

- हाल में, राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIX) ने घोषणा की कि वह अपने प्राथमिकता वाली 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी में मुफ्त IDN (इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम) देगी।
- यह प्रत्येक IN डोमेन के साथ उपलब्ध होगा जिसे पंजीकरण कराने वाले के द्वारा बुक कराया जाएगा।
- यह ऑफर इसलिए किया गया है जिससे भारत (IDN) डोमेन नाम के अपनाने को प्रोत्साहन दिया जा सके और स्थानीय भाषा विषयवस्तु के प्रसार को बढ़ावा दिया जा सके।

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में

- यह गैर लाभकारी संगठन है जोकि भारत के नागरिकों में इंटरनेट तकनीक के प्रसार के लिए 2003 से कार्यरत है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

खबर में क्यों है?

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) 2021 के 22वें संस्करण को जारी किया है।



प्रमुख खास बातें

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) मार्च 2020 के 14.7 प्रतिशत से सुधरकर सितंबर 2020 में 15.8 प्रतिशत हो गए।
- SCBs के सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPA) अनुपात 8.4 प्रतिशत से गिरकर 7.5 प्रतिशत हो गया।
- SCBs का प्रोविजन कवरेज अनुपात (PCR) 66.2 प्रतिशत से सुधरकर 72.4 प्रतिशत हो गया।
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रथम अग्रिम अनुमानों को शामिल करने वाले स्थूल तनाव परीक्षण (Macro stress tests) इंगित कर रहे हैं कि सभी SCBs का GNPA अनुपात सितंबर 2020 के 7.5 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 तक 13.5 प्रतिशत हो सकता है।
- यह संभावित परिसंपत्ति गुणवत्ता क्षरण को झेलने के लिए पूंजी पर्याप्तता के सक्रिय रूप से निर्माण के लिए जरूरत को रेखांकित करता है।
- नेटवर्क विश्लेषण बतलाता है कि वित्तीय प्रणाली में इकाईयों के मध्य कुल द्विपक्षीय जोखिम में सितंबर 2020 में समाप्त होने वाली तिमाही में मामूली सी बढ़ोतरी हुई है।

- निजी क्षेत्र बैंकों (PVBs) और विदेशी बैंकों (FBs) की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) में क्रमशः 4.6% और 2.5% से 7.9% और 5.4% की वृद्धि हो सकती है।

खराब ऋणों के वर्तमान स्टॉक से निपटने के लिए RBI की अनुशंसा

कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पूनर्पूँजीकरण

- बैंक अपने आप धन एकत्रित करने की स्थिति में नहीं हो सकती है, बड़ी बैंकों के विपरीत (SBI, PNB, BoB इत्यादि) और उन्हें सरकार से सहायता की जरूरत हो सकती है।

बैंकिंग प्रणाली के बैंकिंग न्यायाधीश के रूप में RBI

- तनाव वाली परिसंपत्ति को सुलझाने पर न्यायपालिका और सरकार के हस्तक्षेप ने पूर्व में बैंकिंग क्षेत्र को काफी नुकसान पहुँचाया है।
- RBI को अपना कार्य करने के लिए मुक्त हाथ प्रदान किया गया है और विनियामक इस बात का बेहतर न्यायधीश है कि बैंकिंग प्रणाली के लिए क्या अच्छा है।

खराब बैंक का विचार

- खराब बैंक से आशय एक अलग इकाई से है जहां बैंकिंग उद्योग की सभी खराब परिसंपत्तियां रखी जा सकती हैं।
- एक खराब बैंक केवल उसी समय एक हकीकत हो सकता है जब सरकार आगे बढ़े और आरंभिक पूंजी उपलब्ध कराए।

पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्तियां अनुपात (CRAR) के बारे में

- इसे पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी कहते हैं, जोकि बैंक की पूंजी से उसके जोखिम का अनुपात है।
- बैंकिंग विनियामक बैंक के CAR को देखता है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक एक हद की मात्रा तक हानि को बर्दाश्त कर सकते हैं और वे वैधानिक पूंजी जरूरतों के साथ अनुपालन कर रहे हैं।
- बैंक का CRAR जितना ऊंचा होता है, वह उतना ही बेहतर पूंजीकृत होती है।
- पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्तियां अनुपात की गणना बैंक की टियर 1 पूंजी और टियर 2 पूंजियों का योग करके की जाती है और फिर इस जोड़ को इसके कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों से भाग दे दिया जाता है।

नोट:

- वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष (IMF) द्वारा किया गया।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू+ rbi.org.in

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

खबर में क्यों है?

- 13 जनवरी 2016 को, भारत सरकार ने भारत के किसानों के लिए फसलों के जोखिम कवरेज को मजबूत करने की ओर एक ऐतिहासिक कदम उठाया और फ्लैगशिप फसल बीमा योजना- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को स्वीकृति प्रदान कर दी।



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में

- इसे 2016 में शुरू किया गया था और इसे कृषि मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
- यह किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा योजना है।
- इसका लक्ष्य किसानों पर प्रीमियम के बोझ को घटाना है और पूरी तरह से बीमित राशि के लिए फसल बीमा दावे के जल्दी निपटारे को सुनिश्चित करना है।
- इसे एक देश-एक योजना की थीम के अनुसार बनाया गया है जिसके लिए पूर्व की दो योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषीय बीमा योजना (MNAIS) के स्थान पर लाया गया है।
- यह योजना सभी खाद्य तिलहन फसलों और वार्षिक व्यावसायिक/बागवानी फसलों को कवर करती है जिसके लिए पूर्व के उपज आंकड़े उपलब्ध हैं और जिसके लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (GCES) के अंतर्गत फसल कटान परीक्षणों (CCEs) की जरूरी संख्या को किया गया।

क्रियान्वयन

- इस योजना का क्रियान्वयन सूचीबद्ध सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा किया जा रहा है।
- यह योजना ऋण लेने वाले किसानों के लिए जरूरी है जोकि अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण/KCC खाते को ले रहे हैं और अन्य लोगों के लिए स्वैच्छिक है।
- प्रति हेक्टेयर औसत बीमाकृत राशि पूर्व PMFBY योजनाओं के दौरान रु. 15,100 से बढ़कर PMFBY के अंतर्गत रु. 40,700 हो गई है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- कृषि (महत्वपूर्ण योजना)

स्रोत- PIB

5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार

खबरों में क्यों हैं?

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कारों का उद्घाटन किया।

राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कारों के बारे में

- इसे 2015 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था जोकि स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा था जिसका उद्देश्य भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और सफाई को सुनिश्चित करना था।

लक्ष्य

- यह पुरस्कार उन जिला अस्पतालों, उप-क्षेत्रीय अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को

मान्यता और प्रोत्साहित करता है जिन्होंने सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण में उच्च स्तर हासिल कर लिया है।

मानदंड

मानदंड जिनपर सुविधा के प्रदर्शन का निर्णय लिया जाएगा, निम्न हैं

- अस्पताल/ सुविधा की देखभाल
- सफाई एवं स्वच्छता
- अपशिष्ट प्रबंधन
- संक्रमण नियंत्रण
- समर्थन सेवाएं
- स्वच्छता प्रोत्साहन

आकलन

- इन मानदंडों का आकलन त्रिस्तरीय प्रणाली के द्वारा किया जाता है- पहले आंतरिक आकलन होता है उसके बाद साथियों का आकलन और तब बाह्य आकलन होता है।

महत्व

- कायाकल्प की सफलता को 20-28 मई 2019 को हुए 72वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान अंतरराष्ट्रीय तौर पर सराहा गया था।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- स्वास्थ्य मामले

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2021

खबरों में क्यों है?

- भारत को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट 'हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2021' में 85वां स्थान प्राप्त हुआ है।



हेनली पासपोर्ट सूचकांक के बारे में

- इसे हेनली एवं साझीदारों द्वारा तैयार किया जाता है, जोकि लंदन आधारित वैश्विक नागरिकता एवं आवास परामर्शदात्री फर्म है।
- इसे 2006 में शुरू किया गया था और इसमें 199 प्रकार के विभिन्न पासपोर्ट शामिल हैं।

- यह पासपोर्टों को उनकी शक्ति एवं गतिमयता के आधार पर स्थान देता है।
- यह सूचकांक अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) से आंकड़े इकट्ठा करता है जोकि वैश्विक रूप से अंतर- वायुलाइन सहयोग को प्रबंधित करता है।

सूचकांक की खास बातें

सबसे ऊपर स्थान वाले

- सूचकांक में आज भी पहले स्थान पर **जापान** है, जहां के पासपोर्ट धारक पूरे विश्व में वीजा मुक्त तरीके से 191 गंतव्यों तक पहुँच रखते हैं।
- **सिंगापुर** दूसरे स्थान पर है (190 के स्कोर के साथ) और तीसरे स्थान पर जर्मनी के साथ दक्षिण कोरिया है (189 के स्कोर के साथ)।
- सूचकांक के सोलह वर्ष से ज्यादा के इतिहास में, पारंपरिक रूप से ऊँचे स्थान पर **यूरोपीय संघ के देश, यूनाईटेड किंगडम अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका** काबिज रहे हैं।
- इस वर्ष, **एशिया-प्रशांत (APAC) के पासपोर्ट** हैं जोकि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं क्योंकि इनमें कुछ ऐसे पहले देश शामिल हैं जिन्होंने कोविड-19 महामारी से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सबसे नीचे स्थान वाले धारक

- सीरिया, इराक और अफगानिस्तान लगातार वे देश बने हुए हैं जिनके पास सबसे खराब पासपोर्ट हैं और जिनके पासपोर्ट स्कोर क्रमशः 29, 28 और 26 हैं।

भारत का प्रदर्शन

- भारत का 85वां स्थान है, जिसका वीजा मुक्त स्कोर 58 है।
- भारत के पासपोर्ट का स्थान दोनों ही में 2020 में (84वां) और 2019 में (82वां) था।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतरराष्ट्रीय संबंध

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

इंडिया नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण

खबर में क्यों है?

- नीति आयोग और प्रतिद्वन्दिता संस्थान ने एक वर्चुअल समारोह में **इंडिया नवाचार सूचकांक का दूसरा संस्करण** जारी किया।


NITI Aayog

**INDIA
INNOVATION
INDEX**

2020

इंडिया नवाचार सूचकांक के बारे में

- इंडिया नवाचार सूचकांक का लक्ष्य भारत में 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित क्षेत्रों में भारत के नवाचार पर्यावरण के लगातार मूल्यांकन के लिए एक सघन ढांचे की स्थापना करना है।

इसका उद्देश्य निम्नलिखित तीन कार्यों को करना है-

- उनके सूचकांक स्कोरों के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की रैंकिंग करना
- अवसरों और चुनौतियों की पहचान करना और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों को बनाने में सहायता प्रदान करना।
- यह सूचकांक नवाचार पारितंत्र प्रणाली में विभिन्न हितधारकों के बीच में सहक्रिया का सृजन करेगी, जिससे भारत को अच्छे प्रतियोगी शासन की ओर उन्मुख होने में मदद मिलेगी।
- नवाचार निवेशों का पांच योग्य बनाने वाले मानदंडों से मापन किया जाता था। इसके निर्गत का मापन दो प्रदर्शन मानदंडों से किया जाता था।
- पांच योग्य बनाने वाले मानदंड हैं- मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कर्मों, व्यवसाय का वातावरण, सुरक्षा एवं कानूनी वातावरण।
- दो प्रदर्शन मानदंड: ज्ञान निर्गत और ज्ञान प्रसरण।

दो राज्यों को तीन श्रेणियों में तोड़ा गया है

- प्रमुख राज्य
- उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्य
- केंद्र शासित क्षेत्र/शहरी राज्य/छोटे राज्य

सूचकांक की खास बातें

‘प्रमुख राज्य’ श्रेणी के अंतर्गत

- कर्नाटक लगातार पहले स्थान पर कायम है।
- चार दक्षिणी राज्यों- कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल- ने इस वर्ष ‘प्रमुख राज्य’ श्रेणी के अंतर्गत पांच सर्वोच्च स्थान हासिल किये हैं।

Best performers Four of the five highest scoring major States in the India Innovation Index are from the south 	Rank	Major States	Score
	1	Karnataka	42.5
	2	Maharashtra	38.03
	3	Tamil Nadu	37.91
	4	Telangana	33.23
	5	Kerala	30.58
	6	Haryana	25.81
	7	Andhra Pradesh	24.19
	8	Gujarat	23.63
	9	Uttar Pradesh	22.85
	10	Punjab	22.54

कम स्कोर वाले प्रमुख राज्य

- झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार ने सूचकांक में सबसे कम स्कोर हासिल किया है, जिसने इन्हें ‘प्रमुख राज्य’ श्रेणी में निचले पायदान पर ला दिया है।

केंद्र शासित क्षेत्र/शहरी राज्य/छोटे राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत

- दिल्ली ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है, जबकि चंडीगढ़ ने 2019 से लंबी छलांग लगाई है और इस वर्ष दूसरा स्थान हासिल किया है।

उत्तर-पूर्वी राज्य/पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत

- हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान से उठकर इस वर्ष पहले स्थान पर पहुँच गया है।
- 2019 के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले (इस श्रेणी में), सिक्किम फिसल कर चौथे स्थान पर पहुँच गया है।

कर्नाटक की रैंक के कारण

- कर्नाटक की सर्वोच्च स्थिति का कारण उसके वेंचर कैपिटल समझौतों की बड़ी संख्या है, इसके अतिरिक्त पंजीकृत भौगोलिक संसूचक और सूचना एवं संचार तकनीक निर्यात भी कारणों में शामिल हैं।
- इसका ऊंचा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) प्रवाह ने राज्य की नवाचार क्षमता को भी उन्नत कर दिया है।

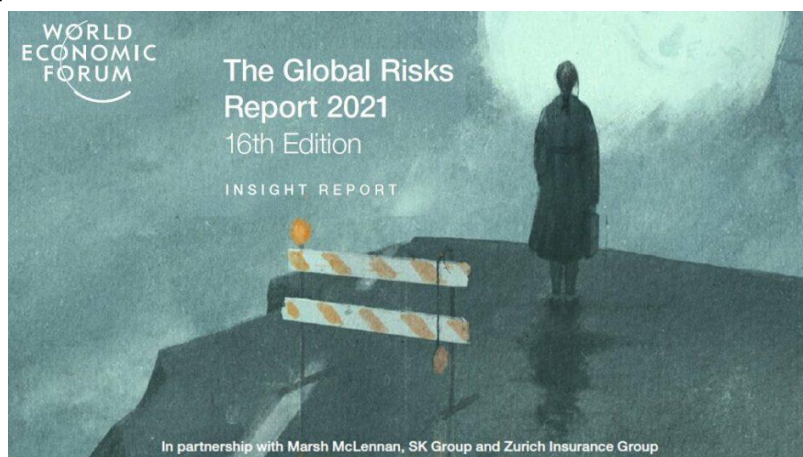
विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

‘वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021’ का 16वां संस्करण

खबर में क्यों है?

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने हाल में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के 16वें संस्करण को जारी किया है।



रिपोर्ट की खास बातें

वैश्विक जोखिम बोध

- अगले दस वर्षों के सबसे ज्यादा संभावित जोखिम निम्न हैं
 - चरम मौसम
 - मौसम कार्ययोजना की असफलता
 - मानव जनित पर्यावरणीय क्षति; साथ ही डिजिटल शक्ति का केंद्रण
 - डिजिटल असमानता और साइबरसुरक्षा की असफलता।

- अगले दशक के सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले जोखिमों में संक्रामक रोग सबसे ऊपर हैं, जिसके बाद मौसम कार्ययोजना की असफलता और अन्य पर्यावरणीय जोखिम हैं; साथ ही जनसंहार के हथियार, जीवनयापन संकट, ऋण का संकट और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना में टूटफूट भी इसमें शामिल हैं।
- **GRPS** के लगभग 60 प्रतिशत उत्तरकर्ताओं ने “संक्रामक रोगों” और “जीवनयापन संकट” को विश्व के लिए लघु अवधि के खतरे के रूप में पहचाना है।
- जीवन और जीवनयापन की क्षति “सामाजिक बंधन के क्षरण” के जोखिम को बढ़ा देगा, जिसे **GRPS** में लघु अवधि के खतरे के रूप में पहचाना गया है।
- **संक्रामक रोग** जिसके बाद मौसम कार्ययोजना असफलता आने वाले दशक के लिए सबसे बड़े वैश्विक जोखिम हैं (अन्य वैश्विक जोखिम बोध के लिए एंफोग्राफिक को देखें)।
- **आर्थिक कमजोरी** और सामाजिक विभाजन का बढ़ना निश्चित है क्योंकि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्तीय स्थिरता और तकनीक में अन्तर्निहित विषमता की वजह से संकट पैदा हुआ है जिसने कुछ समूहों और देशों को गैरसमानुपातिक रूप से प्रभावित किया है।
- **बढ़ता हुआ डिजिटल विभाजन** और तकनीक को अपनाने ने चिंताएं पैदा की हैं जो कोविड-10 की वजह से और भी तीव्र हो गई हैं।
- कोविड-19 महामारी की वजह से **आर्थिक कमजोरी और दीर्घावधि स्वास्थ्य प्रभाव** के विध्वंसकारी परिणाम जारी रहेंगे।

विश्व आर्थिक मंच की अन्य रिपोर्ट

- वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक
- वैश्विक सूचना तकनीक रिपोर्ट
- यात्रा एवं पर्यटन प्रतिद्वन्द्विता रिपोर्ट
- वैश्विक प्रतिद्वन्द्विता रिपोर्ट
- वैश्विक योग्य बनाने वाली व्यापार रिपोर्ट
- वैश्विक ऊर्जा आर्किटेक्चर प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट
- वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक
- विश्व शक्ति भाषा सूचकांक
- समावेशी विकास सूचकांक
- वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट
- ऊर्जा संक्रमण सूचकांक
- फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट
- वैश्विक विनिर्माण सूचकांक
- सामाजिक गतिमयता सूचकांक

विषय-सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- महत्वपूर्ण रिपोर्ट

स्रोत- द हिंदू

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना

खबर में क्यों है?

- सरकार ने महत्वपूर्ण बल्क औषधियों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए **PLI** योजना के अंतर्गत अरबिंदो फार्मा और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स सहित फर्मों को स्वीकृति दी।



उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) के बारे में

- भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए, सरकार ने हाल में मोबाइल फोनों, फार्मा उत्पादों और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के लिए **PLI** योजना की घोषणा की।
- यह **इलेक्ट्रॉनिक योजना पर राष्ट्रीय नीति** का हिस्सा है जिसकी अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 को जारी की गई थी।
- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य महत्वपूर्ण प्रमुख शुरुआती पदार्थों (**KSM**)/ औषधि मध्यवर्तियों और सक्रिय फार्मास्युटिकल घटकों के देश में निर्माण को प्रोत्साहन देना है।

योजना की अवधि

- PLI योजना वित्त वर्ष 2019-20 से पांच वर्षों के लिए सक्रिय रहेगी। यह प्रोत्साहनों की गणना के लिए आधार वर्ष होगा।
- इसका अर्थ है कि सभी निवेश और अतिरिक्त बिक्री जिसका पंजीकरण वित्त वर्ष 20 के बाद हो रहा है, प्रत्येक कंपनी को दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि की गणना में विचार में रखी जाएगी।

किसी प्रकार की कंपनियों और किसी प्रकार के निवेश पर विचार किया जाएगा?

- सभी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियां जोकि या तो भारतीय हैं या उनकी भारत में पंजीकृत इकाई है, इस योजना के लिए पात्र होंगी।
- ये कंपनियां या तो नई इकाई तैयार कर सकती हैं या भारत में एक या ज्यादा स्थानों से अपनी वर्तमान इकाईयों के लिए प्रोत्साहन राशि मांग सकती हैं।
- कोई अतिरिक्त खर्च जो कंपनियों ने संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, अनुसंधान एवं विकास और मोबाइल फोनों एवं संबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण के लिए तकनीकी हस्तांतरण के लिए किया हो, प्रोत्साहन राशि योजना के लिए पात्र होगा।
- लेकिन, कंपनियों का भूमि और परियोजना के लिए इमारत के लिए निवेश को किसी प्रोत्साहन राशि के लिए विचार नहीं किया जाएगा अथवा इससे योजना की पात्रता निर्धारित नहीं होगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

FICCI सर्वेक्षण ने दर्शाया वित्त वर्ष 21 में GDP 8% संकुचित होगी

खबर में क्यों है?

- FICCI के हालिया आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार, 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 8% तक संकुचित होने की संभावना है।

पृष्ठभूमि

- उद्योग निकाय की वार्षिक औसत वृद्धि भविष्यवाणी उद्योग, बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्रों का प्रतिनिधि करने वाले अग्रणी अर्थशास्त्रियों के जवाबों पर आधारित है।



सर्वेक्षण की मुख्य खास बातें

कृषि के लिए

- कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए औसत वृद्धि भविष्यवाणी को 2020-21 में 3.5% पर रखा गया है।
- कृषि क्षेत्र ने महामारी के बावजूद काफी लचीलापन दर्शाया है।

उद्योग और सेवा क्षेत्र

- उद्योग और सेवा क्षेत्र, जो महामारी की वजह से पैदा आर्थिक अफरा-तफरी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, के 2020-21 के दौरान क्रमशः 10% और 9.2% तक संकुचित होने की संभावना है।
- औद्योगिक बहाली में गति पैदा हो रही है, लेकिन अभी भी वृद्धि वृहद् स्तर पर नहीं है।
- तिमाही औसत भविष्यवाणी दर्शाती है कि 2020-21 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के 1.3% तक संकुचित होने की संभावना है।
- चौथी तिमाही तक वृद्धि दर सकारात्मक मार्ग पर आ जाएगी जिसके लिए 0.5% वृद्धि दर का अनुमान है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, अन्य देशों में पुराने पड़ते बांध गंभीर खतरा: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

खबर में क्यों है?

- रिपोर्ट जिसका शीर्षक 'एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर: एन इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क' है और जिसे जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के कनाडा आधारित संस्थान ने संकलित किया है, को हाल में जारी किया गया।



रिपोर्ट की मुख्य खास बातें

- रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक, धरती पर अधिकांश लोग 1930 से 1970 के बीच में 20वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किये गये हजारों बांधों के प्रवाह की ओर निवास करेंगे। इनकी डिजाइन 50 से 100 वर्षों के बीच के जीवन के लिए है। ये अभी से डिजाइन जीवन पर अथवा पार प्रचालित हो रहे हैं।
- दुनिया के कुल बांधों के लगभग 55% केवल चार एशियाई देशों में हैं: चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया।
- वैश्विक रूप से पुराने पड़ रहे बांधों को सार्वजनिक सुरक्षा, बढ़ती हुई रखरखाव की लागत, जलाशय में गाद जमा होने और प्राकृतिक नदी पारिस्थितिकीय प्रणाली की बहाली को सुनिश्चित करने के लिए बंद करने की प्रवृत्ति है।

बंद करने के साथ मामला

- यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा क्योंकि यह मत्स्यन, कृषि, पर्यटन और पनबिजली को प्रभावित करता है।
- यह क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक इतिहास और विरासत को भी प्रभावित करते हैं।
- रिपोर्ट का यह सुझाव भी है कि प्रोटोकॉलों के ढांचे का विकास किया जाए जो बांध को हटाने को निर्देशित और तीव्र करेगा।

भारत और बांध

- भारत में 1,115 बड़े बांध हैं जो 2025 में मोटे तौर पर 50 वर्ष पुराने होंगे; 2050 में 4,250 देश में बड़े बांध 5 दशकों से भी ज्यादा पुराने होंगे और 2050 में 64 बड़े बांध 150 वर्षों से भी ज्यादा पुराने होंगे।
- रिपोर्ट का कहना है कि लगभग 35 लाख लोग खतरे में होंगे यदि केरल में भारत का मुल्लापेरियार बांध, जोकि 100 पहले निर्मित किया गया था।
- भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में, बांध काफी संरचनात्मक खामियां दिखलाते हैं और इसका प्रबंधन केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच में विवाद का विषय है।

भारत में बांध प्रबंधन के सुधार के लिए उठाए गए कदम

बांध सुरक्षा विधेयक, 2019

- लोकसभा ने इसे पूरे देश में सभी विशेषीकृत बांधों के लिए निगरानी, जांच, प्रचालन और रखरखाव के लिए पारित किया है।

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (ORIP)

- यह चुने हुए बांधों की सुरक्षा और प्रचलानात्मक प्रदर्शन के सुधार में मदद प्रदान करेगा।
- हाल में, कैबिनेट ने बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना के 2 और 3 चरण को स्वीकृति प्रदान की है।

DHARMA (बांध स्वास्थ्य एवं पुनर्वास निगरानी) सॉफ्टवेयर

- इसका प्रयोग भारत में सभी बड़े बांधों के प्रभावी रूप से संपत्ति के संग्रह और प्रबंधन और स्वास्थ्य आंकड़े के लिए किया जाता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- आपदा प्रबंधन

स्रोत- द हिंदू

वैश्विक मौसम जोखिम सूचकांक 2021

खबर में क्यों है?

- मौसम जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार, जिसे पर्यावरणीय थिंकटैंक जर्मन वाच ने जारी किया है, भारत ने 2019 में चरम मौसम की वजह से अधिकतम हानि झेली है।
- इस सूचकांक को **मौसम तदात्म्य शिखर सम्मेलन** के पूर्व जारी किया गया जो वर्चुअल रूप से 25 जनवरी को शुरू हुआ और इसकी मेजबानी नीदरलैंड्स द्वारा की जा रही है।



वैश्विक मौसम जोखिम सूचकांक के बारे में

- वैश्विक मौसम जोखिम सूचकांक (CRI) मौतों और आर्थिक हानियों में चरम मौसम घटनाओं के मात्रात्मक प्रभावों को विश्लेषित करता है।
- यह सूचकांक म्यूनिख रिस नेटकेटसर्विस से आंकड़ों पर आधारित है।

मौसम जोखिम सूचकांक 2021 के प्रमुख परिणाम:

- **मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मालावी, दक्षिण सूडान और नाइजर** सूचकांक के अनुसार 2019 में चरम मौसम से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले दस देशों में पांच अफ्रीकी देश हैं।

मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे पहले और दूसरे स्थान पर

- मालावी पांचवे स्थान पर, दक्षिण सूडान आठवें स्थान पर और नाइजर नौवें स्थान पर है।
- सूचकांक ने भारत को ऐसे देश के रूप में रैंक दी है जिसने जापान के बाद 2019 में मौसम परिवर्तन की वजह से दूसरा सबसे बड़ा मौद्रिक हानि झेली है।
- इसने यह भी दर्शाया कि 2019 में चरम मौसम घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित दस देशों में से आठ निम्न से निम्न मध्य आय वर्ग में शामिल हैं।
- इसमें से पांच सबसे कम विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं।

भारत और रिपोर्ट

- भारत 2019 में मौसम परिवर्तन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में सातवें स्थान पर है।
- इसने भारत को ऐसे देश के रूप में रैंक दी है जिसने जापान के बाद 2019 में मौसम परिवर्तन की वजह से दूसरा सबसे बड़ा मौद्रिक हानि झेली है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण, स्रोत- डाउन टू अर्थ

कोविड-19 प्रदर्शन रैंकिंग

खबर में क्यों है?

- लोवी संस्थान, जो एक ऑस्ट्रेलियाई थिंकटैंक है, ने हाल में कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया है।

कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक के बारे में

- यह सूचकांक छह अलग-अलग संसूचकों पर आधारित थी, जिसमें प्रति मिलियन लोगों पर मृत्यु के पुष्टि हुए मामले और परीक्षण के स्केल को शामिल किया गया है। यह देशों के सापेक्षिक प्रदर्शन को जानना चाहता है।
- इसने 98 देशों के सौवें मामले के बाद के 36 सप्ताहों तक का आकलन किया।

सूचकांक के प्रमुख खास बिंदु

- संस्थान ने पाया कि यद्यपि चीन में इसकी शुरुआत हुई, एशिया-प्रशांत क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा, जबकि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका शुरुआत से ही इसमें फंस गये।
- लेकिन यूरोप ने किसी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा सबसे ज्यादा सुधार को दर्शाया, लेकिन फिर वह दूसरे तंत्र का शिकार हो गया, जिसका कारण ज्यादा खुली सीमाएं होना है।
- **सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश:** महामारी से निपटने में न्यूजीलैंड और वियतनाम को सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश की श्रेणी में रखा गया।
- **भारत की रैंक 98 देशों में 86वीं रही, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान 94वां रहा।** श्रीलंका दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश रहा, जिसकी रैंकिंग 10 रही, जबकि मालदीव का स्थान 25वां, पाकिस्तान का स्थान 69वां, नेपाल का 70वां और बांग्लादेश का स्थान 84वां रहा।
- **ब्राजील सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर रहा।**
- चीन को परीक्षण पर सार्वजनिक उपलब्ध आंकड़ों की अनुपस्थिति की वजह से शामिल नहीं किया गया।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- स्वास्थ्य मामले (महत्वपूर्ण सूचकांक) + अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

स्रोत- द हिंदू

कला एवं संस्कृति

जालीकट्टू, सांड को वश में करने का खेल

खबर में क्यों है?

- जालीकट्टू एक बदनाम सांड को वश में करने का खेल है जिसे पोंगल के हिस्से के रूप दक्षिण भारत में मट्टू पोंगल पर विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह खेल पारंपरिक रूप से पोंगल त्योहार का हिस्सा रहा है। लेकिन, इस प्रथा का लंबे समय से पशु अधिकार समूहों द्वारा विरोध किया जाता रहा है और जानवरों के साथ क्रूरता के मामले और खेल के खतरनाक और खूनी पहलू पर न्यायालय ने चिंता व्यक्त की है।

जालीकट्टू का अर्थ क्या है?



- जालीकट्टू शब्द 'सल्ली कासू' से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ सिक्का है और 'कट्टू' का अर्थ पुरस्कार राशि के रूप में सांड के सींगों में बंधा हुआ पैकेज।
- 2017 में, तमिलनाडु में जबर्दस्त विरोध हुआ जिसमें मांग की गई कि केंद्र और तमिलनाडु सरकार जालीकट्टू को करवाने के लिए कानूनी कदम ले।
- इस पर प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि इस खेल के दौरान चोटों और मृत्यु से संबंधित कई मामले हुए थे, जिसमें भागीदार और इसमें शामिल पशु दोनों ही शामिल थे। पशु अधिकार संगठनों ने खेल पर रोक लगाने का आह्वान किया था।

इस खेल का क्या महत्व है?

- जालीकट्टू एक प्रथा है जिसमें पशुओं की पोंगल के त्योहार के दौरान विशेष रूप से तमिलनाडु में पूजा की जाती है।

नोट: इसी तरह से "कनुमा" भी मकर संक्रांति के तीसरे दिन संस्कृति के हिस्से के रूप में तेलंगाना में मनाया जाता है। इस त्योहार में पशुओं की पूजा की जाती है जिससे समाज के पोषण और विकास में पशुओं के महत्व को रेखांकित किया जाता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I: कला एवं संस्कृति

स्रोत- दि हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस

इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी की खोज

खबर में क्यों है?

- पुरातत्वविदों ने हाल में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा कला की खोज की है- यह इंडोनेशिया में कम से कम 45,5000 वर्ष पुरानी चित्रित की गई एक जंगली सुअर का जीवन आकार का चित्र है।
- इस पूर्व सबसे पुराना शैल कला दृश्य कम से कम 43,900 वर्ष पुराना था जिसमें मानव-जानवर संकर प्राणी को निरूपित किया गया था जो सुलावेसी वार्टी सुअरों और बौने दुधारू पशुओं का शिकार कर रहा था।



चित्रकारी के बारे में

- इस चित्रकारी की खोज दक्षिण सुलावेसी में की गई है जिसमें एक सांकेतिक वार्टी सुअर का निरूपण किया गया है। यह एक जंगली सुअर है जो इस इंडोनेशियाई द्वीप का स्थानिक जीव है।

चित्रकारी की आयु पहचानने के लिए प्रयोग की गई तकनीक

- शोधकर्ताओं ने एक यूरेनियम श्रृंखला डेटिंग तकनीक का प्रयोग किया जिससे खनिज संरचना का विश्लेषण किया जा सके जिसने चित्र के हिस्से को ढंक रखा था और निश्चित रूप से इसकी संरचना गुफा कला के बनने के बाद ही बनी होगी।
- खनिज संरचना कम से कम 45,500 वर्ष पुरानी है, यह बताता है कि यह कलाकृति अपने आप में इससे ज्यादा पुरानी हो सकती है।



महत्व

- यह चित्रकारी इस क्षेत्र में मानव बस्ती के प्रारंभिक साक्ष्य को उपलब्ध कराती है।

नोटः

- दक्षिण अफ्रीका में, हैशटैग जैसा इडल जिसे ऐसा विश्वास किया जाता है कि 73,000 वर्ष पूर्व बनाया गया था, सबसे पुरानी ज्ञात चित्रकारी है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021

खबर में क्यों है?

- हाल में राजेंद्र कुमार भंडारी और सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय विकास समिति (SEEDS) को सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया।



प्रमुख खास बातें

- राजेंद्र कुमार भंडारी को इस आपदा प्रबंधन में अपने कार्य के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है।
- सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय विकास समिति को आपदा के लिए सामुदायिक लचीलापन निर्मित करने में सराहनीय कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में चुना गया है।

सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के बारे में

- इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को की जाएगी, जोकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन है।

उद्देश्य

- इस पुरस्कार को भारत में व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा की मूल्यवान योगदान एवं स्वार्थरहित सेवा को मान्यता और सम्मान देने के लिए दिया जाता है।

पुरस्कार की राशि

- इस पुरस्कार में संस्था होने की स्थिति में रु. 51 लाख की नकद राशि और एक प्रमाणपत्र और व्यक्ति होने की स्थिति में रु. 5 लाख और एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

पात्रता

- सभी भारतीय नागरिक और संगठन, जिन्होंने आपदा प्रबंधन (बचाव, शमन अथवा पूर्व चेतावनी) के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है, इस पुरस्कार के पात्र हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- आपदा प्रबंधन

स्रोत- द हिंदू

भीमा कोरेगांव

खबर में क्यों है?

- हाल में, मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने भारतीय सरकार से 2018 के भीमा कोरेगांव के लिए जेल में रह रहे कार्यकर्ताओं को रिहा करने का आह्वान किया। कम से कम होने जमानत दे दी जाए।

पृष्ठभूमि

- भीमा कोरेगांव का मामला 1 जनवरी, 2018 को हुआ था, जिसके द्वारा भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं वर्षगांठ मनाई गई थी।
- इस समारोह का आयोजन ब्रिटिश सेना की विजय को मनाने के लिए किया गया था, जिसमें **बड़ी संख्या में महार शामिल** थे। यह युद्ध पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना के खिलाफ था।
- कई मानवाधिकार कार्यकर्ता, जिसमें सुधा भारद्वाज, वारावर राव और गौतम नवलखा शामिल हैं, जांच के दौरान गिरफ्तार किये गये थे।

भीमा कोरेगांव के बारे में

- यह महाराष्ट्र के पूणे जिले का एक छोटा गांव है, भीमा कोरेगांव, जो मराठा इतिहास के एक महत्वपूर्ण चरण से संबंधित है।
- 1 जनवरी, 1818 को एक दलित वर्चस्व वाली सेना ने पेशवा की सेना को हरा दिया था, जिसका नेतृत्व कोरेगांव में पेशवा बाजीराव द्वितीय कर रहे थे।



- इस युद्ध ने दलितों के लिए ऐतिहासिक ऊंचाई हासिल कर ली, जो इसे पेशवाओं द्वारा की गई ज्यादतियों के खिलाफ इस विजय को महारों की विजय मानते हैं।
- एक स्तम्भ जिसे **विजय स्तम्भ (विक्ट्री पिलर)** कहते हैं, को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध में उनके लिये लड़ने वालों की याद में स्थापित करवाया था।
- इसी स्तम्भ पर आकर **हजारों दलित 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अपना सम्मान प्रकट करते हैं।**

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I-इतिहास, स्रोत- द हिंदू

पथारूघाट विद्रोह

खबर में क्यों है?

- हाल में पथारूघाट में सरकार और स्थानीय लोगों ने घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की (कृषक शहीद दिवस)। यह असम के दारांग जिले में एक छोटा गांव है।



पथारूघाट विद्रोह क्यों हुआ?

- 1826 में ब्रिटिश द्वारा असम पर कब्जे के बाद, इस राज्य की वृहद भूमि का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। इस तरह के सर्वेक्षण के आधार पर, ब्रिटिश सरकार ने भूमि कर लगाने आरंभ किये, जिससे किसानों के मध्य असंतोष फैला।
- 1893 में, ब्रिटिश सरकार ने कृषीय भूमिकर को 70-80 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया।
- इसकी वजह से किसानों ने विरोध करना आरंभ किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस तरह के विरोधों को राजद्रोह की जन्मभूमि के रूप में देखना आरंभ किया।
- इसमें लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद गोलियां चलाई गईं जिससे वहां उपस्थित कई किसानों की मृत्यु हो गई।
- आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, जिसका दारांग जिले के गजेट में 1905 में उल्लेख किया गया है और जिसका संपादन बी. सी. एलेन द्वारा किया गया है, ने पथारूघाट घटना के दौरान कुल 15 मौतों और 37 घायल लोगों का जिक्र किया।
- लेकिन, गैर आधिकारिक स्रोतों के अनुसार यह संख्या काफी ज्यादा थी।

घटना का महत्व

- असम के वृहद समुदाय के लिए, पथारूघाट का स्थान सरायघाट के युद्ध के बाद आता है, जब अहोम लोगों ने मुगलों को 1671 में हरा दिया था।
- यह असमी समुदाय के लिए काफी प्रेरणास्पद घटना है, जो उनके लिए राष्ट्रीय जागृति थी।
- यह एक शांतिपूर्ण विरोध था और नागरिक अवज्ञा आंदोलन का अग्रदूत था, जिसे बाद में महात्मा गांधी ने प्रचारित किया।

नोट:

- इसे असम का जालियांवाला बाग भी कहा जाता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- इतिहास

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस